



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 116]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, मई 6, 2010/वैशाख 16, 1932

No. 116]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 6, 2010/VAISAKHA 16, 1932

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मई, 2010

अंतिम जांच परिणाम

विषय : चीन जन. गण. के मूल के या वहां से निर्यातित डाइथाइल थियो फास्फोरिल क्लोराइड (डी ई टी पी सी) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच ।

फा. सं. 14/18/2008-डीजीएडी.—यतः निर्दिष्ट प्राधिकारी ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे एतदपश्चात् अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतदपश्चात् नियमावली कहा गया है), को ध्यान में रखते हुए :

1. यतः मै. कैमिनोवा इंडिया लि. (जिसे एतदपश्चात् आवेदक कहा गया है) ने उक्त अधिनियम और नियमावली के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतदपश्चात् प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष एक याचिका दायर की है जिसमें चीन जन. गण. (जिसे एतदपश्चात् संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित डाइथाइल थियो फास्फोरिल क्लोराइड (डी ई टी पी सी) के पाटन का आरोप लगाया गया है और संबद्ध वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए जांच की शुरुआत करने का अनुरोध किया गया है ।

2. और यतः प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर दिनांक 17 नवम्बर, 2008 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया तथा जिसके तहत नियमावली के उप-नियम 5(5) के अनुसार संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू की गई ताकि कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और उसके प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी ।

3. और यतः प्राधिकारी ने इस अधिनियम और नियमावली को ध्यान में रखते हुए जांच की थी और दिनांक 25 मई, 2009 के समसंख्यक प्रारंभिक जांच परिणामों द्वारा संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के उपशीर्ष 29.30 के अंतर्गत आने वाली संबद्ध वस्तु के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी और संबद्ध वस्तुओं पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क दिनांक 22.6.2009 की सीमाशुल्क अधिसूचना सं. 73/2009 द्वारा लगाया गया था ।

क. मामले की पृष्ठभूमि:

4. इस मामले की पृष्ठभूमि निम्नानुसार है:

i) निर्दिष्ट प्राधिकारी को नियमों के अंतर्गत घरेलू उद्योग हेतु तथा उसकी ओर से मै0 एक्सेल इंडस्ट्रीज लि0, मुम्बई के समर्थन से मै0 केमिनोवा इंडिया लि0, मुम्बई से एक लिखित आवेदन प्राप्त हुआ जिसमें चीन जन गण के मूल के या वहाँ से निर्यातित डाई-इथाइल थियो फॉस्फोरिल क्लोराइड (डी ई टी पी सी) के पाटन का आरोप लगाया गया था ।

ii) घरेलू उद्योग की ओर से आवेदक द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर प्राधिकारी ने कथित आयातों की उपस्थिति, मात्रा एवं प्रभाव की जाँच करने तथा पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग की क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, पाटनरोधी नियमों के उप नियम 6 (1) के अनुसार चीन जन गण के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित डाई-इथाइल थियो फॉस्फोरिक क्लोराइड के आयातों की पाटनरोधी जाँच शुरू करते हुए दिनांक 17 नवम्बर 2008 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की जो भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित हुई ।

iii) निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जारी की गई जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना को मै. मेघमणि आर्गेनिक्स लि., अहमदाबाद द्वारा विशेष सिविल याचिका सं. 2201/2009 के तहत माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी । इस मामले को गुजरात उच्च न्यायालय की माननीय डिविजन बेंच द्वारा 8.4.2009 को सुना गया था और इस निर्देश के साथ निपटाया गया था कि याचिकाकर्ता द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र के संबंध में की गई प्रारंभिक आपत्ति पर विचार किया जाएगा और कानून के अनुसार इस संबंध में याचिकाकर्ताओं को सुनने के बाद निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा 4 सप्ताह की अवधि के भीतर अर्थात् 7.5.2009 को अथवा उससे पहले तत्संबंधी निर्णय लिया जाएगा ।

iv) गुजरात उच्च न्यायालय की माननीय डिवीजन बेंच के दिनांक 8.4.2009 के निर्देशों के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा 24.4.2009 को सुनवाई की गई थी मै. मेघमणि आर्गेनिक्स लि. को अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ सुनवाई हेतु आमंत्रित किया गया था ।

v) मै0 मेघमणि आर्गेनिक्स लि0, घरेलू उद्योग तथा निर्यातकों के प्रतिनिधियों ने सुनवाई में भाग लिया था और उन्हें निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष अपने तर्क प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था । हितबद्ध पक्षकारों तथा उनके प्रतिनिधियों की सुनवाई के बाद निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 28.4.2009 तक लिखित अभ्यावेदन तथा दिनांक 1.5.09 तक प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था ।

vi) मै. मेघमणि आर्गेनिक्स लि., अहमदाबाद और अन्य हितबद्ध पक्षकारों की ओर से किए गए अनुरोधों की विस्तृत जांच और उन पर ध्यानपूर्वक विचार करने और संगत नियमावली तथा निर्णयों पर विश्वास करके निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 6 मई, 2009 के एक आदेश द्वारा एक स्पीकिंग ऑर्डर जारी किया ।

vii) निर्दिष्ट प्राधिकारी ने इस अधिनियम और पाटनरोधी नियमावली को ध्यान में रखते हुए संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी । प्रारंभिक जांच परिणाम दिनांक 25 मई, 2009 की अधिसूचना सं. 14/18/2008-डीजीएडी द्वारा प्रकाशित किए गए थे और दिनांक 22 जून, 2009 की सी.शु. अधिसूचना सं. 73/2009-सी.शु. द्वारा संबद्ध वस्तुओं पर अनंतिम शुल्क लगाया गया था ।

viii) मै. मेघमणि आर्गेनिक्स लि., अहमदाबाद ने गुजरात के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष 2009 की विशेष सिविल याचिका सं. 6881 के माध्यम से पुनः एक याचिका दायर की जिसमें दिनांक 17.11.2008 की जांच शुरुआत संबंधी सूचना और गुजरात उच्च न्यायालय के माननीय डिवीजन बेंच के 8.4.2009 के पूर्ववर्ती आदेशों के अनुपालन में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए दिनांक 6.5.2009 के स्पीकिंग ऑर्डर, 25.5.2009 के प्रारंभिक जांच परिणाम और दिनांक 22.6.2009 की सी.शु. अधिसूचना सं. 73/2009 को इन आधारों पर चुनौती दी गई कि जांच शुरुआत संबंधी सूचना क्षेत्राधिकार के बिना है और संपूर्ण जांच में अत्यधिक गोपनीयता बरती गई है ।

ix) गुजरात के उच्च न्यायालय की माननीय डिवीजन बेंच ने दिनांक 9-10-2009 के आदेश द्वारा गोपनीयता के मुद्दे पर निर्दिष्ट प्राधिकारी के प्रारंभिक जांच परिणाम को अस्वीकृत कर दिया । माननीय डिवीजन बेंच ने निर्दिष्ट प्राधिकारी को जांच परिणामों के उन सभी आवश्यक व्यौरों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जिन्हें प्रारंभिक जांच परिणामों को

रिकॉर्ड करते समय रिक्त रखा गया है ताकि याचिकाकर्ता इस संबंध में आपत्तियां उठा सकें और अंतिम जांच परिणाम रिकॉर्ड करते समय उन आपत्तियों और अनुरोधों पर विचार किया जाए। निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात पर भी विचार करने का निर्देश दिया गया था कि क्या एक्सल इंडस्ट्रीज लि. (पूर्ववर्ती प्रतिवादी सं. 4) और उनकी संबद्ध कंपनी ने चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तु का कोई आयात किया है। इसके अलावा, निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यह प्रक्रिया शुरू किए जाने और अंतिम जांच परिणाम घोषित करने तक याचिकाकर्ता को चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तु के आयात पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क की लेवी से छूट प्रदान की जाए। इस छूट को आदेश की तारीख के एक सप्ताह के भीतर प्राधिकारी के समक्ष इस आशय की एक वचनबद्धता प्रस्तुत करने के अधीन रखा गया जिसमें यह कहा गया हो कि यदि वे संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क देने के लिए पात्र माने जाते हैं तो इस मामले में अंतिम जांच परिणाम रिकॉर्ड करते समय वे अपील करने के अपने अधिकार और किसी सक्षम न्यायालय और न्यायाधिकरण से ऐसे शुल्क के विरुद्ध स्टे प्राप्त करने के अधीन ऐसे पाटनरोधी शुल्क का भुगतान करेंगे।

x) निर्दिष्ट प्राधिकारी ने 2010 की विशेष अनुमति याचिका सं. 887 (और पृथक रूप से 2009 की स्पेशल लीव पेटिशन सं. 34374 द्वारा कैमिनोवा इंडस्ट्रीज लि. और 2009 की विशेष अनुमति याचिका सं. 35243 द्वारा एक्सल इंडस्ट्रीज लि.) द्वारा भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष गुजरात उच्च न्यायालय की माननीय डिविजन बेंच के 9-10-2009 के विवादित आदेशों को चुनौती दी। पक्षकारों को सुनने के बाद माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार आदेश दिया :

"लीव प्रदत्त".

सुनवाई तेज की जाए।

अपीलों का निपटान होने तक विवादित आदेश पर स्टे रहेगा।

26 अगस्त, 2010 को अपील प्रस्तुत करें

xi) मै. सिरीज क्रॉप साइसेंस लि. ने 2010 की रिट याचिका सं. 190 के द्वारा, मै. सेबोरो आर्गोनिक्स गुजरात लि. ने 2010 की रिट याचिका सं. 173 के द्वारा मै. रोटेम इंडिया लि. ने 2010 की रिट याचिका सं. 191 के द्वारा और मै. पी आई इंडस्ट्रीज लि. ने 2010 की रिट याचिका सं. 183 के द्वारा, मै. जीएसपी क्रॉप साइसेंस प्रा. लि. ने 2010 की रिट याचिका सं. 736 के द्वारा, मै. भागीरथा कैमिकल्स इंडस्ट्रीज लि. ने 2010 की रिट याचिका सं. 737 के द्वारा और मै. गर्दा कैमिकल्स लि. ने 2010 की रिट याचिका सं. 738 के द्वारा रिट याचिकाएं दायर की हैं जिनमें 17.11.2008 की जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना गुजरात उच्च न्यायालय की माननीय डिविजन बेंच के दिनांक 8.4.2009 के आदेशों के अनुपालन में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा 6.5.2009 को जारी किए गए आदेश 25.5.2009 के प्रारंभिक जांच परिणामों और दिनांक 22.6.2009 की सी.शु. अधिसूचना सं. 73/2009 को इन आधारों पर दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है कि जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना क्षेत्राधिकार के बिना है और संपूर्ण जांच अत्यधिक गोपनीयता से ग्रस्त है।

xii) पक्षकारों को सुनने के बाद माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी किया और मामले की सुनवाई 24.5.2009 को निर्धारित की। चूंकि रिट याचिकाकर्ताओं ने अंतरिम स्टे ऑर्डर के लिए भी आवेदन प्रस्तुत किया था; परंतु माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा कोई अंतरिम स्टे ऑर्डर नहीं दिया गया।

ख. प्रक्रिया

5. इस कार्यवाही में निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

- i. उपर्युक्त नियम 5 के उप-नियम (5) के अनुसार प्राधिकारी ने जांच शुरू करने से पहले भारत में स्थित संबद्ध देश के दूतावास को याचिकाकर्ता से पाटनरोधी आवेदन प्राप्त होने की सूचना दी थी;
- ii. घरेलू उद्योग की ओर से आवेदक द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर प्राधिकारी ने कथित आयातों की उपस्थिति, मात्रा एवं प्रभाव की जाँच करने तथा पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग की क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, पाटनरोधी नियमों के उप नियम 6 (1) के अनुसार चीन जन गण के मूल के अथवा वहां से निर्यातित डाई-इथाइल थियो फॉस्फोरिक क्लोराइड के आयातों की पाटनरोधी जाँच शुरू करते हुए दिनांक 17 नवम्बर 2008 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की जो भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित हुई।
- iii. प्राधिकारी ने दिनांक 17.11.2008 की जाँच शुरूआत अधिसूचना की प्रति आवेदक के पास उपलब्ध पतों के अनुसार चीन जन गण के ज्ञात निर्यातकों, उत्पादकों, संबंधित देश के दूतावास, प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग को अग्रेषित की थी और उनसे जांच शुरूआत अधिसूचना के 40 दिनों के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया था।
- iv. उपर्युक्त नियम 6 के उप-नियम (3) के अनुसार प्राधिकारी ने आवेदन का अगोपनीय रूपान्तर सभी ज्ञात निर्यातकों और भारत में स्थित संबद्ध देश के दूतावास को उपलब्ध कराया था।
- v. नई दिल्ली स्थित संबद्ध देश के दूतावास को भी जांच शुरूआत के संबंध में सूचना दी गई थी और दूतावास को उनके देश के निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित समय के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए सलाह देने का अनुरोध किया गया था। ज्ञात निर्यातकों के नाम एवं पतों के साथ उन्हें भेजे गए पत्र एवं प्रश्नावली की प्रति भी दूतावास को भेजी गई थी।
- vi. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमों के नियम 6 (4) के अनुसार संगत सूचना प्राप्त करने के लिए संबद्ध देश के ज्ञात निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजी थीं।

- vii. उपर्युक्त अधिसूचना की प्रतिक्रियास्वरूप निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों/संघों ने उत्तर प्रस्तुत किया है:-

क्र. सं.	कंपनी का नाम
1.	यांग्सिन चेन्शियन केमिकल इंडस्ट्री कं० लि०
2.	लियनयुंगोंग लिबेन एग्रो-केमिकल कं० लि०
3.	जिंग्टाई पेस्टीसाइड कं० लि०
4.	झेजियांग जिनांग केमिकल कं० लि०
5.	चाइना क्रॉप प्रोटेक्शन इंडस्ट्री एसोसिएशन

- viii. पाटनरोधी नियमों के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना प्राप्त करने के लिए भारत में संबद्ध वस्तु के ज्ञात आयातकों और/या प्रयोक्ताओं को आयातक प्रश्नावली भेजी गई थी।

- ix. निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं से सूचना प्राप्त हुई है:-

क्र. सं.	कंपनी का नाम
1.	मेघमणि ऑर्गेनिक्स लि०
2.	भागीरथ केमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज लि०
3.	गर्दा केमिकल्स लि०
4.	पी आई इंडस्ट्रीज
5.	एस आई आर आई एस क्रॉप साइंस लि०

- x. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय अंश को प्राधिकारी द्वारा रखी जाने वाली एक सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध रखा और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण किए जाने के लिए खुला रखा था।
- xi. वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) से पिछले तीन वर्षों और जांच अवधि के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयातों के ब्यौरे की व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया था। डी जी सी आई एंड एस से सूचना प्राप्त हुई है और आवश्यक समझी गई सीमा तक उसका उपयोग किया गया है।

- xii. आवेदकों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर यह पता लगाने के लिए कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग की क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा, सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जी ए ए पी) के आधार पर उत्पादन की लागत और भारत में संबद्ध वस्तुएं बनाने और उनकी बिक्री करने की लागत का परिकलन किया गया था ।
- xiii. जांच में 1 अप्रैल, 2007 से 31 मार्च, 2008 (पी ओ आई) तक की अवधि शामिल थी । क्षति विश्लेषण के संदर्भ में प्रवृत्तियों की जांच में अप्रैल 2004- मार्च 2005, अप्रैल 2005-मार्च 2006, अप्रैल, 2006 - मार्च, 2007 और जांच अवधि की समाप्ति तक की अवधि शामिल थी ।
- xiv. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(6) के अनुसार प्राधिकारी ने सभी ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को 7 अक्टूबर, 2009 को हुई सार्वजनिक सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचारों को प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया । सार्वजनिक सुनवाई में अपने विचारों को प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से मौखिक रूप से व्यक्त विचारों को लिखित रूप में व्यक्त करने का अनुरोध किया गया । हितबद्ध पक्षकारों को लिखित अनुरोध और प्रत्युत्तर क्रमशः 15-10-2009 और 21.10.2009 को प्रस्तुत करने की सलाह दी गई ।
- xv. प्रारंभिक जांच परिणामों की अधिसूचना से पहले हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों जिन्हें अधिसूचित प्रारंभिक जांच परिणामों में प्रकाशित कर दिया गया है, को संक्षिप्तता के कारण उनमें दोहराया नहीं गया है । तथापि, प्रारंभिक जांच परिणामों के उत्तर में किए गए अनुरोधों और सार्वजनिक सुनवाई के बाद ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त लिखित अनुरोधों/प्रत्युत्तरों में दिए गए तर्कों तथा विभिन्न न्यायालयों में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर जहां कहीं भी संगत हो इन जांच परिणामों में विचार किया गया है ।
- xvi. घरेलू उद्योग और चीन के सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना और आंकड़ों के संबंध में आवश्यक समझी गई सीमा तक सत्यापन किया गया था ।
- xvii. पाटनरोधी नियमावली के नियम 16 के अनुसार प्राधिकारी द्वारा विचारित अनिवार्य तथ्यों को दिनांक 13 अप्रैल, 2010 के प्रकटन विवरण द्वारा सभी हितबद्ध पक्षकारों के समक्ष प्रकट किया गया था । प्रकटन विवरण के संबंध में प्राप्त हुई टिप्पणियों की इन जांच परिणामों में विधिवत ढंग से जांच की गई है और उन पर संगत ढंग से विचार किया गया है ।

- xviii. विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा पहले व्यक्त किए गए विचारों पर प्रारंभिक जांच परिणामों और प्रकटन विवरण पर भी विचार किया गया था। उन विचारों जिन पर प्रारंभिक जांच परिणामों में और प्रकटन विवरण में पहले विचार नहीं किया गया है और जिन्हें प्रकटन विवरण के उत्तर में उठाया गया है, की भी जांच की गई है और नियमों के अनुसार उनकी संगतता की सीमा तक और इस मामले से उनके संबंध के मद्देनजर इन जांच परिणामों के संगत पैराग्राफों में उन पर विचार किया गया है।
- xix. ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की गोपनीयता के दावे के पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। इससे संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने गोपनीयता के दावों को जहां आवश्यक हो स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना गया है और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसका प्रकटन नहीं किया गया है। जहां कहीं भी संभव हो, गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
- xx. जहां कहीं किसी हितबद्ध पक्षकार ने सूचना देने से मना किया है या अन्यथा वर्तमान जांच की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना प्रदान नहीं की है या इस जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर इन जांच परिणामों को रिकॉर्ड किया है।
- xxi. इस अधिसूचना में *** हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई और प्राधिकारी द्वारा नियमों के अंतर्गत विचार की गई सूचना का प्रतीक है।
- xxii. जांच अवधि के लिए स्वीकार की गई विनिमय दर 40.75 रु. = 1 अम.डॉ. है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और घरेलू समान वस्तु

ग.1 घरेलू उद्योग के विचार

6. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किये गए हैं:

- वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद डाई-इथाइल थियो फॉस्फोरिल क्लोराइड (डी ई टी पी सी) है जो दुर्गंध युक्त, रंगहीन अथवा हल्का पीला/ऐम्बर कार्बनिक द्रव है। इसका घनत्व 1.196 ग्राम/से.मी.³ होता है। डाई-इथाइल थियो फॉस्फोरिल क्लोराइड पानी में अघुलनशील परन्तु कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होता है। यह एक अत्यधिक जहरीला रसायन है जो आँखों एवं फेफड़ों को नुकसान पहुँचा सकता है। इसका प्रयोग कीटनाशकों हेतु मध्यवर्ती के रूप में होता है। बाजार में इसे ओ, ओ डाई-इथाइल फॉस्फोरोक्लोरिडोथियोएट या डी ई टी पी.सी के नाम से भी

जाना जाता है। डाई-इथाइल थियो फॉस्फोरिल क्लोराइड का रासायनिक सूत्र $C_4H_{10}ClO_2PS$ है। यह कीटनाशकों के उत्पादन में प्रयोग होने वाला मध्यवर्ती है।

ii) नीचे दिए गए अनुसार अलग-अलग समानार्थक नामों एवं सीमाशुल्क वर्गीकरणों के अंतर्गत डाई-इथाइल थियो फॉस्फोरिल क्लोराइड का आयात किया जा रहा है:-

- क्लोर यूरो डे डाई-इथाइलथियोफॉस्फोराइल (डॉट फ्रेंच)
- ओ, ओ -डाई इथाइल थियोनोफॉस्फोरिक क्लोराइड
- क्लोरयूरो डे डाईटिलथियोफॉस्फोरिलो (डॉट स्पेनिश)
- डाइथोऑक्सीथियोफॉस्फोरिल क्लोराइड
- डाई-इथाइल क्लोरोथियोफॉस्फेट
- डाई-इथाइल फॉस्फोरोक्लोराइडोथियोएट
- इथाइल फॉस्फोरोक्लोराइडोथियोएट ((ई टी ओ) 2 CLPS)
- ओ, ओ डाई-इथाइल फॉस्फोरोथियोनोक्लोरिडेट
- फॉस्फोरोक्लोरिडोथियोइक एसिड, ओ, ओ डाई-इथाइल ईस्टर

iii) चूँकि ये विचाराधीन उत्पाद के सामान्य समानार्थी हैं, अतः याचिकाकर्ता ने इन सभी समानार्थियों को विचाराधीन उत्पाद के अंतर्गत शामिल किए जाने का अनुरोध किया है।

iv) विचाराधीन उत्पाद सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 29 के अंतर्गत वर्गीकृत है। परन्तु उपलब्ध सूचना के अनुसार कई सीमाशुल्क वर्गीकरणों के अंतर्गत विचाराधीन उत्पाद का आयात किया जा रहा है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

		आयात मी.ट. में			
क्र.सं.	आईटीसी-कोड	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
1	28121090	-	-	-	1,160
2	28129000	180	-	-	20
3	28273990	320	210	160	-
4	29051100	-	120	160	380
5	29091900	40	-	-	-
6	29095090	20	-	-	-
7	29190090	460	40	240	-
8	29199010	-	-	80	560
9	29199090	-	-	-	600
10	29201000	7,523	6,989	3,220	-
11	29201010	-	-	400	-
12	29201020	-	-	920	-
13	29201100	-	-	80	100
14	29201910	-	-	-	2,078

15	29201920	-	-	160	220
16	29201990	-	-	40	2,175
17	29209010	-	140	40	-
18	29209020	-	-	440	596
19	29209030	-	-	240	760
20	29209090	480	-	-	-
21	29209099	-	-	1,990	3,553
22	29241900	-	-	138	254
23	29310090	270	100	10	140
24	29420011	700	360	-	20
25	29420090	300	95	440	-
26	38089010	178	-	-	-

v) चूँकि विचाराधीन उत्पाद का आयात अध्याय 28, 29, 30 के अंतर्गत किया गया है अतः जाँच में इन तीनों अध्यायों में विचाराधीन उत्पाद के आयात को शामिल किया गया है। तथापि, सीमाशुल्क वर्गीकरण सांकेतिक मात्र है और वर्तमान जाँच के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।

ग.2 आयातक/प्रयोदना, निर्यातक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार:

7. किसी भी प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकार ने इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं जताई है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को उनके द्वारा संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु के समान वस्तु माना जाता रहा है।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

8. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) में समान वस्तु को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

"समान वस्तु" का अर्थ एक ऐसी वस्तु है जो भारत में पाटन के लिए जांच के अधीन वस्तु के समान हो या प्रत्येक दृष्टि से उसके जैसी हो अथवा ऐसी वस्तु के अभाव में कोई अन्य ऐसी वस्तु जो यद्यपि प्रत्येक दृष्टि से समान न हो तब भी उसमें जांचाधीन वस्तु से अत्यधिक मिलती-जुलती विशेषताएं हो;

9. भारतीय बाजार में निर्यातकों द्वारा बेचे जा रहे उत्पाद और घरेलू उद्योग द्वारा बेचे जा रहे उत्पाद में संभावित अंतर के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित तथा संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। भौतिक एवं रसायनिक गुणधर्मों, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्य एवं प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत, वितरण एवं विपणन तथा वस्तु के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं के रूप में भारतीय उद्योग द्वारा उत्पादित

तथा संबद्ध देश से आयातित विचाराधीन उत्पाद तुलनीय हैं। दोनों तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। प्रयोक्ताओं द्वारा दोनों का प्रयोग एक-दूसरे के स्थान पर किया जा रहा है। किसी भी विरोधकर्ता हितबद्ध पक्षकार ने इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं की है। पाटनरोधी नियमों के अनुसार संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु को याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु के समान वस्तु माना जा रहा है।

घ. विभिन्न न्यायालयों के समक्ष मुकदमे

घ.1 गुजरात उच्च न्यायालय, अहमदाबाद की माननीय पीठ के समक्ष विशेष सिविल याचिका सं. 2201/2009

10. मै० मेघमणि ऑर्गेनिक्स लि० द्वारा विशेष सिविल आवेदन सं० 2201/2009 के जरिए माननीय गुजरात उच्च न्यायालय में जाँच शुरुआत संबंधी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। दिनांक 8.4.09 को माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के डिवीजन बेंच द्वारा मामले की सुनवाई की गई थी और निम्नलिखित आदेश के साथ मामले का निपटारा किया गया था:-

" विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्देश पर श्री हरिन पी. रावल, भारत के सुविज्ञ सहायक महान्यायवादी ने उल्लेख किया है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी के क्षेत्राधिकार के संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा की गई प्रारंभिक आपत्ति पर कानून के अनुसार याचिकाकर्ता की सुनवाई के पश्चात् निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा चार सप्ताह की अवधि के भीतर अर्थात् 7.5.09 तक या उससे पूर्व कार्रवाई की जाएगी एवं निर्णय दिया जाएगा।

11. गुजरात उच्च न्यायालय की माननीय डिवीजन बेंच के दिनांक 8.4.2009 के निर्देशों के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा 24.4.2009 को सुनवाई की गई थी मै. मेघमणि ऑर्गेनिक्स लि. को अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ सुनवाई हेतु आमंत्रित किया गया था।

12. मै० मेघमणि ऑर्गेनिक्स लि०, घरेलू उद्योग तथा निर्यातकों के प्रतिनिधियों ने सुनवाई में भाग लिया था। मै० मेघमणि ऑर्गेनिक्स लि०, घरेलू उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ अन्य हितबद्ध पक्षकारों को निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष अपने तर्क प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था। हितबद्ध पक्षकारों तथा उनके प्रतिनिधियों की सुनवाई के बाद निर्दिष्ट प्राधिकारी ने दिनांक 28.4.2009 तक लिखित अभ्यावेदन तथा दिनांक 1.5.09 तक प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।

13. निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा सुनवाई के अनुसरण में विभिन्न पक्षकारों द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों एवं प्रत्युत्तरों का सार निम्नानुसार है:-

क) मै0 मेमब्रणि ऑर्गेनिक्स लि0 तथा चीन जन गण के निर्यातकों द्वारा

- (i) धारा 5 (1) में "घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से" आवेदन प्रस्तुत किए जाने का निर्धारण किया गया है। धारा 5 (1) में उल्लिखित शब्द "घरेलू उद्योग" की परिभाषा धारा 2 (ख) में दी गई है। आवेदन मै0 केमिनोवा द्वारा प्रस्तुत किया गया है जो नियम 2 (ख) में यथापरिभाषित "घरेलू उद्योग" के लिए पात्र नहीं हैं। घरेलू उत्पादन में आवेदक का हिस्सा केवल 28 प्रतिशत है जिसे घरेलू उत्पादन का बड़ा हिस्सा नहीं माना जा सकता है।
- (ii) जाँच शुरूआत के पूर्व आवेदक द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी को सूचित किया गया था कि भारत में संबद्ध वस्तु के तीन उत्पादक हैं। जाँच शुरूआत के समय प्राधिकारी ने इस तथ्य के बावजूद कि घरेलू उत्पादन में आवेदक का हिस्सा केवल 28 प्रतिशत है, भारत में कुल उत्पादन का निर्धारण करने के लिए मतगणना का सहारा नहीं लिया जैसाकि अन्य मामलों में किया गया है। तीसरे उत्पादक के बारे में किसी सूचना के बिना निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यह जाँच नहीं की जा सकती थी कि आवेदन घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किया गया है क्योंकि वे कुल घरेलू उत्पादन के "बड़े हिस्से" के संबंध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते थे।
- (iii) नियम 2 (ख) में वे उत्पादक शामिल नहीं हैं जिनके विचाराधीन उत्पाद (तथाकथित पाटित वस्तु) के निर्यातकों के साथ संबंध है। आवेदन के अगोपनीय रूपांतर में मै0 केमिनोवा के डेनमार्क स्थित संबंधित कंपनी से संबंध को छिपाया गया है। ऐसी सूचना के अभाव में निर्दिष्ट प्राधिकारी यह निर्णय नहीं ले सकते कि नियम 2 (ख) के अनुसार ऐसे उत्पादकों को शामिल किया जाए या नहीं।
- (iv) जाँच शुरूआत संबंधी अधिसूचना में किसी भी तरीके से यह उल्लिखित नहीं है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने अपने विवेकाधिकार का प्रयोग किया और उसमें भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात कर रही डेनमार्क की कंपनी के साथ संबंध के बावजूद आवेदक को पात्र घरेलू उद्योग मानने की अनुमति देने के कारण भी उल्लिखित नहीं हैं।
- (v) प्राधिकारी ने भारत में संबद्ध वस्तु के तीन उत्पादक होने की सूचना उपलब्ध होने के बाद भी मै0 सबेरो ऑर्गेनिक्स गुजरात लि0 के उत्पादन को नजरअंदाज किया।
- (vi) निर्धारित कानून के अनुसार शुरूआत से पूर्व का निर्धारण करते समय आबद्ध खपत को शामिल नहीं किया जा सकता है जैसाकि कानून के अनुसार अधिदेशित है। मै0 केमिनोवा ने आवेदन के अगोपनीय रूपांतर में वस्तु की किसी आबद्ध खपत के ब्यौरे नहीं दिए और इसके अलावा जाँच शुरूआत अधिसूचना में उसके संबंध में कोई निर्धारण नहीं किया गया था।

- (vii) इस चरण में मै0 एक्सेल, जो जाँच शुरूआत के समय आवेदक नहीं था, को सूचना प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है क्योंकि इससे हितबद्ध पक्षकारों के हित प्रतिकूल रूप से प्रभावित होंगे ।
- (viii) निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा वर्तमान में पाटनरोधी जाँच को रद्द किया जा सकता है क्योंकि यह प्राधिकारी के क्षेत्राधिकार से बाहर है और सांविधिक नियम के विरुद्ध है ।
- (ix) शुल्क को भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने का कोई मामला नहीं बनता है क्योंकि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 क (3) की किसी शर्त को पूरा नहीं किया गया है ।
- (x) सार्वजनिक फाइल की सूची की प्रति, आवेदनों की प्रतियाँ आदि उपलब्ध कराई जानी चाहिए ।

ख) घरेलू उद्योग

- (i) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों, जो त्रुटिपूर्ण और अनुचित कानूनी सोच पर आधारित हैं, में कोई औचित्य नहीं है । आवेदन में नियम 2 (ख) के साथ पठित नियम 5 (3) के अंतर्गत दी गई अपेक्षा को पूरा किया गया है । अतः आवेदक पाटनरोधी नियमावली के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग का हिस्सा है ।
- (ii) घरेलू उद्योग की स्थिति और दायरा दो अलग-अलग अपेक्षाएँ हैं । क्षेत्राधिकार के नाम पर मै0 मेघमणि ने "घरेलू उद्योग के दायरे" का मुद्दा उठाया है और इस बात का उल्लेख नहीं किया है कि इस मामले में अब तक कैसे स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है । अतः स्थिति संबंधी अपेक्षा के संबंध में मै0 मेघमणि का तर्क निराधार है ।
- (iii) पाटनरोधी नियमावली के अनुसार मै0 कैमिनोवा, जिसका उत्पादन कुल उत्पादन का अधिकांश हिस्सा है, घरेलू उद्योग होने के पात्र हैं । हितबद्ध पक्षकार बार-बार "प्रमुख हिस्सा" दोहरा रहे हैं जबकि अपेक्षा "एक प्रमुख हिस्से" की है । अतः "एक" को छोड़ा जाना भूलवश नहीं है बल्कि इन हितबद्ध पक्षकारों द्वारा जानबूझ कर किया गया है ।
- (iv) जाँच शुरूआत से पूर्व मत प्राप्त करने के लिए कोई पूर्वनिर्धारित कानूनी शर्त नहीं है ।
- (v) डेनमार्क में मै0 कैमिनोवा की सहायक कंपनी द्वारा किए गए निर्यात संबद्ध देश (चीन जन गण) से इतर देश द्वारा किए गए निर्यात हैं जो नियम 2 (ख) की परिभाषा में शामिल नहीं है ।
- (vi) मै0 सबैरो ऑर्गेनिक्स को शामिल न किए जाने के मामले में उसे इन आधारों पर शामिल नहीं किया गया कि (क) कंपनी ने उत्पाद में बड़ी मात्रा में कमी की अथवा उसे बंद कर

दिया और उत्पाद का आयात शुरू कर दिया तथा (ख) कंपनी ने बड़ी मात्रा में विचाराधीन उत्पाद का आबद्ध रूप से उपयोग किया।

- (vii) आबद्ध खपत पर विचार न किए जाने के संबंध में यह देखा जा सकता है कि यदि ऐसी आबद्ध खपत को शामिल नहीं किया जाता तब भी मै0 कैमिनोवा का उत्पादन न्यूनतम प्रारंभिक सीमा से कहीं अधिक है। इसके अतिरिक्त मै0 सबैरो ऑर्गेनिक्स बाजार में डी ई टी पी सी की बिक्री नहीं करता और संपूर्ण उत्पादन का प्रयोग कर लेता है। अतः इस आधार पर मै0 सबैरो के उत्पादन को शामिल नहीं किया जा सकता है।
- (viii) पाटनरोधी नियमावली के अनुसार यदि आवेदक भारतीय उत्पादन के 25 प्रतिशत से अधिक का उत्पादन करता है तो आवेदन की स्थायी शर्त पूरी होगी। मौजूदा मामले में आवेदक का उत्पादन कुल भारतीय उत्पादन के 28 प्रतिशत से अधिक है और मै0 एक्सेल इंडस्ट्रीज, जिनका उत्पादन लगभग 71 प्रतिशत है, द्वारा आवेदन का समर्थन किया गया है।
- (ix) अपेक्षाकृत छोटी अवधि में भारी मात्रा में आयात हुए हैं जो इस तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि मार्च 2009 के दौरान न्यूनतम 1,500 मी.टन डी ई टी पी सी का आयात किया गया था और चालू माह में लगभग 2,000 मी.टन के आयात, जो सामान्य मूल्य से कम कीमत पर किए जा रहे हैं, को स्वीकृति दी जानी है।
- (x) अत्यधिक आयात के कारण दोनों घरेलू उद्योगों को अपना उत्पादन कम करने के लिए बाध्य होना पड़ा है और वे उत्पादन लागत से कहीं कम कीमत पर भारी पाटन के कारण क्षति का सामना कर रहे हैं।
- (xi) डी ई टी पी सी का प्रयोग कृषि-रसायनों (कीटनाशक) के विनिर्माण के लिए किया जाता है जो मुख्यतः खरीफ के मौसम में प्रयोग होने वाला मौसमी उत्पाद है और दो माह के लिए शुल्क अधिरोपण में विलंब से आयातक को पूरे एक वर्ष के लिए लाभ प्राप्त होगा। परिपक्वता अवधि से पूर्व के चरण में उच्च न्यायालय में जाने का संपूर्ण प्रयोजन पाटनरोधी शुल्क के अधिरोपण में विलंब करके संबंधित उत्पाद की मौसमी खपत की अवधि प्राप्त करना है।
- (xii) मै0 एक्सेल इंडस्ट्रीज ने न केवल पाटनरोधी शुल्क के अधिरोपण हेतु आवेदन का समर्थन किया है बल्कि प्राधिकारी को लागत निर्धारण तथा क्षति संबंधी सूचना भी प्रदान की है।
- (xiii) चूंकि आवेदन की स्थिति या घरेलू उद्योग के दायरे के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों में कोई तर्काधार नहीं है अतः भूतलक्षी आधार पर पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण पूर्णतया उचित है।

ग) प्राधिकारी द्वारा जाँच

14. सुनवाई के उपरांत हितबद्ध पक्षकारों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों/अनुरोधों की निम्नानुसार जाँच की गई है:-

- i) घरेलू उद्योग के रूप में मै0 कैमिनोवा इंडिया लि0 की पात्रता के संबंध में यह पाया गया कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 (3) के साथ पठित नियम 2 (ख) के अनुसार प्राधिकारी द्वारा इस बात से संतुष्ट होना अपेक्षित है कि क्या आवेदन घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से दायर किया गया है।

पाटनरोधी नियमावली के 2 (ख) में निम्नानुसार उल्लेख है:-

" घरेलू उद्योग " का तात्पर्य समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न समूचे घरेलू उत्पादकों या ऐसे उत्पादकों से है, जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक प्रमुख भाग बनता है, परन्तु जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं तो ऐसे मामले में ऐसे उत्पादकों को घरेलू उद्योग का एक भाग नहीं माना जाएगा;

पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 (3) में निम्नानुसार प्रावधान है:

" निर्दिष्ट प्राधिकारी उप नियम (1) के तहत दायर किए गए आवेदन के अनुसार तब तक जाँच की शुरुआत नहीं करेंगे जब तक कि:-

(क) वे समान वस्तु के घरेलू उत्पादकों द्वारा दिए गए आवेदन के समर्थन अथवा विरोध के स्तर की जाँच के आधार पर यह निर्धारण न कर लें कि आवेदन घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से किया गया है;

परन्तु यह कि किसी जाँच की शुरुआत नहीं की जाएगी यदि आवेदन का स्पष्ट रूप से समर्थन करने वाले घरेलू उत्पादकों का हिस्सा घरेलू उद्योग द्वारा किए गए समान वस्तु के कुल उत्पादन के पच्चीस प्रतिशत से कम हो, और

(ख) वे आवेदन में प्रदत्त साक्ष्य की सतीकता और समुचितता की जाँच करेंगे और निम्नलिखित के संबंध में स्वयं को संतुष्ट करेंगे -

(i) पाटन,

(ii) क्षति, जहाँ भी लागू हो; और

(iii) जाँच शुरुआत का औचित्य सिद्ध करने के लिए जहाँ भी लागू हो, ऐसे पाटित आयातों तथा कथित क्षति के बीच कारणात्मक संबंध

व्याख्या - इस नियम के प्रयोजनार्थ आवेदन को घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से दायर माना जाएगा यदि वह उन घरेलू उत्पादकों द्वारा समर्थित हो जिनका सामूहिक उत्पादन घरेलू उद्योग के उस हिस्से, जो यथास्थिति आवेदन का समर्थन अथवा विरोध कर रहा हो, द्वारा उत्पादित समान वस्तु के कुल उत्पादन के 50 प्रतिशत से अधिक हो।"

ii) यह पाया गया है कि मौजूदा मामले में संबद्ध वस्तु का आयातक होने के कारण मै0 सबैरो ऑर्गेनिक्स के उत्पादन, यदि हो, को छोड़कर घरेलू उत्पादन में आवेदक का हिस्सा 27.33 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त आवेदन एक प्रमुख उत्पादक मै0 एक्सेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा समर्थित है जिसका कुल उत्पादन घरेलू उत्पादन के 50 प्रतिशत से अधिक है।

iii) जाँच शुरूआत से पूर्व मतगणना की अपेक्षा के संबंध में यह सूचित किया जाता है कि जाँच शुरूआत से पूर्व मत प्राप्त करने से संबंधित कोई पूर्व निर्धारित कानूनी आवश्यकता नहीं है। जाँच शुरूआत करते समय प्राधिकारी द्वारा एक विस्तृत पड़ताल करना अपेक्षित नहीं है लेकिन नियम 5 (3) के तहत निर्धारित शर्तों के प्रति संतुष्ट होना अपेक्षित है। घरेलू उत्पादकों तथा उनके उत्पादन की पुष्टि के लिए संबंधित प्रशासनिक विभाग से संगत ब्यौरे उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था।

iv) यह तर्क निराधार है कि प्राधिकारी को इस बात की सूचना होने के बावजूद कि भारत में संबद्ध वस्तु के तीन उत्पादक हैं, प्राधिकारी ने मै0 सबैरो ऑर्गेनिक्स के उत्पादन पर विचार नहीं किया। संबंधित प्रशासनिक विभाग से मै0 सबैरो ऑर्गेनिक्स सहित घरेलू उत्पादकों तथा उनके उत्पादन से संबंधित ब्यौरे उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग ने केवल मै0 कैमिनोवा तथा मै0 एक्सेल इंडस्ट्रीज के बारे में ही सूचना प्रदान की। इस सूचना से आवेदक द्वारा अपने आवेदन में इस संबंध में दी गई सूचना की पुष्टि हुई। जाँच की शुरूआत के उपरांत मै0 सबैरो ऑर्गेनिक्स से भी अपना उत्तर प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था लेकिन अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला है। घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोधों से यह भी पता चला कि मै0 सबैरो ऑर्गेनिक्स ने उत्पादन में काफी मात्रा में कमी की अथवा उसे रोक दिया और आयात शुरू कर दिए तथा आबद्ध रूप से उत्पाद का उपयोग भी किया।

v) यह तर्क भी सही नहीं है मै0 कैमिनोवा ने आवेदन के अगोपनीय रूपांतर में डेनमार्क स्थित अपनी मूल कंपनी के साथ अपने संबंध को छिपाया था। वास्तव में डेनमार्क में स्थित मूल कंपनी से संबंध से जुड़े तथ्यों को छिपाया नहीं गया था। प्राधिकारी ने जाँच शुरूआत से पहले विशेष रूप से इस संबंध में सूचना माँगी थी और आवेदक द्वारा तथ्य प्रस्तुत किए गए थे।

vi) यह अनुरोध सही नहीं है कि मै0 कैमिनोवा इंडिया लि0 की मूल कंपनी मै0 कैमिनोवा डेनमार्क द्वारा भारत को किए गए निर्यातों के कारण मै0 कैमिनोवा इंडिया लि0

का घरेलू उद्योग का दर्जा खत्म हो जाता है। मूल कंपनी द्वारा किए गए निर्यात संबद्ध देश अर्थात् चीन जन गण से नहीं थे अतः उन्हें पाटित वस्तु नहीं माना जा सकता है। माननीय सी ई एस टी ए टी ने अपने विभिन्न निर्णयों में यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि केवल संबद्ध देशों के मामले में ही घरेलू उद्योग तथा संबंधित निर्यातकों के संबंधों की जांच की जानी चाहिए। बिरला एरिक्सन लि० बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी [2001 (127) ई-एल टी 363 (टी आर आई - डी ई एल)] के मामले में माननीय सी ई एस टी ए टी ने निम्नानुसार निर्णय दिया था:

" आवेदकों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील का उपर्युक्त तर्क पूर्ण रूप से नियमावली के नियम 2 (ख), जो घरेलू उद्योग को परिभाषित करता है, में उल्लिखित अपवर्जन पर आधारित है। यह परिभाषित करने के बाद कि घरेलू उद्योग का तात्पर्य उन घरेलू उत्पादकों से है जिनका संबद्ध वस्तु का सामूहिक उत्पादन कुल घरेलू उत्पादन में प्रमुख हिस्सा रखता है, कुछ श्रेणियों को उसमें शामिल नहीं किया गया है। अपवर्जित श्रेणियाँ वे घरेलू उत्पादक हैं जो कथित रूप से पाटित वस्तु के निर्यातकों से संबंध रखते हैं, जो कथित रूप से पाटित वस्तु के आयातकों से संबंध रखते हैं अथवा जो स्वयं उस वस्तु के आयातक हैं।" उस वस्तु के आयातक " शब्दों का दायरा क्या है? घरेलू उत्पादकों, जो संबद्ध वस्तु के आयातक हैं, के इस वर्ग को कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों से संबंध रखने वाले घरेलू उत्पादकों और कथित पाटित वस्तु के आयातकों से संबंध रखने वाले घरेलू उत्पादकों के साथ जोड़ा जाएगा। इस प्रकार घरेलू उत्पादक जो स्वयं आयातक हैं का तात्पर्य उन घरेलू उत्पादकों से है जो स्वयं कथित पाटित वस्तु के आयातक हैं। दूसरे शब्दों में उन घरेलू उत्पादकों को "घरेलू उद्योग" की परिभाषा में से अपवर्जित नहीं किया जाएगा जो स्वयं संबद्ध देश से कथित पाटित वस्तु के आयातक नहीं हैं।"

vii) यह आरोप लगाया गया है कि मै० कैमिनोवा ने संबद्ध वस्तु की आबद्ध खपत की है और निर्धारित कानून के अनुसार जाँच शुरुआत से पूर्व निर्धारण करते समय आबद्ध खपत को शामिल नहीं किया जा सकता है। मै० कैमिनोवा द्वारा आवेदन के अगोपनीय सारांश में संबद्ध वस्तु की अपनी आबद्ध खपत का ब्यौरा न दिए जाने के कारण वह घरेलू उद्योग माने जाने के लिए पात्र नहीं है। यह पाया गया है कि मै० कैमिनोवा ने बिक्री शीर्ष के अंतर्गत क्र०सं० 1 पर प्रोफार्मा IV क के तहत अपनी याचिका में अपनी आबद्ध खपत दर्शाई है हालांकि वह नाम मात्र के लिए है। इसके अलावा यदि आबद्ध खपत की मात्रा को शामिल न किया जाए तो भी शीर्ष मात्रा 26.53 प्रतिशत है जो पाटनरोधी नियमावली के अंतर्गत 25 प्रतिशत की निर्धारित प्रारंभिक सीमा से अधिक है।

viii) यह तर्क निराधार है कि मै० एक्सेल इंडस्ट्रीज लि०, जो जाँच की शुरुआत के समय आवेदक नहीं था, को बाद में सूचना प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह देखा गया है कि मै० एक्सेल इंडस्ट्रीज लि०, जो घरेलू उत्पादन का 72.67 प्रतिशत से भी अधिक हिस्सा रखने वाला एक प्रमुख उत्पादक है, ने आरंभिक चरण से ही

याचिका का समर्थन करने के साथ, समग्र क्षति अवधि और जांच अवधि के दौरान अपने उत्पादन और घरेलू बिक्री के संबंध में प्राधिकारी को संगत सूचना/आंकड़े प्रस्तुत किए हैं।

ix) जैसाकि नियम 6 (7) के अंतर्गत पूर्व निधारित है, विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दी गई सूचनाओं की अगोपनीय प्रतियाँ रखने वाली एक सार्वजनिक फाइल तैयार की गई है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने उस फाइल का अवलोकन किया है और अपेक्षित सूचनाओं की प्रतियाँ प्राप्त की हैं। याचिकाकर्ता सार्वजनिक फाइल तैयार किए जाने की इस पद्धति से पूर्णतः परिचित है और वह आवश्यक सूचनाओं की अपेक्षित प्रतियाँ प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता था।

15. मै. मेघमणि आर्गेनिक्स लि., अहमदाबाद और अन्य हितबद्ध पक्षकारों की ओर से किए गए अनुरोधों की विस्तृत जांच और उन पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद तथा संगत नियमावली तथा निर्णयों पर भरोसा करते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी ने 6 मई, 2009 के आदेश द्वारा एक स्पीकिंग ऑर्डर जारी किया। यह देखा गया कि मै. एक्सल इंडस्ट्रीज लि. द्वारा समर्थित मै. कैमिनोवा इंडिया लि. घरेलू उद्योग हैं और प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी जांच की शुरुआत करना पाटनरोधी नियमावली और संबंधित कानून के अंतर्गत पूर्णतः उनके क्षेत्राधिकार के भीतर है। तदनुसार चीन जन.गण. के मूल की अथवा वहां से निर्यातित डाइथाइल थियो फॉस्फोरिल क्लोराइड (डी ई टी पी सी) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच को जारी रखने का आदेश दिया गया ताकि पाटनरोधी नियमावली और कानून के अनुसार आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु सिफ़ारिश की जा सके।

घ.2. माननीय गुजरात उच्च न्यायालय, अहमदाबाद के समक्ष विशेष सिविल याचिका सं. 2009 की 6881

16. मै. मेघमणि आर्गेनिक्स लि., अहमदाबाद ने गुजरात के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष 2009 की विशेष सिविल याचिका सं. 6881 के माध्यम से पुनः एक याचिका दायर की जिसमें दिनांक 17.11.2008 की जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना और गुजरात उच्च न्यायालय के माननीय डिविजन बैंच के 8.4.2009 के पूर्ववर्ती आदेशों के अनुपालन में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए दिनांक 6.5.2009 के आदेश, 25.5.2009 के प्रारंभिक जांच परिणाम और दिनांक 22.6.2009 की सी.शु. अधिसूचना सं. 73/2009 को इन आधारों पर चुनौती दी गई कि जांच शुरुआत संबंधी सूचना क्षेत्राधिकार के बिना है और संपूर्ण जांच में अत्यधिक गोपनीयता बरती गई है।

17. उच्च न्यायालय की माननीय डिविजन बैंच ने दिनांक 9-10-2009 के आदेश द्वारा गोपनीयता के मुद्दे पर निर्दिष्ट प्राधिकारी के प्रारंभिक जांच परिणाम को अस्वीकृत कर दिया। माननीय डिविजन बैंच ने निर्दिष्ट प्राधिकारी को जांच परिणामों के उन सभी आवश्यक ब्यौरों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जिन्हें प्रारंभिक जांच परिणामों को रिकॉर्ड करते समय

रिक्त रखा गया है ताकि याचिकाकर्ता इस संबंध में आपत्तियां उठा सकें और अंतिम जांच परिणाम रिकॉर्ड करते समय उन आपत्तियों और अनुरोधों पर विचार किया जाए । निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात पर भी विचार करने का निर्देश दिया गया था कि क्या एक्सल इंडस्ट्रीज लि. (पूर्ववर्ती प्रतिवादी सं. 4) और उनकी संबद्ध कंपनी ने चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तु का कोई आयात किया है । इसके अलावा, निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यह प्रक्रिया शुरू किए जाने और अंतिम जांच परिणाम घोषित करने तक याचिकाकर्ता को चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तु के आयात पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क की लेवी से छूट प्रदान की जाए । इस छूट को आदेश की तारीख के एक सप्ताह के भीतर प्राधिकारी के समक्ष इस आशय की एक वचनबद्धता प्रस्तुत करने के अधीन रखा गया जिसमें यह कहा गया हो कि यदि वे संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क देने के लिए पात्र माने जाते हैं तो इस मामले में अंतिम जांच परिणाम रिकॉर्ड करते समय वे अपील करने के अपने अधिकार और किसी संक्षम न्यायालय या न्यायाधिकरण से ऐसे शुल्क के विरुद्ध स्टे प्राप्त करने के अधीन ऐसे पाटनरोधी शुल्क का भुगतान करेंगे ।

विचाराधीन आदेशों के संगत हिस्सों को नीचे उद्धरित किया गया है:

"अतः हम विवादित अधिसूचना में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निर्णित अन्य मुद्दों पर कोई राय व्यक्त नहीं करते हुए और अंतिम जांच परिणामों के समय याचिकाकर्ता के चुनौती देने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए हम गोपनीयता के मुद्दे पर निर्दिष्ट प्राधिकारी के प्रारंभिक जांच परिणामों को अस्वीकृत करते हैं और निर्दिष्ट प्राधिकारी को जांच परिणामों के सभी आवश्यक ब्यौरे उपलब्ध कराने का निर्देश देते हैं जिन्हें प्रारंभिक जांच परिणाम रिकॉर्ड करते समय रिक्त रखा गया है ताकि याचिकाकर्ता इस संबंध में आपत्तियां उठा सकें और अंतिम जांच परिणाम रिकॉर्ड करते समय निर्दिष्ट प्राधिकारी इस संबंध में की गई ऐसी आपत्तियों और अनुरोधों को ध्यान में रखेंगे । केवल यही नहीं निर्दिष्ट प्राधिकारी प्रतिवादी सं. 4 के संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए मुद्दों को भी ध्यान में रखेंगे और इस बात का निर्णय करेंगे कि क्या वे या उनकी संबद्ध कंपनी ने चीन से संबद्ध वस्तु का कोई आयात किया है । निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड किए गए जांच परिणामों के ब्यौरे याचिकाकर्ताओं को उपलब्ध कराए जाएंगे । निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा इस प्रक्रिया को शुरू किए जाने और प्रारंभिक जांच परिणामों तक पहुंचने तक याचिकाकर्ता पर चीन से संबद्ध वस्तु के आयातों पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क का बोझ नहीं डाला जाएगा जो इस शर्त के अधीन होगा कि याचिकाकर्ता आज की तारीख से एक सप्ताह के भीतर निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष इस आशय की एक वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि यदि उन्हें चीन से एतदपश्चात् संबद्ध वस्तु के लिए गए आयात पर पाटनरोधी का भुगतान का करने का पात्र माना जाएगा तो इस मुद्दे पर अंतिम जांच परिणाम रिकॉर्ड किए जाते समय वे अपील करने के अपने अधिकार और किसी संक्षम न्यायालय या न्यायाधिकरण से ऐसे शुल्क के विरुद्ध स्टे प्राप्त करने के अधीन पाटनरोधी शुल्क का भुगतान करेंगे"

एक बार पुनः इस बात को स्पष्ट किया गया है कि हमने किसी अन्य मुद्दे जिसे इस न्यायालय के समक्ष उठाया गया है या निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड किए गए जांच परिणामों पर कोई राय व्यक्त नहीं की है और उन्हें खुला रखा गया है और पक्षकार यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो अंतिम जांच परिणामों को चुनौती देते समय उचित मंच के समक्ष उसका विरोध करने के लिए स्वतंत्र हैं।

पूर्वोक्त समुक्तियों और निर्देशों के अधीन तदनुसार इस याचिका का निपटारा किया जाता है। नियमों को लागतों के संबंध में कोई आदेश दिए बिना केवल उपर्युक्त सीमा तक निरपेक्ष बनाया गया है।

इस स्थिति में प्रतिवादी सं. 3 और 4 की ओर से इस आदेश के कार्यकरण पर रोक लगाने का एक अनुरोध किया गया है ताकि वे उच्चतर मंच के पास जाने में सक्षम हो सकें क्योंकि गोपनीयता के पहलू से उन्हें नुकसान हुआ है। गोपनीयता के संबंध में हमारे जांच परिणाम के मद्देनजर इन प्रतिवादियों को कोई हानि होने का प्रश्न नहीं उठता है। यह भी तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा आयात की जाने वाली वस्तु पर पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाने का निर्देश देने से प्रतिवादी सं. 3 और 4 के हित के प्रभावित होने की संभावना है। हमारी राय में इसके परिणामस्वरूप अलग-अलग आधारों पर विधिक न्यायिक आदेशों पर रोक नहीं लगाई जाती है। अतः इस अनुरोध को माना नहीं जा सकता है।

घ.3. 2010 की विशेष लीव याचिका सं. 887

18. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने 2010 की विशेष लीव पेटिशन सं. 887 और पृथक रूप से 2009 की स्पेशल लीव पेटिशन सं. 34374 द्वारा कैमिनोवा इंडस्ट्रीज लि. और 2009 की स्पेशल लीव पेटिशन सं. 35243 द्वारा एक्सल इंडस्ट्रीज लि. (घरेलू उद्योग) द्वारा भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष गुजरात उच्च न्यायालय की माननीय डिविजन बेंच के 9-10-2009 के आदेशों को चुनौती दी।

पक्षकारों को सुनने के बाद माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 8 फरवरी, 2010 के अपने आदेश द्वारा निम्नानुसार आदेश दिया :

"लीव प्रदत्त".

सुनवाई शीघ्रता से की जाए।

अपीलों का निपटारा होने तक विवादित आदेश पर रोक लगी रहेगी।

26 अगस्त, 2010 को अपील प्रस्तुत करें

घ.4 विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई रिट याचिकाएं:

19. मै. सिरीज क्रॉप साइसेंस लि. ने 2010 की रिट याचिका सं. 190 के द्वारा, मै. सेबोरो आर्गोनिक्स गुजरात लि. ने 2010 की रिट याचिका सं. 173 के द्वारा, मै. रोटेम इंडिया लि. ने 2010 की रिट याचिका सं. 191 के द्वारा, मै. पी आई इंडस्ट्रीज लि. ने 2010 की रिट याचिका सं. 183 के द्वारा, मै. जीएसपी क्रॉप साइसेंस प्रा. लि. ने 2010 की रिट याचिका सं. 736 के द्वारा, मै. भागीरथा कैमिकल्स इंडस्ट्रीज लि. ने 2010 की रिट याचिका सं. 737 के द्वारा और मै. गर्दा कैमिकल्स लि. ने 2010 की रिट याचिका सं. 738 के द्वारा रिट याचिकाएं दायर की हैं जिनमें 17.11.2008 की जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना, गुजरात उच्च न्यायालय की माननीय डिविजन बेंच के आदेशों के अनुपालन में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा 6.5.2009 को जारी किए गए आदेश 25.5.2009 के प्रारंभिक जांच परिणामों और दिनांक 22.6.2009 की सी.सु. अधिसूचना सं. 73/2009 को इन आधारों पर दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है कि जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना क्षेत्राधिकार के बिना है और संपूर्ण जांच अत्यधिक गोपनीयता से ग्रस्त है।

20. पक्षकारों को सुनने के बाद माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी किया और मामले की सुनवाई 24.5.2009 को निर्धारित की। चूंकि रिट याचिकाकर्ताओं ने अंतरिम रोक आदेश के लिए भी आवेदन प्रस्तुत किया था, परंतु माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा कोई अंतरिम रोक आदेश नहीं दिया गया।

ड. घरेलू उद्योग का दायरा और स्थिति

ड.1. निर्यातकों के विचार

21. प्रारंभिक जांच परिणामों के बाद के स्तर पर मै. दुआ एसोसिएट्स ने मै. यांगजिन चेन्नियान कैमिकल इंडस्ट्रीज कं. लि., जेझियांग जिनोंग कैमिकल कं. लि. और चाइना क्रॉप प्रोटेक्शन इंडस्ट्री एसो. की ओर से निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- (i) याचिकाकर्ता नियम 2 (ख) के अंतर्गत "घरेलू उद्योग" नहीं हैं और यह याचिका पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(1) और 5(3) के विपरीत स्थिति संबंधी अपेक्षाओं को पूरा नहीं करती है और इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए।
- (ii) याचिकाकर्ता न तो समान वस्तु के विनिर्माण में कार्यरत एकमात्र घरेलू उत्पादक है और न ही उक्त वस्तु का याचिकाकर्ता का उत्पादन उस वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का प्रमुख हिस्सा बनता है।

- (iii) कैमिनोवा इंडिया लि. कथित पाटित वस्तु के निर्यातक कैमिनोवा डेनमार्क से स्पष्ट रूप से संबंधित हैं ।
- (iv) प्राधिकारी ने त्रुटिपूर्ण ढंग से इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है कि मै. कैमिनोवा इंडिया लि. की मूल कंपनी मै. कैमिनोवा डेनमार्क द्वारा भारत को किए गए निर्यात कैमिनोवा इंडिया को घरेलू उद्योग के रूप में अपात्र ठहराते हैं, जिसमें यह कहा गया है कि मूल कंपनी द्वारा किए गए निर्यात संबद्ध देश अर्थात् चीन जन.गण. से नहीं किए गए हैं और इस प्रकार उन्हें पाटित वस्तु नहीं माना जा सकता है ।
- (v) इन जांच परिणामों पर पहुंचते समय चीन में कैमिनोवा की मूल कंपनी की मौजूदगी की पूरी जांच घरेलू उद्योग के उनके दर्जे के संबंध में नहीं की गई है । मूल कंपनी कैमिनोवा डेनमार्क का कैमिनोवा शंघाई रिप्रजेंटेटिव कार्यालय और याचिकाकर्ता कैमिनोवा जो मूल कंपनी की अधीनस्थ है, दोनों को प्रत्यक्ष और/अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उक्त कैमिनोवा डेनमार्क द्वारा नियंत्रित किया जाता है । तदनुसार यदि नियम 2(ख) पर केवल संबद्ध देश अर्थात् चीन जन.गण. के संदर्भ में शब्दशः गौर किया जाए तो उस परीक्षण के द्वारा भी कैमिनोवा घरेलू उद्योग के परीक्षण में पूरा नहीं उतरता है ।
- (vi) प्राधिकारी यह घोषित करते समय कि मै. एक्सल इंडस्ट्रीज लि. द्वारा समर्थित कैमिनोवा इंडिया लि. घरेलू उद्योग है, इस बात की जांच करने में पूर्णतः विफल हो गए हैं कि क्या एक्सल पाटनरोधी नियमावली के अनुसार "घरेलू उद्योग" की कसौटी को पूरा करता है । वस्तुतः माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणामों में स्वयं इस पहलू को रिकॉर्ड किया है कि मै. एक्सल इंडस्ट्रीज लि. द्वारा बाद में निवेदन किया गया है । यद्यपि, उन्होंने माना है कि यह तर्क कि बाद के अनुरोध की अनुमति नहीं है, सही नहीं है क्योंकि एक्सल ने कथित रूप से संगत सूचना/आंकड़ों के साथ आरंभिक स्तर से याचिका का समर्थन किया है । इस प्रकार यह अनुरोध किया जाता है कि यह एक त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण है और यह दोहराया जाता है कि एक अनुवर्ती प्रस्तुतिकरण जिसकी पात्रता की जांच किया जाना अपेक्षित है, को प्राधिकारी को क्षेत्राधिकार दिए जाने के संबंध में पूर्वव्यापी प्रभाव से प्रयोग नहीं किया जा सकता है जो संगत समय अर्थात् जांच शुरूआत के समय उनके पास नहीं था ।
- (vii) कैमिनोवा इंडिया लि. उपर्युक्त अनुरोधों के अनुसार भी "घरेलू उद्योग" नहीं हैं । इसके अलावा, यदि यह स्वीकार किए बिना माना भी जाता है कि यह आवेदन घरेलू उद्योग "की ओर से" किया गया है, तो "घरेलू उद्योग" से संबंधित सूचना कैमिनोवा इंडिया लि. के आवेदन का हिस्सा नहीं थी, जिसके आधार पर वर्तमान जांच शुरू की गई है ।

- (viii) एक्सल ने एक समूह के रूप में स्वयं एक्सल क्रॉप केयर लि. के माध्यम से डीटीपीसी का आयात किया है और इसलिए वे पाटनरोधी कानून के अंतर्गत संरक्षण मांगने के लिए पात्र नहीं हैं ।

ड.2. आयातकों के विचार

22. प्रारंभिक जांच परिणामों के बाद मै. ए पी जे- एस एल जी, लॉ आफिसेज ने मै. गर्दा कैमिकल्स लि., मेघमनी आर्गेनिक्स लि., सिरिस क्रॉप साइंसेस लि. और पी आई इंडस्ट्रीज लि. की ओर से निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :

(क) खंड 5(1) में यह व्यवस्था है कि आवेदन "घरेलू उद्योग द्वारा या उनकी ओर से" किया जाना चाहिए । स्वीकृत रूप से यह आवेदन मै. कैमिनोवा द्वारा प्रस्तुत किया गया है जो नियम 2(ख) के अंतर्गत यथापरिभाषित ढंग से "घरेलू उद्योग" होने के पात्र नहीं हैं ।

(ख) नियम 5(3) के अंतर्गत यथाअधिदेशित कोई निर्धारण प्राधिकारी द्वारा नहीं किया गया है जिससे इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके कि आवेदन घरेलू उद्योग की ओर से दायर किया गया है ।

(ग) यह आवेदन एकमात्र उत्पादक मै. कैमिनोवा द्वारा दायर किया गया है और न कि घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से, आवेदन में दी गई क्षति संबंधी सूचना एकमात्र उत्पादक अर्थात् मै. कैमिनोवा के लिए है और न कि घरेलू उद्योग या न ही मै. एक्सल की सूचना को शामिल करने के बाद, के लिए है । इस प्रकार नियम 5(3) की शर्तों के साथ सूचना की पर्याप्तता और सत्यता को लागू या उसकी जांच नहीं की जा सकती है । इसके अलावा, निर्यातकों के साथ संबंधित पक्षकारों को जांच से अलग रखने की जांच पर विचार नहीं किया गया है । कानून के अंतर्गत यथाअधिदेशित सही निर्धारण करने के लिए आबद्ध खपत की कोई जांच भी नहीं की गई है ।

(घ) कैमिनोवा इंडिया संबद्ध वस्तु के प्रमुख उत्पादक नहीं हैं क्योंकि एक्सल के पास कुल भारतीय उत्पादन का 71% हिस्सा है ।

(ड) कैमिनोवा इंडिया कथित पाटित वस्तु के निर्यातक अर्थात् कैमिनोवा डेनमार्क से संबंधित हैं । प्राधिकारी ने त्रुटिपूर्ण ढंग से यह माना है कि मै. कैमिनोवा डेनमार्क द्वारा किए गए निर्यात संबद्ध देश अर्थात् चीन जन.गण. से नहीं किए गए हैं और इस प्रकार उन्हें पाटित वस्तु नहीं माना जा सकता है ।

(च) जांच की शुरुआत कैमिनोवा इंडिया द्वारा प्रस्तुत सूचना पर आधारित है जो घरेलू उद्योग नहीं है। समर्थक मै. एक्सल ने जांच शुरुआत के समय कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की है।

(छ) एक्सल घरेलू उद्योग का हिस्सा नहीं हो सकता है। जब तक प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में उसकी जांच नहीं की जाए कि एक्सल नियम 2(ख) के अंतर्गत उल्लिखित मापदंडों को पूरा करता है।

(ज) आवेदक मै. कैमिनोवा घरेलू उद्योग नहीं है क्योंकि उनका कुल भारतीय उत्पादन में केवल 28% हिस्सा बनता है और वे विचाराधीन उत्पाद के डेनमार्क के निर्यातक से संबंधित हैं।

(झ) भारत में संबद्ध वस्तु के कुल 3 उत्पादक हैं। जांच शुरुआत के समय निर्दिष्ट प्राधिकारी को अन्य मामलों की तरह भारत में कुल उत्पादन का पता लगाने के लिए उनके विचार मंगाने चाहिए थे।

(ञ) नियम 2(ख) के अंतर्गत समर्थक की जांच की परिकल्पना नहीं की गई है। परंतु केवल प्रमुख हिस्सा बनने वाले आवेदक की जांच की व्यवस्था है। यदि सबेरो एक्सल से माल खरीदता है तो इससे वह नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग से बाहर रखे जाने के लिए पात्र नहीं बनता है। इसके अलावा, इस तथ्य के कारण उत्पादन में कमी करना अनावश्यक है।

(ट) प्राधिकारी यह घोषित करते समय कि "मै. एक्सल इंडस्ट्री लि. द्वारा समर्थित कैमिनोवा इंडिया लि. घरेलू उद्योग हैं" इस बात की जांच करने में पूर्णतः विफल हो गए हैं कि क्या एक्सल पाटनरोधी नियमावली के अनुसार "घरेलू उद्योग" की कसौटी पर खरा उतरता है।

(ठ) इस बात से इंकार किया गया है कि एक्सल क्राप केयर लि. याचिकाकर्ता की एक संबंधित कंपनी है। कंपनी लॉ के अनुसार उसके दायित्व के अंतर्गत उसे एक्सल के रिकॉर्डों में एक संबंधित कंपनी दर्शाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में उनके द्वारा किए गए अनुरोधों को गोपनीय माना गया है। वह भी इस तथ्य के बावजूद कि इसका कोई अगोपनीय अंश प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(ड) एक्सल क्राप केयर के उत्तर के गोपनीयता का बिना कोई कारण बताए ऐसे दावों के गोपनीय होने का दावा किया गया है और इसका भी कारण नहीं बताया गया है कि इन्हें सूचीबद्ध करना क्यों संभव नहीं है। इस तरह की प्रक्रिया नियम 7 की अपेक्षाओं के विपरीत है।

(ढ) एक्सल का पिछले दरवाजे से प्रवेश इस रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि यदि उन्हें जांच शुरुआत के समय शामिल किया जाता तो यह मामला जांच शुरुआत की पूर्व शर्तों को पूरा कर लेगा और क्षति का परिसमापन हो जाएगा । स्पष्ट रूप से इस तरह की नीति पूर्व नियोजित थी और अनंतिम शुल्क लागू करवाकर वाणिज्यिक लाभ पहले ही लिया जा चुका है ।

(ण) याचिकाकर्ता "घरेलू उद्योग" नहीं है और यह याचिका योग्यता संबंधी अपेक्षाओं को पूरा नहीं करती है । वर्तमान याचिका पाटनरोधी नियमावली के नियम 5(1) और 5(3) के विपरीत हैं और इसे निरस्त कर दिया जाना चाहिए ।

(त) घरेलू उद्योग ने यह स्वीकार किया है कि यह आवेदन मै. कैमिनोवा द्वारा दायर किया गया है जिनका नियम 2(ख) के अनुसार भारत के कुल उत्पादन में काफी कम हिस्सा बनता है । दूसरे शब्दों में वह घरेलू उद्योग के रूप में पात्र नहीं हैं और घरेलू उद्योग के लिए नियम 5(2)(ख) और नियम 5(2)(ग) के अनुसार समग्र रूप से क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं करा सकते हैं । समग्र रूप से घरेलू उद्योग के लिए आवेदन में स्वयं ऐसे आंकड़े और सूचना के अभाव में प्राधिकारी को वर्तमान मामले में जांच की शुरुआत नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि ये जांच शुरुआत के पूर्व शर्तें हैं । इसके अलावा, नियम 2(ख) के अंतर्गत निर्यातकों के साथ संबंध और संबंधित कंपनियों से आयात की अपेक्षाओं को जांच की शुरुआत के बाद एक्सल पर लागू किया गया है । दूसरे शब्दों में जांच शुरुआत की पूर्व शर्त के तौर पर इस जांच को जांच शुरुआत के बाद लागू किया जा रहा है । केवल यही तथ्य वर्तमान जांच को समाप्त करने के लिए एक पर्याप्त कारण है ।

(थ) नियम 2(ख) के अंतर्गत प्रदत्त स्वविवेक का तब तक प्रयोग नहीं किया जा सकता जब तक एक उचित समय पर निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास आवश्यक तथ्यपूर्ण सामग्री उपलब्ध नहीं हो । स्पष्ट रूप से जांच शुरुआत के स्तर पर यह सभी सूचना रिकॉर्ड में भी नहीं थी और इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने नियम 2(ख) के अंतर्गत स्व-विवेक का इस्तेमाल किया है । चूंकि यह जांच शुरुआत की पूर्व शर्त है इसलिए समर्थक कारणों के बिना स्व-विवेक का प्रयोग किया जाना त्रुटिपूर्ण है और कानून के विरुद्ध है । उपर्युक्त के मद्देनजर घरेलू उद्योग द्वारा उद्धरित न्यायालय निर्णय वर्तमान जांच के तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू नहीं होता है ।

ड.3. घरेलू उद्योग के विचार

23. प्रारंभिक जांच परिणामों के बाद घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित विचार प्रस्तुत किए गए हैं:

(क) यह आवेदन मै. कैमिनोवा इंडिया लि. द्वारा दायर किया गया है और आवेदन के समय से मै. एक्सल इंडस्ट्रीज लि. द्वारा इसका समर्थन किया गया है। दोनों ने क्षति संबंधी सूचना उपलब्ध कराई है।

(ख) हितबद्ध पक्षकारों ने याचिका की स्थिति पर प्रश्न उठाया है। घरेलू उद्योग द्वारा विस्तृत अनुरोध किए गए थे। तत्पश्चात् निर्दिष्ट प्राधिकारी ने माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के 8 अप्रैल, 2009 के आदेशों के अनुपालन में दिनांक 6 मई, 2009 को एक विस्तृत स्पीकिंग ऑर्डर जारी किया है जिसमें यह माना गया है कि यह याचिका योग्यता संबंधी मापदंडों को पूरा करती है। घरेलू उद्योग यह अनुरोध करता है कि इस संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा की गई आपत्तियों का कोई तर्कसंगत आधार नहीं है। संपूर्ण आपत्तियां गलत और त्रुटिपूर्ण विधिक समझ पर आधारित है।

(ग) नियमावली में यह व्यवस्था है कि याचिका घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से दायर की जानी चाहिए जिसका अर्थ यह है कि याचिका ऐसे घरेलू उत्पादकों द्वारा समर्थित होनी चाहिए जिनका समग्र उत्पादन कुल उत्पादन के 50% के अधिक हो। स्वीकृत रूप से वर्तमान याचिका उन घरेलू उत्पादकों द्वारा समर्थित है जिनका समग्र उत्पादन पात्र घरेलू उत्पादन के 50% से अधिक है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता का उत्पादन घरेलू उद्योग द्वारा समान वस्तु के कुल उत्पादन के 25% से अधिक है। इस बात पर जोर दिया गया है कि सबैरो आर्गेनिक्स के उत्पादन को किसी भी तरह से इन बातों के मद्देनजर बाहर रखा जाए कि : (क) इस कंपनी ने उत्पादन को पर्याप्त रूप से कम कर दिया है या उसे रोक दिया है। (ख) यह कंपनी आबद्ध रूप से इस उत्पाद की पर्याप्त खपत कर रही है और कैमिनोवा और एक्सल इंडस्ट्रीज दोनों को सबैरो द्वारा डी ई टी पी सी की किसी बिक्री की जानकारी नहीं है, वह भी तब जबकि ये दोनों कंपनियां काफी समय से बाजार में मौजूद हैं और (ग) उनके द्वारा भारी मात्रा में आयात किए गए हैं। इसके अलावा, सबैरो ने आज की तारीख तक प्राधिकारी को कोई उत्तर नहीं दिया है।

(घ) डेनमार्क वर्तमान जांच में संबद्ध देश नहीं है। घरेलू उत्पादक जो संबद्ध देश से कथित घाटित वस्तु के आयातक नहीं हैं, को घरेलू उद्योग की परिभाषा से बाहर नहीं रखा जाए। यद्यपि, कैमिनोवा डेनमार्क के पास चीन में भी एक संबंधित कंपनी है, परंतु यह अनुरोध किया जाता है कि यह कंपनी विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन और बिक्री में बिल्कुल भी शामिल नहीं है और न ही उसने संगत अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया है।

(ङ) एक्सल की संबंधित कंपनी द्वारा किए गए आयातों के संबंध में यह अनुरोध किया जाता है कि एक्सल इंडस्ट्रीज और एक्सल क्राफ केयर असंबंधित कंपनियां हैं और एक्सल इंडस्ट्रीज की किसी भी संबंधित कंपनी ने विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है। तथापि, मै. एक्सल क्राफ केयर उन कंपनियों की श्रेणी में आती है, जिन पर प्रमुख प्रबंधन कर्मियों और/या उनके संबंधियों का पर्याप्त प्रभाव रहता है। कंपनी अधिनियम में यथापरिभाषित "प्रमुख प्रबंधन व्यक्ति" ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका अन्य कंपनियों पर पर्याप्त प्रभाव हो, इसका यह अर्थ नहीं है कि ऐसे प्रमुख प्रबंधन कार्मिक विधिक या प्रचालनात्मक रूप से दूसरी कंपनी पर नियंत्रण या

उन्हें निर्देश देने की स्थिति में हों । इसके अलावा, (i) एक्सल क्राप केयर और एक्सल इंडस्ट्रीज कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 370 (1 ख) और 372 (11) के प्रावधानों पर विचार करते हुए "एक समान प्रबंधन" के अधीन नहीं हैं और (ii) ऐसल क्राप केयर और एक्सल इंडस्ट्रीज, दोनों के बीच केवल एक साझा निदेशक है ।

(च) किसी पूर्वाग्रह के बिना यह अनुरोध किया जाता है कि एक्सल क्राप केयर ने चीन जन.गण. से विचाराधीन उत्पाद की मामूली मात्रा का आयात किया है ।

(छ) मै. सबैरो आर्गेनिक्स, के संबद्ध वस्तु का आयातक होने के कारण, उत्पादन, यदि कोई हो, को शामिल नहीं करने पर आवेदक का घरेलू उत्पादन में 27.33% हिस्सा बनता है । इसके अलावा, यह आवेदन एक प्रमुख उत्पादक जिनका समग्र उत्पादन घरेलू उद्योग के उत्पादन के 50% से अधिक अर्थात् 72.67% बनता है, द्वारा समर्थित था । पाटनरोधी नियमावली के अनुसार मै. कैमिनोवा घरेलू उद्योग माने जाने की स्थिति में है, जिनका उत्पादन कुल उत्पादन का प्रमुख हिस्सा है । हितबद्ध पक्षकार बार-बार "प्रमुख हिस्से" की बात कर रहे हैं जबकि अपेक्षा "एक प्रमुख हिस्सा" की है । यह आवेदन नियम 2(ख) के साथ पठित नियम 5(3) के अंतर्गत योग्यता की अपेक्षा को पूरा करता है । इस प्रकार आवेदक पाटनरोधी नियमावली के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग है ।

ड 4 प्राधिकारी द्वारा जांच

24. प्रारंभिक जांच परिणामों के बाद घरेलू उद्योग के दायरे और उसकी स्थिति के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा व्यक्त विचारों/अनुरोधों की निम्नानुसार जांच की गई है:

- (i) घरेलू उद्योग के रूप में मै0 कैमिनोवा इंडिया लि0 की पात्रता के संबंध में यह पाया गया कि सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतदपश्चात् पाटनरोधी नियमावली कहा गया है) के नियम 5 (3) के साथ पठित नियम 2 (ख) के अनुसार प्राधिकारी द्वारा यह जांच किया जाना अपेक्षित है कि क्या आवेदन घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से दायर किया गया है ।

पाटनरोधी नियमावली के 2 (ख) में निम्नानुसार उल्लेख है:-

" घरेलू उद्योग " का तात्पर्य समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न समूचे घरेलू उत्पादकों या ऐसे उत्पादकों से है, जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक प्रमुख भाग बनता है, परन्तु जब ऐसे उत्पादक आरोपित

पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं तो ऐसे मामले में ऐसे उत्पादकों को घरेलू उद्योग का एक भाग नहीं माना जाएगा;

नियम 2(ख) में दिनांक 27 फरवरी, 2010 की अधिसूचना सं. 18-2010-सी.शु. (एन टी) द्वारा आगे और संशोधन किया गया है जो निम्नानुसार है:

"घरेलू उद्योग" का तात्पर्य समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न समूचे घरेलू उत्पादकों या ऐसे उत्पादकों से है, जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक प्रमुख भाग बनता है, परन्तु जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं; ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" शब्दों का अर्थ केवल शेष उत्पादकों के संदर्भ में किया जा सकता है।

पाटनरोधी नियमावली के नियम 5 (3) में निम्नानुसार प्रावधान है:

"निर्दिष्ट प्राधिकारी उप नियम (1) के तहत दायर किए गए आवेदन के अनुसार तब तक जाँच की शुरुआत नहीं करेंगे जब तक कि:-

(क) वे समान वस्तु के घरेलू उत्पादकों द्वारा दिए गए आवेदन के समर्थन अथवा विरोध के स्तर की जाँच के आधार पर यह निर्धारण न कर लें कि आवेदन घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से किया गया है;

परन्तु यह कि किसी जाँच की शुरुआत नहीं की जाएगी यदि आवेदन का स्पष्ट रूप से समर्थन करने वाले घरेलू उत्पादकों का हिस्सा घरेलू उद्योग द्वारा किए गए समान वस्तु के कुल उत्पादन के पच्चीस प्रतिशत से कम हो, और

(ख) वे आवेदन में प्रदत्त साक्ष्य की सटीकता और समुचितता की जाँच करेंगे और निम्नलिखित के संबंध में स्वयं को संतुष्ट करेंगे -

- (i) पाटन,
- (ii) क्षति, जहाँ भी लागू हो; और
- (iii) जाँच शुरुआत का औचित्य सिद्ध करने के लिए जहाँ भी लागू हो, ऐसे पाटित आयातों तथा कथित क्षति के बीच कारणात्मक संबंध।

व्याख्या - इस नियम के प्रयोजनार्थ आवेदन को घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से दायर माना जाएगा यदि वह उन घरेलू उत्पादकों द्वारा समर्थित हो जिनका सामूहिक उत्पादन घरेलू उद्योग के

उस हिस्से, जो यथास्थिति आवेदन का समर्थन अथवा विरोध कर रहा हो, द्वारा उत्पादित समान वस्तु के कुल उत्पादन के 50 प्रतिशत से अधिक हो ।"

- (ii) जांच शुरुआत से पहले सबके विचार जानने की अपेक्षा के संबंध में प्राधिकारी यह समुक्ति करते हैं कि जांच की शुरुआत से पहले सबके विचार जानने की कोई निर्धारित विधिक अपेक्षा नहीं है और न ही हितबद्ध पक्षकार ने यह सिद्ध किया है कि इस मामले में ऐसी प्रक्रिया अपनाना क्यों आवश्यक या वांछनीय है । हितबद्ध पक्षकार अब तक इस तथ्य को सिद्ध नहीं कर पाया है कि यह याचिका किसी भी स्तर पर स्थिति संबंधी अपेक्षा को पूरा नहीं करती है । यह भी नोट करना महत्वपूर्ण है कि जांच की शुरुआत के समय प्राधिकारी के लिए विस्तृत पड़ताल करना अपेक्षित होता है । प्राधिकारी के लिए जांच की शुरुआत के समय केवल प्रथम दृष्टया स्वयं को इस बात से संतुष्ट करना अपेक्षित होता है कि क्या नियम 5(3) के अंतर्गत निर्धारित अपेक्षाएं पूरी हो गई हैं । संबंधित प्रशासनिक विभागों से सूचना एकत्र करने, डीजीसीआईएंडएस से आयात संबंधी आंकड़े और सीमाशुल्क से आंकड़े एकत्र करने समेत विभिन्न मापदंडों के संबंध में विभिन्न स्रोतों के माध्यम से सूचना का सत्यापन विस्तृत जांच का मुद्दा है ।
- (iii) यह देखा गया है कि वर्तमान मामले में आवेदक कंपनी का घरेलू उत्पादन में 27.33% हिस्सा है जिसमें मै. सबैरो आर्गेनिक्स, जिन्होंने जांच का उत्तर नहीं दिया है, के उत्पादन यदि कोई हो, को शामिल नहीं किया गया है । यह आवेदन स्वयं आवेदन किए जाने के समय एक अन्य प्रमुख उत्पादक मै. एक्सल इंडस्ट्रीज लि. द्वारा समर्थित है । इसके अलावा, डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों के अनुसार मै. सबैरो आर्गेनिक्स ने जांच अवधि के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु की भारी मात्रा का आयात किया है ।
- (iv) संबंधित प्रशासनिक विभाग से घरेलू उत्पादकों और मै. सबैरो आर्गेनिक समेत उनके उत्पादन के बारे में ब्यौरे उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था । रसायन और पेट्रो रसायन विभाग ने केवल मै. केमिनोवा और मै. एक्सल इंडस्ट्रीज के बारे में सूचना उपलब्ध कराई थी । दूसरे शब्दों में इस उत्पाद के संबंध में भारत सरकार के संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना में भी मै. सबैरो आर्गेनिक्स को एक उत्पादक के रूप में शामिल नहीं किया गया है । इस सूचना से इस संबंध में आवेदक द्वारा उनके आवेदन में प्रस्तुत की गई सूचना की पुनः पुष्टि हो गई । जांच शुरुआत के पश्चात मै. सबैरो आर्गेनिक्स से भी उनका उत्तर प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था । परंतु अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया गया है । आगे यह भी समुक्ति की गई है कि आवेदक द्वारा किए गए यह अनुरोध कि मै. सबैरो आर्गेनिक्स ने उत्पादन में कटौती कर दी है या उत्पादन रोक दिया है और अब वह आयात कर रहा है और वह उत्पाद की आबद्ध रूप से

खपत कर रहा है, का भी कोई खंडन प्राधिकारी के समक्ष मै. सबैरो आर्गेनिक्स द्वारा नहीं किया गया है।

(V) यह तर्क भी सही नहीं है मै0 कैमिनोवा ने आवेदन के अगोपनीय रूपांतर में डेनमार्क स्थित अपनी मूल कंपनी के साथ अपने संबंध को छिपाया था। वास्तव में डेनमार्क में स्थित मूल कंपनी से संबंध से जुड़े तथ्यों को छिपाया नहीं गया था। प्राधिकारी ने जाँच शुरुआत से पहले विशेष रूप से इस संबंध में सूचना माँगी थी और आवेदक द्वारा तथ्य प्रस्तुत किए गए थे।

(vi) यह आरोप लगाया गया है कि मै. कैमिनोवा के पास संबद्ध वस्तु की आबद्ध खपत है, और निर्धारित कानून के अनुसार आबद्ध खपत को जाँच शुरुआत पूर्व निर्धारण के समय शामिल नहीं किया जा सकता है। यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदन के अगोपनीय अंश में संबद्ध वस्तु की आबद्ध खपत के ब्यौरे प्रस्तुत करने में मै. कैमिनोवा की विफलता उन्हें घरेलू उद्योग बनाए जाने से अयोग्य ठहराती है। तथापि, घरेलू उद्योग के आंकड़ों का पहले ही सत्यापन किया गया है और प्राधिकारी यह समुक्ति करते हैं कि :- सर्वप्रथम मै. कैमिनोवा ने सार्वजनिक फाइल में उपलब्ध आवेदन के अगोपनीय अंश समेत प्रारूप IV-क के अंतर्गत अपनी याचिका में अपनी आबद्ध खपत घोषित की है। दूसरी ओर यह नोट किया जाता है कि इस कंपनी की आबद्ध खपत काफी नगण्य है जो लगभग *** मी.ट. है तथा जो घरेलू उद्योग के कुल उत्पादन का लगभग 1% है। तीसरी बात यह है कि यदि आबद्ध खपत की मात्रा को बाहर रखा जाए तो भी शेष मात्रा 26.53% बनती है और इस प्रकार इससे उनकी स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

(vii) यह अनुरोध कि मै. कैमिनोवा डेनमार्क, जो मै. कैमिनोवा इंडिया लि. की मूल कंपनी है, द्वारा भारत को किए गए निर्यात से कैमिनोवा इंडिया को अयोग्य ठहराया जा सकता है, गलत है। मूल कंपनी द्वारा किए गए निर्यात संबद्ध देश अर्थात् चीन जन.गण. से नहीं किए गए थे और न ही उनकी मात्रा अधिक थी और न वे कम कीमतों पर थे। चूंकि आयात तीसरे देशों से हुए थे, इसलिए सर्वप्रमुख बात यह है कि इन आयातों को "पाटित वस्तु" नहीं माना जा सकता है। नियमावली का नियम 2(ख) घरेलू उद्योग को परिभाषित करता है। यह बताने के बाद कि घरेलू उद्योग का अर्थ क्या है, अर्थात् समग्र रूप से घरेलू उत्पादक या संबद्ध वस्तु का जिनका समग्र उत्पादन कुल घरेलू उत्पादन का एक प्रमुख हिस्सा हो, घरेलू उत्पादकों की कतिपय श्रेणियों को इससे बाहर रखा गया है। इससे बाहर रखी गई श्रेणियों में ऐसे घरेलू उत्पादक हैं, जो कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों से संबंधित हैं, जो कथित पाटित वस्तु के आयातकों से संबंधित हैं या जो स्वयं कथित पाटित वस्तु के आयातक हैं। इसलिए विचारार्थ उत्पन्न होने वाला मुद्दा यह है कि कथित पाटित वस्तु का दावरा क्या है। घरेलू उत्पादकों का समूह जो कथित पाटित वस्तु का आयातक है या जो कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों से संबंधित है या जो कथित पाटित वस्तु के आयातकों से संबंधित है, को इस प्रावधान के अंतर्गत

पृथक् माना जा सकता है । ऐसे घरेलू उत्पादक जो स्वयं आयातक हैं, का अर्थ ऐसे घरेलू उत्पादक होना चाहिए जो संबद्ध देश से कथित पाटित वस्तु के स्वयं आयातक हैं । दूसरे शब्दों में घरेलू उत्पादक जो संबद्ध देश से कथित पाटित वस्तु के आयातक नहीं हैं, को "घरेलू उद्योग" की परिभाषा से बाहर रखा जाए ।

- (viii) यह तर्क दिया गया है कि एक्सल इंडस्ट्रीज लि. ने जांच शुरुआत के बाद सूचना उपलब्ध कराई है और उसे इस जांच हेतु प्राधिकारी द्वारा स्वीकार या उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है । प्राधिकारी यह समुक्ति करते हैं कि मै. एक्सल इंडस्ट्रीज लि. ने जांच की शुरुआत के समय मै. कैमिनोवा इंडिया लि. द्वारा दायर याचिका का खुले तौर पर समर्थन किया है । नियम 6(4) के अंतर्गत प्राधिकारी ने निर्यातकों, विदेशी उत्पादकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों सहित विभिन्न ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों से निर्धारित प्रारूप और ढंग से सूचना मंगाने के लिए नोटिस जारी किया था । यह सूचना उन पक्षकारों द्वारा दी जानी अपेक्षित होती है । नियम 2(ग) में हितबद्ध पक्षकार को परिभाषित किया गया है और उसमें भारत में समान वस्तु के उत्पादक या कोई व्यापारी और व्यापारिक एसोसिएशन, जिसके अधिकांश सदस्य भारत में समान वस्तु का उत्पादन करते हों, शामिल हैं । इस प्रकार प्राधिकारी के लिए संबद्ध वस्तु के अन्य भारतीय उत्पादकों से सूचना मंगाना अपेक्षित होता है जो याचिका में पक्षकार नहीं हों । ऐसे मामले में इस तर्क का कोई न्यायसंगत आधार नहीं है कि प्राधिकारी को ऐसी किसी कंपनी से सूचना नहीं मंगानी चाहिए जिसका भारतीय उत्पादन में प्रमुख हिस्सा हो । वह भी एक ऐसी जांच में जहां विचाराधीन उत्पाद केवल 3 उत्पादकों द्वारा उत्पादित किया जा रहा है । वस्तुतः जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना की एक प्रति मै. सबैरो आर्गेनिक्स को भी भेजी गई थी । तथापि, उन्होंने प्राधिकारी को उत्तर नहीं दिया ।

- (ix) रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के पठन और उसके सत्यापन के पश्चात यह नोट किया जाता है कि एक्सल इंडस्ट्रीज लि., मुंबई (आवेदन का समर्थक) ने संपूर्ण संगत अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु का आयात नहीं किया है । इसके अलावा, इस कंपनी के पास अनेक संबंधित कंपनियां हैं । एक्सल इंडस्ट्रीज ने इस बात से इंकार किया है कि उसकी किसी भी संबंधित कंपनी ने संगत अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है । तथापि, एक्सल इंडस्ट्रीज लि. द्वारा प्रदत्त सूचना से यह पता चलता है कि एक्सल क्राफ्ट केयर लि. एक सामूहिक कंपनी है और डी ई टी पी सी की खपत करती है । डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों से यह नोट किया जाता है कि एक्सल क्राफ्ट केयर ने कुल 9335 मी.ट. के कुल भारतीय उत्पादन, 20285 मी.ट. की मांग और 12361 मी.ट. के आयातों के मुकाबले जांच-अवधि के दौरान केवल *** मी.ट. डी ई टी पी सी का आयात किया है । किसी भी दृष्टि से इस कंपनी द्वारा आयात की गई मात्रा काफी मामूली है जो भारतीय उत्पादन के 1% से भी कम है ।

- (X) प्राधिकारी ने नियम 2(ख) के अंतर्गत मै. एक्सल इंडस्ट्रीज लि. को पात्र घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर रखने की संभावना पर भी विचार किया है। तथापि, प्राधिकारी ने यह देखा है कि यदि मै. एक्सल इंडस्ट्रीज लि. को घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर रखा जाता है तो उस मामले में कैमिनोवा का हिस्सा पात्र घरेलू उत्पादन का 100% हो जाएगा क्योंकि अन्य कथित उत्पादक मै. सबैरो आर्गेनिक्स जांच अवधि के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के अपने भारी आयातों के कारण अयोग्य ठहरा दिया गया है और उसने प्राधिकारी के साथ सहयोग नहीं किया है।
25. उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकारी मानते हैं कि एक्सल क्राप केयर द्वारा किए गए आयात नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग के रूप में एक्सल इंडस्ट्रीज लि. की स्थिति को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करते हैं। प्राधिकारी ने दिनांक 27 फरवरी, 2010 की अधिसूचना सं. 18-2010-सी.शु.(एन टी) द्वारा यथासंशोधित नियम 2(ख) को भी नोट किया है। प्राधिकारी ने इस बात की जांच की है कि क्या उपर्युक्त निष्कर्ष वर्तमान विधिक प्रावधानों पर विचार करते हुए भिन्न हो सकता था। प्राधिकारी मानते हैं कि एक्सल इंडस्ट्रीज को संशोधित नियम 2(ख) के अंतर्गत भी पात्र घरेलू उद्योग माना जा सकता है।
26. प्रकटन के बाद हितबद्ध पक्षकारों ने याचिकाकर्ता की स्थिति संबंधी कमी के संबंध में अपने तर्कों को दोहराया है। इस मुद्दे पर प्राधिकारी द्वारा प्रारंभिक जांच परिणामों और प्रकटन विवरण में भी काफी विचार किया गया था। उन्होंने तर्क दिया है कि एक्सल इंडस्ट्रीज के संबंध में प्राधिकारी द्वारा ज्ञात तथ्यों के निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण हैं और इसके अलावा, इन तथ्यों का निष्कर्ष कार्रवाई के अंतिम स्तर पर निकाला गया है। इस संबंध में यह बताया गया है कि यदि नियम 2(ख) के अंतर्गत एक्सल इंडस्ट्रीज को अपात्र माना जाता है तो वर्तमान याचिका प्रस्तुत करने की याचिकाकर्ता की योग्यता कम से कम, बढ़ जाएगी जैसा कि प्रकटन विवरण में दर्शाया गया है। अतः चाहे एक्सल इंडस्ट्रीज को जांच की शुरुआत के समय पात्र अथवा अपात्र माना जाए या नहीं, उससे वर्तमान निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जांच शुरुआत के बाद चूंकि एक्सल इंडस्ट्रीज ने संगत सूचना उपलब्ध कराई है और इसके अलावा, चूंकि नियम 2(ख) में घरेलू उत्पादकों को समग्र रूप से घरेलू उद्योग मानने की व्यवस्था है; और केवल सभी घरेलू उत्पादकों की गैर-मौजूदगी में ही कानून में घरेलू उद्योग के रूप में एक प्रमुख हिस्सा मानने की अनुमति दी गई है। इसलिए प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणामों के स्तर पर कैमिनोवा और एक्सल को घरेलू उद्योग माना है।
27. हितबद्ध पक्षकारों ने यह भी तर्क दिया है कि संगत नियम ने ऐसे उत्पादकों के उत्पादन को शामिल नहीं करने की अनुमति नहीं दी गई है जो घरेलू उद्योग का हिस्सा नहीं हों। ऐसा इन शब्दों के प्रयोग के कारण है कि "कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा"। तथापि, उन्होंने इस परिभाषा के शेष भाग की बिल्कुल अनदेखी कर दी है जिसमें यह व्यवस्था है कि यदि कोई उत्पादक कथित पाटित वस्तु के निर्यातकों या

आयातकों से संबंधित है या स्वयं इनका आयातक है तो ऐसे मामले में उस उत्पादक को घरेलू उद्योग का हिस्सा नहीं माना जाएगा। इसके अलावा, यद्यपि, प्राधिकारी ने नियम 5 के अंतर्गत स्थिति के संदर्भ में इस मुद्दे का संदर्भ दिया है तथापि, वे इसका संदर्भ घरेलू उद्योग की परिभाषा के संबंध में दे रहे हैं। नियम 5(3) में यह व्यवस्था है कि आवेदन घरेलू उद्योग द्वारा या उनकी ओर से किया जाएगा। यदि वह ऐसे घरेलू उत्पादकों द्वारा समर्थित है जिनका समग्र उत्पादन समान वस्तु के कुल उत्पादन के 50% से अधिक बनता है जो आवेदन का समर्थन या विरोध करने वाले घरेलू उत्पादकों, जैसा भी मामला हो, का हिस्सा हो। नियम 5(3) के इसी संदर्भ में प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यदि एक्सल इंडस्ट्रीज को अयोग्य माना जाता है तो मै. कैमिनोवा का उत्पादन 100% हो जाएगा।

28. उपर्युक्त संदर्भ में प्रकटन के बाद हितबद्ध पक्षकारों ने यह आरोप लगाया है कि प्राधिकारी ने आयातों की भारी मात्रा पर विचार करने के लिए भिन्न-भिन्न मामलों में भिन्न-भिन्न मानक लागू किए हैं। उन्होंने बताया है कि वर्तमान मामले में प्राधिकारी ने आयातों की भारी मात्रा की जांच कुल उत्पादन के प्रतिशत के रूप में करने का प्रस्ताव किया है जबकि विस्कोस फिलामेंट यार्न के मामले में संबंधित देश से कुल आयातों के % के रूप में इसी जांच को लागू किया गया है जो कि पूर्णतः विरोधी दृष्टिकोण हैं। तथापि, प्राधिकारी यह समुक्ति करते हैं कि वर्तमान मामले में सभी 3 संभावित मापदंडों अर्थात् कुल आयात, उत्पादन और खपत की दृष्टि से आयातों का काफी कम प्रतिशत बनता है।

29. संबद्ध वस्तु के संबंध में पाटनरोधी जाँच की शुरुआत के विरुद्ध मै0 मेघमणि ऑर्गेनिक्स लि0, अहमदाबाद और अन्य हितबद्ध पक्षकारों की ओर से किए गए अनुरोधों तथा मौजूदा मामले में पाटनरोधी जाँच की शुरुआत के समर्थन में घरेलू उद्योग की ओर से किए गए अनुरोधों की विस्तृत जाँच और उन पर सावधानी से विचार करने बाद और संगत नियमों तथा निर्णयों के आधार पर यह अभिमत दिया गया है कि मै0 एक्सल इंडस्ट्रीज लि0 द्वारा समर्थित मै0 कैमिनोवा इंडिया लि0 घरेलू उद्योग का हिस्सा है और प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी जाँच की शुरुआत इस संबंध में पाटनरोधी नियमावली तथा कानून के क्षेत्राधिकार के भीतर आती है।

च. गोपनीयता का मुद्दा

च.1 आयातकों के विचार

30. प्रारंभिक जांच परिणामों के बाद मै. गर्दा कैमिकल लि., मेघमणि आर्गेनिक्स लि., सिरिस क्रॉप साइंसेज लि. और पी आई इंडस्ट्रीज लि. का प्रतिनिधित्व करते हुए मै. ए पी जे- एस एल जी, लॉ आफिसेज ने प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अनुरोधों में दी गई सूचना की गोपनीयता को विवादित ठहराया है। उन्होंने प्रारंभिक जांच परिणामों में प्राधिकारी द्वारा कतिपय सूचना का खुलासा नहीं किए जाने पर भी प्रश्न उठाया है और

प्रकटन के बाद की अपनी टिप्पणियों में इन मुद्दों को दोहराया है । उनके तर्क संक्षेप में निम्नानुसार हैं :-

क) निर्दिष्ट प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य परिकलित करने के लिए प्राप्त आंकड़ों और सूचना का प्रकटन नहीं किया है जबकि सभी प्रमुख निविष्टियों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों संबंधी संगत आंकड़ों को गोपनीय नहीं रखा जा सकता है। प्राधिकारी द्वारा जब सामान्य मूल्य का परिकलन किया गया था तो उक्त प्राधिकारी को इस संबंध में गोपनीयता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है ।

ख) हमें अन्य भागीदार पक्षकारों द्वारा प्रश्नावली के उत्तर के अगोपनीय अंश आ अवलोकन भी नहीं करने दिया गया है जो हम मानते हैं कि सार्वजनिक फाइल का हिस्सा होना चाहिए था । निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेजों की प्रतियां हमें उपलब्ध कराई जानी चाहिए । गोपनीय दस्तावेजों के मामले में नियम 6(7) के अनुसार अगोपनीय अंश उपलब्ध कराया जाना चाहिए ।

ग) नियम 6(7) की अपेक्षाओं के विपरीत हमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों के लिखित अनुरोधों की प्रतियां तब भी उपलब्ध नहीं कराई गई हैं जबकि इन हितबद्ध पक्षकारों ने उनके संबंध में गोपनीयता का दावा नहीं किया है ।

घ) माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी को गुजरात उच्च न्यायालय की माननीय बेंच के दिनांक 9.10.2009 के आदेशों के अनुसार विस्तृत सूचना उपलब्ध करानी चाहिए और सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपना मामला प्रस्तुत करने का अवसर पुनः देना चाहिए ।

ङ) हितबद्ध पक्षकारों ने विभिन्न पत्रों में कतिपय सूचना/दस्तावेज/आंकड़े मांगे थे । जांच के इस स्तर पर भी उक्त सूचना को अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है और वे इन अनिवार्य दस्तावेजों की प्राप्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं । इसके मद्देनजर ये हितबद्ध पक्षकार पूर्ण और सार्थक प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने में अक्षम हैं ।

च) हितबद्ध पक्षकारों ने प्राधिकारी से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने और जांच में प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेजों का अवलोकन करने की अनुमति देने का अनुरोध किया है । किसी भी तरह से इन जांच परिणामों तक पहुंचने के लिए आधार माने गए दस्तावेजों को हितबद्ध पक्षकारों से छुपाया नहीं जा सकता है और उन्हें सार्वजनिक फाइल में उपलब्ध कराया जाना या रखा जाना चाहिए ।

छ) घरेलू उद्योग ने यह आरोप लगाया है कि प्रतिवादी निर्यातकों ने प्रश्नावली का ऐसा उत्तर प्रस्तुत किया है जो बिल्कुल अधूरा है और निर्यातकों ने अत्यधिक गोपनीयता

का दावा किया है । इसके विपरीत हमने नोटिस किया है कि घरेलू उद्योग ने अपने पूरे आवेदन में अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है । इसके अलावा, इसके बाद के समस्त अनुरोध/आंकड़े/सूचना नियम 7 के विपरीत हैं ।

ज) ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान मामले में गोपनीयता के दावों की निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा सूचना की प्रकृति की जांच किए बिना स्वतः ही अनुमति दे दी गई है ।

च.2 निर्यातकों/उद्योग एसोसिएशन के विचार

31. प्रारंभिक जांच परिणामों के बाद मै. यांगजिन चेनटियांग कैमिकल इंडस्ट्रीज लि., झेजियांग जिनांग कैमिकल कं. लि. और चाइना क्राफ प्रोटक्शन इंड एसो. का प्रतिनिधित्व करने वाले मै. दुवा एसो. ने गोपनीयता के मुद्दे पर निम्नलिखित विचार व्यक्त किए हैं और उन्हें प्रकटन के बाद दोहराया है :-

- क) प्राधिकारी द्वारा उनके निष्कर्षों का आधार मानी गई संगत सूचना को प्रकट नहीं किया जाना पारदर्शिता की अपेक्षाओं के विरुद्ध है और प्राकृतिक न्याय के नियमों के विरुद्ध है ।
- ख) सामान्य मूल्य, पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन तथा उनमें की गई गणनाओं के घटकों जैसे महत्वपूर्ण मापदंडों को प्रकट नहीं किया जाना प्राकृतिक न्याय के नियम और पारदर्शिता की अपेक्षाओं के विरुद्ध है तथा यह पाटनरोधी नियमावली के नियम 12 और पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 6 के भी विपरीत है । जैसा कि बिरला एरीक्शन के मामले में निर्धारित किया गया है, माननीय प्राधिकारी द्वारा इन सभी गणनाओं का खुलासा किया जाना चाहिए ।
- ग) क्षति रहित कीमत और पहुंच कीमत की गणनाओं सहित सामान्य मूल्य, पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के ब्यौरों का खुलासा नहीं किए जाने से चीन के उत्पादकों/निर्यातकों के प्रतिवाद के अधिकार पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन है ।
- घ) प्रारंभिक जांच परिणामों और उनके बाद भी अनुरोध किए जाने के बावजूद माननीय प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य, पाटन और क्षति मार्जिन संबंधी संगत सूचना का खुलासा नहीं किया है जिससे चीन के उत्पादकों/निर्यातकों की उत्तर देने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ।
- ङ) प्रमुख निविष्टियों के संबंध में सामान्य मूल्य से संबंधित ऐसी किसी सूचना का खुलासा नहीं किया गया है जिस पर विचार किया गया हो जैसे अंतर्राष्ट्रीय

कीमतों का स्रोत प्रत्येक निविष्टि की कीमत, परिवर्तन लागत, प्रयुक्त एस जी ए व्यय और लाभ मार्जिन ।

- च) निर्दिष्ट प्राधिकारी ने इस बात का अवलोकन करने में गलती की है कि प्राधिकारी द्वारा निकाला गया निष्कर्ष चूंकि गोपनीय सूचना पर आधारित है, इसलिए गोपनीय है । गोपनीय आंकड़े और उनसे प्राप्त निष्कर्ष को कम से कम उस संबंधित उत्पादक/निर्यातक को प्रकट किया जा सकता है जिनसे ये आंकड़े संबंधित हैं ।

32. प्रारंभिक जांच परिणामों के बाद मै. सेठ एसोसिएट्स ने मै. लियानयुन गैंग लिबेन एग्रो-कैमिकल कं. लि. और जिगताई पेस्टीसाइड कं. लि. की ओर से यह अनुरोध किया है कि प्राधिकारी ने इस संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई है कि विचाराधीन उत्पाद के सामान्य मूल्य का परिकलन कैसे किया गया है। कच्ची सामग्री की लागत, परिवर्तन लागत, एस जी ए व्यय और वित्त लागत तथा लाभ मार्जिन की राशि संबंधी सूचना भी नहीं दी गई है। परिकलित सामान्य मूल्य को गोपनीय माना गया है, जिससे हमारे मुवक्किल द्वारा इस गणना पर टिप्पणी करने और प्राधिकारी के निर्णय का खंडन किए जाने में मुश्किल हुई है । प्रकटन के बाद उपर्युक्त हितबद्ध पक्षकारों से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है ।

च.3 घरेलू उद्योग के विचार

33. प्रारंभिक जांच परिणामों के बाद घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रश्नावली के उनके उत्तर के अगोपनीय अंश में दी गई सूचना बिल्कुल अधूरी है और उससे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की जानकारी मिलने की कोई तर्कसंगत समझ विकसित नहीं हो सकती है । उत्पादकों/निर्यातकों ने किसी भी परिशिष्ट का सूचीबद्ध अंश प्रस्तुत नहीं किया है । इन पर गोपनीयता का दावा करने का कोई कारण नहीं बताया गया है ।

च.4 प्राधिकारी द्वारा जांच

34. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के गोपनीयता के दावे की जांच की है । प्रारंभिक जांच परिणामों में क्षमता, उत्पादन और बिक्री की मात्रा से संबंधित घरेलू उद्योग के आंकड़े तथा आयात आंकड़ों को गोपनीय नहीं रखा गया है । उपभोक्ताओं, लागत कीमतों के संबंध में घरेलू उद्योग के आंकड़े तथा ऐसे आंकड़े जिनसे उनके प्रतिस्पर्धियों को प्रतिस्पर्धी लाभ मिल सकता है, को गोपनीय रखा गया है ।
35. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों की जांच करने के बाद यह समुक्ति की है कि सामान्य मूल्य की गणना की पद्धति का खुलासा प्रारंभिक जांच परिणामों में किया गया है ।

36. प्राधिकारी ने नियम 6(7) के अनुसार विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय अंश वाली सार्वजनिक फाइल को निरीक्षण के लिए, अनुरोध करने पर सभी हितबद्ध पक्षकारों के लिए उपलब्ध रखा था । जहां तक हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए लिखित अनुरोधों की प्रतिलिपि उपलब्ध कराने का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इन अनुरोधों को भी सार्वजनिक फाइल में उपलब्ध कराया गया है ।
37. गोपनीयता के मुद्दों के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों के तर्क और (क) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदत्त कतिपय सूचना और (ख) प्रारंभिक जांच परिणामों में प्राधिकारी द्वारा आधार मानी गई सूचना के प्रकटन संबंधी विशिष्ट अनुरोधों, जिसके लिए मै. मेघमणि आर्गेनिक्स लि. द्वारा दायर की गई एक रिट याचिका सं. 6881/2009 पर माननीय गुजरात उच्च न्यायालय की बेंच ने दिनांक 9 अक्टूबर, 2009 को एक विस्तृत आदेश दिया था, जिसमें कतिपय सूचना को प्रकट करने का निर्देश दिया गया था । निर्दिष्ट प्राधिकारी ने 2010 की विशेष अनुमति याचिका सं. 887 के द्वारा और घरेलू उद्योग (मै. कैमिनोवा इंडिया लि. ने 2009 की विशेष याचिका सं. 34374 द्वारा और मै. एक्सल इंडस्ट्रीज लि. ने 2009 की विशेष अनुमति याचिका सं. 35243 द्वारा) ने पृथक रूप से गुजरात उच्च न्यायालय की माननीय बेंच के दिनांक 9.1.2009 के आदेश को माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष चुनौती दी थी । पक्षकारों की सुनवाई के बाद माननीय उच्चतम न्यायालय ने 8 फरवरी, 2010 के अपने आदेश द्वारा इन विवादित आदेशों पर रोक प्रदान की थी ।
38. तब जबकि रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा गुजरात उच्च न्यायालय के माननीय बेंच के समक्ष दिए गए तर्क माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अब न्यायिक निर्णयाधीन हैं, प्राधिकारी ने विभिन्न रिट याचिकाओं में दिए गए विभिन्न तर्कों पर विचार किया है, उनकी जांच की है और वर्तमान जांच परिणामों में उन पर ध्यान दिया है ।
39. अनेक पक्षकारों ने निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष यह दावा करते हुए अभ्यावेदन किया है कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए गोपनीयता के दावे अनुचित हैं या प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के गोपनीयता संबंधी दावों को गलत ढंग से स्वीकार किया है । गुजरात और दिल्ली उच्च न्यायालय की माननीय बेंच के समक्ष प्रस्तुत की गई रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं ने निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रारंभिक जांच परिणामों में विभिन्न आंकड़ों/सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा गोपनीयता के आधारों को चुनौती दी है । गुजरात उच्च न्यायालय की माननीय बेंच ने प्रारंभिक जांच परिणाम दर्ज करते समय रिक्त रखी गई सूचना को प्रकट करने का आदेश दिया है जो निम्नानुसार हैं:

क) सामान्य मूल्य से संबंधित सूचना -

- (i) तर्कसंगत लाभ मार्जिन
- (ii) कारखाना द्वार लागत ब्याज को छोड़कर
- (iii) कच्ची सामग्री की लागत
- (iv) परिवर्तन लागत
- (v) एस जी ए व्यय
- (vi) सामान्य मूल्य

ख) निर्यात कीमत से संबंधित सूचना :-

- (i) निर्यात मात्रा
- (ii) प्रति इकाई सीआईएफ निर्यात कीमत
- (iii) कीमत समायोजन
- (iv) समुद्री भाड़ा
- (v) अंतरदेशीय भाड़ा
- (vi) अन्य अनुषंगी शुल्क
- (vii) ऋण लागत
- (viii) बैंक प्रभार

ग) क्षति से संबंधित सूचना-

- (i) बिक्री कीमत
- (ii) कीमत कटौती
- (iii) संपूर्ण क्षति अवधि के लिए बिक्री की लागत
- (iv) आयातों की पहुंच कीमत
- (v) क्षतिरहित कीमत
- (vi) भिन्न-भिन्न निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन
- (vii) कम कीमत पर बिक्री
- (viii) संपूर्ण क्षति अवधि के लिए जी एफ ए तथा एन एफ ए आधार पर नियोजित पूंजी पर आय
- (ix) संपूर्ण क्षति अवधि के लिए नकद प्रवाह
- (x) संपूर्ण क्षति अवधि के लिए नकद लाभ
- (xi) संपूर्ण क्षति अवधि के लिए निर्यात मात्रा

40. हितबद्ध पक्षकारों के विभिन्न तर्कों, गुजरात उच्च न्यायालय की माननीय बेंच के आदेशों, भारतीय पाटनरोधी नियमों और डब्ल्यू टी ओ पाटनरोधी करार के अंतर्गत विधिक प्रावधानों की ध्यानपूर्वक जांच करने के बाद और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर विचार करते हुए प्राधिकारी निम्नानुसार समुक्ति करते हैं:-

क) पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 में किसकी सूचना की गोपनीयता के संबंध में निम्नानुसार व्यवस्था है:-

गोपनीय सूचना. (1) नियम 6 के उप-नियम (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उप नियम (4) और नियम 17 के उप नियम (4) में अंतर्विष्ट प्रावधानों के होते हुए भी नियम 5 के उप नियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों और जांच की प्रक्रिया में किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रदान की गई किसी अन्य सूचना की प्रतियों को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उनकी गोपनीयता से संतुष्ट हो जाने पर गोपनीय माना जाएगा और ऐसी किसी सूचना का प्रकटन उस सूचना को प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार के समक्ष नहीं किया जाएगा ।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उनका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने की अपेक्षा रख सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रदान करने वाले किसी पक्षकार की राय में वह सूचना सारांश योग्य नहीं है तो उस पक्षकार को निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष सूचना का सारांश नहीं हो सकने के कारणों संबंधी एक विवरण प्रस्तुत करना होगा ।

(3) उप नियम (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता संबंधी अनुरोध अनावश्यक है या उस सूचना को देने वाला सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या सामान्य अथवा सारांश-रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत नहीं करता है तो प्राधिकारी ऐसी सूचना पर गौर नहीं करेंगे ।

ख) पाटनरोधी संबंधी डब्ल्यू टी ओ करार में सूचना की गोपनीयता के संबंध में निम्नानुसार व्यवस्था है :-

अनुच्छेद-6.5 कोई सूचना जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है (उदाहरणार्थ क्योंकि उसके प्रकटन से किसी प्रतिस्पर्धी को प्रतिस्पर्धा संबंधी भारी लाभ हो जाएगा या क्योंकि उसके प्रकटन से सूचना देने वाले व्यक्ति या उस व्यक्ति जिससे उसने सूचना प्राप्त की है, पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा), या जो किसी जांच के पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई है, को पर्याप्त कारण बताए जाने पर प्राधिकारियों द्वारा गोपनीय माना जाएगा । ऐसी सूचना को उसे प्रस्तुत करने वाले पक्षकार की विशिष्ट अनुमति के बिना प्रकट नहीं किया जाएगा ।

अनुच्छेद-6.5.1 प्राधिकारी गोपनीय सूचना प्रदान करने वाले हितबद्ध पक्षकारों से उनका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेंगे । इन सारांशों में ऐसे पर्याप्त ब्यौरे होंगे जिनसे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के अर्थ की तर्कसंगत समझ प्राप्त हो सके । आपवादिक परिस्थितियों में ऐसे पक्षकार बता सकते हैं कि उस सूचना

का सारांश नहीं हो सकता है। ऐसी आपवादिक परिस्थितियों में सारांश नहीं किए जा सकने के कारणों संबंधी एक विवरण अवश्य प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

अनुच्छेद-6.5.2 यदि प्राधिकारी पाते हैं कि गोपनीयता संबंधी अनुरोध अनावश्यक है और यदि सूचना प्रदान करने वाला व्यक्ति उस सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या सामान्य अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत नहीं करता है तो प्राधिकारी ऐसी सूचना को नजरअंदाज कर सकते हैं। जब तक कि उचित स्रोतों से वह इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाते हैं कि यह सूचना सही है।

अनुच्छेद 6.5.2 की पाद टिप्पणी (डब्ल्यू टी ओ पाटनरोधी करार की पाद टिप्पणी 18) में निम्नानुसार व्यवस्था है :

सदस्य इस बात पर सहमत हैं कि गोपनीयता के अनुरोध को मनमाने ढंग से अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

41. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्राधिकारियों द्वारा जारी सार्वजनिक सूचनाएं प्रत्यक्ष रूप से गोपनीयता संबंधी प्रावधानों के अधीन हैं और उन्हें किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत गोपनीय सूचना का संरक्षण करना चाहिए। इसके अलावा, गोपनीय सूचना के आधार पर प्राधिकारी द्वारा निकाला गया कोई निष्कर्ष भी गोपनीय हो जाता है यदि ऐसे निष्कर्ष का खुलासा करने से किसी भी तरह से गोपनीय आधार पर प्रदत्त सूचना का वास्तविक प्रकटन होता है।

42. प्राधिकारी ने विधिक प्रावधानों और अन्य जांचकर्ता प्राधिकारियों की प्रथाओं की भी जांच की है और यह देखा कि अन्य जांचकर्ता प्राधिकारी द्वारा भी जारी की गई समान सूचना/पत्रों में जांच परिणाम जारी करते समय किसी गोपनीय सूचना को शामिल नहीं किया जाता है।

43. हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध के संबंध में कि निर्दिष्ट प्राधिकारी ने गोपनीयता के कारणों का खुलासा नहीं किया है, प्राधिकारी ने निम्नानुसार नोट किया है:-

- (ii) डब्ल्यू टी ओ पाटनरोधी करार और पाटनरोधी नियमावली में स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट किया गया है कि किस सूचना को गोपनीय सूचना माना जाना अपेक्षित है।

- (ii) प्राधिकारी मानते हैं कि कोई सूचना जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है या जो गोपनीय आधार पर प्रदान की गई है, को गोपनीय माना जाना अपेक्षित है और उसे अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट नहीं किया जा सकता है ।
- (iii) अपने पत्रों/आदेशों में कोई सूचना प्रकट करते समय प्राधिकारी के लिए यह सुनिश्चित करना अपेक्षित है कि सूचना के उस प्रकटन से किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का अंततः प्रकटन नहीं होना चाहिए । दूसरे शब्दों में यदि कोई हितबद्ध पक्षकार किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रदान की गई गोपनीय सूचना तक पहुंचने में सफल हो जाएगा तो उक्त सूचना प्राधिकारी द्वारा प्रकट नहीं की जा सकती है ।
- (iv) यद्यपि, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले हितबद्ध पक्षकारों के लिए गोपनीयता संबंधी दावे के कारण बताना अपेक्षित है, परंतु प्राधिकारी के लिए सार्वजनिक सूचना में दी गई सूचना की गोपनीयता के कारण बताना अपेक्षित नहीं है । नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी के लिए विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दावा की गई गोपनीयता के कारणों के संबंध में संतुष्ट होना अपेक्षित है ।
- v) कुछ हितबद्ध पक्षकारों ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों को प्राधिकारी द्वारा भेजे गए पत्रों की प्रतिलिपि की मांग की है । इन हितबद्ध पक्षकारों ने जांच की शुरुआत से पहले प्राधिकारी और आवेदक घरेलू उद्योग के बीच हुए पत्राचार की प्रतिलिपि की भी मांग की है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि आंकड़ों/सूचना को अनिवार्य रूप से दस्तावेजों से अलग रखना चाहिए । हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध में अनेक दस्तावेज शामिल हैं । इस अनुरोध को गुजरात उच्च न्यायालय की माननीय बेंच के समक्ष किया गया था । तथापि, गुजरात उच्च न्यायालय की माननीय डिविजन बेंच के आदेश ऐसे किसी अनुरोध को कवर नहीं करते हैं । इसके अलावा, किसी भी प्रकार से प्राधिकारी जांच की शुरुआत से पहले या उसके बाद हितबद्ध पक्षकारों के साथ प्राधिकारी द्वारा किए गए पत्राचार को उपलब्ध कराना उचित नहीं समझते हैं ।
- vi) नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी हितबद्ध पक्षकारों से दस्तावेज प्राप्त करते हैं । गोपनीयता संबंधी प्रावधान में यह व्यवस्था है कि प्राधिकारी को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का खुलासा अन्य हितबद्ध पक्षकारों के समक्ष नहीं किया जा सकता है यदि गोपनीयता का दावा अनावश्यक भी है तब भी प्राधिकारी केवल ऐसी सूचना को नजरअंदाज करने के लिए प्राधिकृत है । पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 और पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 6.5 के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए उस सूचना को गोपनीय मानना अपेक्षित है यदि वह किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई है ।

प्राधिकारी ऐसी सूचना का खुलासा या उसे सार्वजनिक करने के लिए प्राधिकृत नहीं हैं ।

- vii) अंतिम जांच परिणाम जारी करने से पहले अनिवार्य तथ्यों का खुलासा करने संबंधी प्रावधान पाटनरोधी नियमावली के नियम 16 में निर्धारित किया गया है । नियम 16 के अंतर्गत भी गोपनीय तथ्यों को "अलग-अलग हितबद्ध पक्षकारों" को प्रकट करना अपेक्षित है जबकि अगोपनीय तथ्यों को सभी हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट किया जाना अपेक्षित है । किसी भी स्तर पर निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास गोपनीय सूचना को प्रतिस्पर्धी और विरोधी हितों वाले पक्षकारों के समक्ष प्रकट करने की शक्तियां नहीं हैं । इस प्रकार यह पर्याप्त होगा यदि वास्तविक आंकड़ों का खुलासा करने के बजाए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निर्यात कीमत, सामान्य मूल्य और क्षति रहित कीमत के निर्धारण और तुलना में प्रयुक्त पद्धति के कारणों के पूरे स्पष्टीकरण का खुलासा किया जाए । सामान्य मूल्य निर्यात कीमत और क्षति रहित कीमत पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत गोपनीय सूचना पर आधारित होती है और इसके प्रकटन से किसी प्रतिस्पर्धी को भारी प्रतिस्पर्धी लाभ हो सकता है और उसके प्रकटन से सूचना देने वाले व्यक्ति पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है ।
- viii) जांच में सुविधा पहुंचाने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रदत्त वाणिज्यिक रूप से संवेदनशील और गोपनीय सूचना का भरोसे और विश्वास को ताक पर रखकर, खुलासा करने से घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय, दोनों मोर्चों पर बाजार के माहौल पर काफी बुरा प्रभाव पड़ेगा । घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत, क्षति रहित कीमत आदि से संबंधित गोपनीय सूचना के प्रकटन से उनके घरेलू तथा विदेशी प्रतिस्पर्धियों को अनावश्यक लाभ मिल जाएगा और वे उपभोक्ताओं के समक्ष हानिकारक स्थिति में पहुंच जाएंगे । इसी प्रकार सामान्य मूल्य, निवल निर्यात कीमत, पहुंच कीमत आदि से संबंधित निर्यातकों की गोपनीय सूचना के प्रकटन से उनके प्रतिस्पर्धियों तथा क्रेताओं के समक्ष उनके वाणिज्यिक हित खतरे में पड़ जाएंगे ।

44. हितबद्ध पक्षकारों ने प्राधिकारी की इस दृष्टिकोण पर भी प्रश्न उठाया है कि गोपनीय सूचना के आधार पर ज्ञात निष्कर्ष भी गोपनीय है । इसके अलावा, उन्होंने यह कहा है कि उस सूचना को कम से कम गोपनीय सूचना से संबंधित पक्षकार को तो प्रस्तुत किया ही जा सकता है । इस संबंध में यह दोहराया जाता है कि गोपनीय सूचना पर आधारित कोई निष्कर्ष वस्तुतः गोपनीय रहेगा । ऐसी किसी सूचना के खुलासे से अन्य पक्षकारों को हितबद्ध पक्षकारों की गोपनीय सूचना का पता चल जाएगा और इससे प्रदत्त गोपनीयता का मूल प्रयोजन विफल हो जाएगा । उच्चतम न्यायालय के समक्ष दायर एस एल पी में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यही दृष्टिकोण अपनाया गया है । जहां तक संबंधित हितबद्ध पक्षकार को सूचना का खुलासा किए

जाने का संबंध है, प्राधिकारी यह समुक्ति करते हैं कि उसका खुलासा पहले ही संबंधित पक्षकार को कर दिया गया है ।

छ. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए अन्य मुद्दे

(क) यह अनंतिम शुल्क लगाए जाने के लिए उपयुक्त मामला नहीं था । निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रारंभिक जांच परिणाम नियम 12 की अनिवार्य अपेक्षाओं के विपरीत हैं । रिकॉर्ड में किसी सामग्री के अभाव में ऐसे अनिवार्य निर्धारण तक पहुंचना कि ये उपाय जांच अवधि के दौरान हो रही क्षति को रोकने के लिए आवश्यक हैं, प्रारंभिक जांच परिणामों में की गई यह सिफारिश नियम 20 के साथ पठित नियम 12 और अनुच्छेद 7.1 (iii) के विरुद्ध है ।

(ख) घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त लिखित अनुरोध सही ढंग से क्रमांकित नहीं किए गए हैं, जिससे दिनांक 22 अक्टूबर, 2007 के व्यापार नोटिस सं. 1/2007 के अनुसार माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथाअपेक्षित पैरा-वार टिप्पणियां करना हितबद्ध पक्षकारों के लिए कठिन हो गया है ।

(ग) मै. एक्सल के उत्तर को सत्यता प्रमाण पत्र के समर्थन के बिना स्वीकार कर लिया गया है ।

(घ) निर्दिष्ट प्राधिकारी ने इस आशय के लिए नियम 12 के अनुसार कोई जांच परिणाम रिकॉर्ड नहीं किए हैं कि वर्तमान मामला एक उचित मामला है, जिसमें अनंतिम शुल्क का सिफारिश करने वाले प्रारंभिक जांच परिणाम जारी करना आवश्यक था ।

छ.1 प्राधिकारी द्वारा जांच

45. हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों पर कानून के अनुसार समुचित ढंग से विचार किया गया है । प्राधिकारी ने कथित पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति की प्रारंभिक स्तर पर वस्तुनिष्ठ जांच की है और पर्याप्त रूप से विस्तृत सूचना के आधार पर और पाटनरोधी नियमावली तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रारंभिक जांच परिणाम रिकॉर्ड किए गए थे । जहां तक अनंतिम पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश के सही होने का संबंध है, प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रारंभिक जांच परिणाम स्वतः स्पष्ट हैं जिसके द्वारा प्राधिकारी ने अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है ।

46. जहां तक घरेलू उद्योग द्वारा लिखित अनुरोध प्रस्तुत किए जाने की पद्धति का संबंध है, प्राधिकारी इस बात को दोहराते हैं कि ऐसी कोई निर्धारित अपेक्षा नहीं है कि किसी हितबद्ध पक्षकार को संख्यांकित पैराग्राफ के अनुसार लिखित अनुरोध प्रस्तुत करने चाहिए । किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत किए गए लिखित अनुरोध को ऐसे कारणों से नजरअंदाज/अस्वीकार नहीं किया जा सकता है और न ही इस बात को माना जा सकता है कि कोई हितबद्ध पक्षकार इस कारण से लिखित अनुरोध के संबंध में टिप्पणियां प्रस्तुत नहीं कर

सकता है क्योंकि उसके पैराग्राफ संख्यांकित नहीं हैं। प्राधिकारी द्वारा दिनांक 22 अक्टूबर, 2007 को जारी किया गया व्यापार नोटिस सं. 1/2007 में यह अपेक्षित है कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए लिखित अनुरोधों के प्रत्युत्तरों को लिखित अनुरोधों की टिप्पणियों के बिल्कुल सही पैराग्राफ के अनुसार होना चाहिए।

47. इस आरोप के संबंध में कि मै. एक्सल की सूचना सत्यता के प्रमाण-पत्र के बिना स्वीकार की गई है। यह समुक्ति की जाती है कि घरेलू उद्योग के संबंधित घटक के आंकड़ों का सत्यापन किया गया है और सत्यता के प्रमाण-पत्र की इस स्तर पर कोई आवश्यकता नहीं है।

48. प्रकटन के बाद हितबद्ध पक्षकारों ने यह बताया है कि प्राधिकारी ने अनंतिम शुल्कों का निर्धारण करने के लिए कारण रिकॉर्ड नहीं किए हैं। तथापि, प्रारंभिक जांच परिणाम रिकॉर्ड करने के लिए कारण स्वयं प्रारंभिक जांच परिणामों में ही दर्ज किए गए हैं।

ज. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण

ज.1 बाजार अर्थव्यवस्था के दावों की जांच

49. प्राधिकारी नोट करते हैं कि विगत में पाटनरोधी जाँचों के संबंध में डब्ल्यू टी ओ सदस्यों द्वारा चीन जन गण को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना गया है। अतः पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 8 (2) के अनुसार चीन जन गण को गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना गया है जो पाटनरोधी नियमावली के अनुसार निर्यातक देश या व्यक्तिगत निर्यातकों द्वारा उपर्युक्त अवधारणा के खंडन के अधधीन है।

50. यथासंशोधित पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 1 के पैराग्राफ 8 के अनुसार गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की अवधारणा का खंडन किया जा सकता है यदि चीन जन गण के निर्यातक पैराग्राफ 8 के उप पैराग्राफ (3) में निर्दिष्ट मानदंड के आधार पर सूचना और पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करें तथा उसके विपरीत अवधारणा को सिद्ध करें। चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध वस्तु के सहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार संबंधी प्रश्नावली के उत्तर में पैराग्राफ 8 के उप-पैराग्राफ (3) में यथा उल्लिखित आवश्यक सूचना/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करना अपेक्षित है ताकि निर्दिष्ट प्राधिकारी निम्नलिखित पर विचार कर सकें कि क्या:- :-

(क) कच्ची सामग्रियों सहित कीमत; लागत और निविष्टि तथा श्रम लागत, उत्पादन, बिक्रियां और निवेश के बारे में चीन जन.गण. में संबंधित फर्मों का निर्णय ऐसे बाजारी संकेतों के अनुसार किया जाता है जिसमें आपूर्ति और मांग परिलक्षित होती है और इस बारे में राज्य का अधिक हस्तक्षेप नहीं होता है और क्या प्रमुख निविष्टियों की लागत में बाजार मूल्य पर्याप्त रूप से प्रदर्शित होते हैं;

- (ख) इस प्रकार की फर्मों की उत्पादन लागत और वित्तीय स्थिति विशेषकर परिसंपत्तियों के मूल्यहास, अन्य बड़े खातों, वस्तु विनिमय-व्यापार और ऋणों की प्रतिपूर्ति के माध्यम से भुगतान के संदर्भ में पूर्ववर्ती गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाली प्रणाली से हुई महत्वपूर्ण विकृतियों के अधधीन हैं;
- (ग) इस प्रकार की फर्में दिवालियापन और संपत्ति कानूनों के अधधीन हैं जो फर्मों के प्रचालन की कानूनी निश्चितता और स्थिरता की गारंटी देते हैं; और
- (घ) विनिमय दर का परिवर्तन ब्याज की दर पर किया जाता है।

51. प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्राधिकारी द्वारा प्रारंभिक जाँच परिणाम संबंधी नोटिस जारी किए जाने के पश्चात संबद्ध देश से संबद्ध उत्पादों के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों ने प्रश्नावली के साथ बाजार अर्थव्यवस्था प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है और गैर-बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी पूर्वानुमान का खण्डन किया है। नीचे यथासूचीबद्ध ऐसे प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों के प्रश्नावली के उत्तरों और बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी उत्तरों की पाटन मार्जिन के निर्धारण हेतु जांच की गई है। प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए प्राधिकारी ने अलग-अलग पाटन मार्जिन निर्धारित किया है और पाटनरोधी नियमावली के अनुसार बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी दर्जे की जांच की है :-

क्र. सं.	कंपनी का नाम
1.	यांग्सिन चेन्शियन केमिकल इंडस्ट्री कं० लि०
2.	लियनयुँगाँग लिबेन एग्रो-केमिकल कं० लि०
3.	जिंग्टाई पेस्टीसाइड कं० लि०
4.	झेजियांग जिनाँग केमिकल कं० लि०

ज.2. घरेलू उद्योग के विचार

(क) ऐसी स्थिति में बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। जहां एक प्रमुख शेयर धारक राज्य के स्वामित्व वाली/नियंत्रित कंपनी है।

(ख) प्रारंभिक जांच परिणाम से यह स्पष्ट है कि प्राधिकारी नोट करते हैं कि ऐसी स्थिति में जहां कंपनी का एक शेयरधारक राज्य के स्वामित्व वाली/नियंत्रित कंपनी है, जिसके पास कंपनी के पर्याप्त शेयर हैं, वहां राज्य के हस्तक्षेप की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

(ग) बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक नहीं दिया जा सकता है जब तक चीन के निर्यातक यह सिद्ध न कर दें कि प्रमुख निविष्टियों की कीमतें पर्याप्त रूप से बाजार मूल्य को प्रदर्शित करती हैं। घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि "बाजार मूल्यों को पर्याप्त रूप से

प्रदर्शित करना" की व्याख्या का व्यापक अर्थ यह है कि इन निविष्टियों की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रचलित कीमत से अनिवार्य रूप से तुलनीय होनी चाहिए ।

(घ) बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक कि प्रतिवादी निर्यातक यह सिद्ध न कर दें कि उनकी लेखा पुस्तकों की लेखा परीक्षा अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानकों के अनुसार की जाती है ।

(ङ) यदि इनमें से एक भी मापदंड पूरा नहीं होता है तो बाजार अर्थव्यवस्था नहीं दिया जा सकता ।

(च) घरेलू उद्योग यह अनुरोध करता है कि प्राधिकारी के लिए यह सिद्ध करना अपेक्षित नहीं है कि प्रतिवादी कंपनियां वास्तव में बाजार अर्थव्यवस्था के माहौल में प्रचालन कर रही हैं और बाजार अर्थव्यवस्था के व्यवहार की हकदार हैं । इसके विपरीत चीन के प्रतिवादी निर्यातकों के लिए यह सिद्ध करना अपेक्षित है कि वे बाजार अर्थव्यवस्था की दशाओं में प्रचालन कर रहे हैं ।

(छ) ऐसी स्थिति में जहां वर्तमान शेयरधारक ने अपनी स्वयं की उत्पादन सुविधाएं स्थापित नहीं की हैं बल्कि उन्हें किसी अन्य पक्षकार से प्राप्त किया है, बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक स्वामित्व परिवर्तन की प्रक्रिया दस्तावेजी साक्ष्यों के माध्यम से पूर्णतः सिद्ध न हो जाए ।

(ज) घरेलू उद्योग यह अनुरोध करता है कि चीन के प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा ऊपर उल्लिखित शर्तों को पूरा नहीं किया जाना यह मानने के लिए पर्याप्त है कि चीन की प्रतिवादी कंपनियों को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा नहीं दिया जा सकता है और इस प्रकार सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के नियम 7 के अनुसार किया जाना चाहिए ।

ज.3. निर्यातकों के विचार

52. प्रारंभिक जांच परिणामों और प्रकटन के बाद मै. यांगचिन चेन्चियान कैमिकल इंडस्ट्रीज कं. लि. और झेजियांग जिनोंग कैमिकल कं. लि. का प्रतिनिधित्व करने वाले मै. दुआ एसोसिएट्स ने बाजार अर्थव्यवस्था के व्यवहार के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :-

(क) प्रारंभिक जांच परिणामों में माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी ने मै. यांगचिन चेन्चियान कैमिकल इंडस्ट्रीज कं. लि. और झेजियांग जिनोंग कैमिकल कं. लि. के बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी व्यवहार के अनुरोध को सीधे अस्वीकार कर दिया है और उपलब्ध तथ्यों के अनुसार सामान्य मूल्य के परिकलन की कार्यवाही की है ।

(ख) मै. यांगचिन चेन्चियान कैमिकल इंडस्ट्रीज कं. लि. और झेजियांग जिनोंग कैमिकल कं. लि. पूर्णतः निजी कंपनियां हैं।

(ग) मै. यांगचिन चेन्चियान कैमिकल इंडस्ट्रीज कं. लि. और झेजियांग जिनोंग कैमिकल कं. लि. का कोई भी शेयरधारक राज्य के स्वामित्व वाली/नियंत्रण वाली कंपनी नहीं है। इसके विपरीत मै. चेन्चियान के सभी शेयर चीन के लोगों के स्वामित्व में हैं।

(घ) मै. यांगचिन चेन्चियान कैमिकल इंडस्ट्रीज कं. लि. और झेजियांग जिनोंग कैमिकल कं. लि. ने आपूर्तिकर्ताओं के नाम, उनके स्वामित्व की प्रकृति और प्रकार, निविष्टियों की मात्रा और मूल्य आदि समेत उत्पादन के मूलभूत निविष्टियों के बारे में पर्याप्त सूचना प्रदान की है।

(ङ) मै. यांगचिन चेन्चियान कैमिकल इंडस्ट्रीज कं. लि. और झेजियांग जिनोंग कैमिकल कं. लि. दोनों मौके पर कीमत का प्रयोग करते हैं और उत्पादन की मूलभूत निविष्टियों की बिक्री कीमतें बाजार की दशाओं से तय की जाती हैं। मूल निविष्टियों की कीमतें पाटनरोधी नियमावली में यथाअपेक्षित बाजार मूल्य को पर्याप्त रूप से दर्शाती हैं। इसके अलावा, मै. चेन्चियांग और जिनोंग द्वारा कच्ची सामग्री की खरीद अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर की जाती है।

(च) डी टी पी सी की दो प्रमुख निविष्टियां भिन्न-भिन्न आपूर्तिकर्ताओं से खरीदी जाती हैं जिनमें से अधिकांश निजी कंपनियां हैं। इस सामग्री की खरीद कीमत समय-समय पर बदलती रहती है जिससे मांग और आपूर्ति में परिवर्तन की प्रवृत्ति उचित ढंग से प्रदर्शित होती है।

(छ) फॉस्फोरस पेंटासल्फाइड, यलो फॉस्फोरस के समान नहीं होता है। यह अनुरोध किया गया है कि यह वक्तव्य कि यलो फॉस्फोरस का डी टी पी सी की लागत में 20 से 25% हिस्सा बनता है, बिल्कुल गलत है और यलो फॉस्फोरस की कीमत के संबंध में घरेलू उद्योग के सभी अनुरोध पूर्णतः निराधार हैं और वर्तमान मामले से असंगत हैं। इस प्रकार इनका उपयोग चीन की कंपनियों को बाजार अर्थव्यवस्था का व्यवहार देने से इंकार करने के लिए नहीं किया जा सकता है।

(ज) निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यह मान लिया है कि यदि कतिपय निविष्टियों की खरीद कीमत अंतर्राष्ट्रीय कीमत के बराबर नहीं है तो खरीद कीमत संबंधित निविष्टि के "बाजार मूल्य" को नहीं दर्शाती है। यह दोहराया जाता है कि "बाजार मूल्य" आवश्यक रूप से "प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय कीमत" के बराबर होना जरूरी नहीं है। "बाजार मूल्य" शब्द की अवधारणा इस बात पर जोर देती है कि किसी कतिपय उत्पाद के कीमत निर्धारण का तंत्र मांग और आपूर्ति के आधार पर बाजार की शक्तियों द्वारा तय किया जाना चाहिए।

53. मै. सेठ एसोसिएट्स ने प्रारंभिक जांच परिणामों के बाद मै. लियानयुनगेंग लिबेन एग्रो कैमिकल कंपनी लि. और जिंगताई पेस्टीसाइट कंपनी लि. की ओर से बाजार अर्थव्यवस्था के

व्यवहार के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं, परंतु प्राधिकारी द्वारा जारी निर्यातक सत्यापन रिपोर्ट और प्रकटन विवरण के संबंध में उनसे कोई टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई हैं:-

क) हमारे मुवक्किल प्रबंधन संबंधी निर्णय स्वतंत्र रूप से लेते हैं और निविष्टियों की खरीद बाजार कीमत पर करते हैं और मांग और आपूर्ति के आधार पर विचाराधीन उत्पाद की बिक्री करते हैं ।

ख) संबंधित कंपनी के दैनिक प्रचालन में कोई सरकार या सरकारी अभिकरण हस्तक्षेप नहीं करता है । हमारे मुवक्किलों ने बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार संबंधी प्रश्नावली के अपने उत्तर में बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे के लिए अपनी योग्यता को सही साबित करने के लिए पर्याप्त सूचना प्रदान की है और उन्हें बाजार अर्थव्यवस्था का व्यवहार प्रदान किया जाना चाहिए ।

ज.4 प्राधिकारी द्वारा जांच

54. प्राधिकारी ने ऊपर उल्लिखित 4 प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों का सत्यापन किया था । इन प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा किए गए बाजार अर्थव्यवस्था के दावे से संबंधित मुद्दों की मौके पर सत्यापन के दौरान जांच भी की गई थी और इनमें से प्रत्येक प्रतिवादी उत्पादक/निर्यातक को सत्यापन रिपोर्ट जारी की गई थी बाजार अर्थव्यवस्था के व्यवहार संबंधी उनके दावे के होते हुए भी प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि इन सभी 4 कंपनियों के संबंध में स्थिति निम्नलिखित के कारण "गैर-बाजार अर्थव्यवस्था में प्रचालनरत" माना जाना जारी रहेगा:-

मै. ज़ेजियांग जिनींग कैमिकल कं. लि.

55. यद्यपि, इस कंपनी के 1999 में एक लिमिटेड दायित्व वाली कंपनी के रूप में स्थापित होने का दावा किया गया है, तथापि, इस बात को साबित करने के लिए संतोषजनक दस्तावेजी साक्ष्य नहीं दिए गए हैं कि किस प्रकार से एक दशक पहले कंपनी की स्थापना की तारीख से पूर्व "जिनींग" ट्रेड मार्क मौजूद था । इससे अन्य बातों के साथ-साथ यह साबित होता है कि कंपनी 1989 में भी मौजूद थी । जिस तथ्य को प्रतिवादी उत्पादक/निर्यातक ने छिपाया है । इसके अलावा, निधियों के स्रोत, निवेश के उद्देश्य और मै. ज़ियांगशु रूरल क्रेडिट कोऑप. के साथ संबंध के पर्याप्त संतोषजनक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जा सके हैं । तथापि, सत्यापन के बाद की टिप्पणियों में उन्होंने यह स्वीकार किया है कि मै. ज़ियांगशु रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव एक अधीनस्थ कंपनी है, इस तथ्य को उन्होंने पहले घोषित नहीं किया था । इसके अलावा, निधियों के स्रोत निदेशक बोर्ड के ऊपर लेखा परीक्षा मंत्रालय द्वारा नियंत्रित पर्यवेक्षण बोर्ड की मौजूदगी, कंपनी को सरकार से पर्याप्त सब्सिडियां/अनुदान प्राप्त होना जैसा कि वर्ष 2007 के तुलन-पत्र से स्पष्ट है, के संबंध में रिकॉर्डों की गैर-मौजूदगी से संबंधित मुद्दों पर कंपनी ने कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया है जिससे यह प्रदर्शित होता हो कि उनके द्वारा प्रयुक्त प्रमुख निविष्टियों की कीमतें पर्याप्त रूप से बाजार मूल्य को प्रदर्शित करती

हैं और इससे यह पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि संबद्ध उत्पादक/निर्यातक गैर बाजार अर्थव्यवस्था (एन एम ई) की स्थिति में प्रचालन कर रहा है और इसलिए प्राधिकारी उन्हें इस जांच के प्रयोजनार्थ एक एन एम ई कंपनी मानते हैं ।

मै. यांगजिन चेन्चियान कैमिकल इंडस्ट्री कंपनी लि.

56. यद्यपि, कंपनी के वर्ष 2002 में एक सीमित दायित्व वाली कंपनी के रूप में स्थापित होने का दावा किया गया है, तथापि, इस बात को स्पष्ट करने के लिए कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण/दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया जा सका है कि कंपनी 2002 में कैसे स्थापित हुई थी जबकि भूमि प्रयोग अधिकार 2004 में प्राप्त किया गया था । यह कंपनी वास्तव में पूर्ववर्ती राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी मै. हुवांगशी सिटी फुची फॉस्फेट फैक्ट्री (एक राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी) में से विकसित हुई है । यद्यपि, उनके द्वारा इस तथ्य से इंकार किया गया है । वे इस बात को साबित नहीं कर पाए हैं कि पूर्ववर्ती राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी से भूमि और परिसंपत्तियों का हस्तांतरण बाजार मूल्य पर हुआ था और यह भी कि उन्होंने कंपनी के अधिग्रहण के बाद मौजूदा संयंत्र और उपकरणों को किस प्रकार से काम में लिया । प्रकटन के बाद हितबद्ध पक्षकार ने यह दावा किया है कि भूमि और परिसंपत्तियों का उक्त हस्तांतरण बाजार कीमत पर हुआ था परंतु इस दावे के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है । इसके अलावा, संबद्ध कंपनी के अध्यक्ष श्री यिन चिन्घियान पहले यांगसिन जिले में मै. यांगसिन कैमिकल फैक्ट्री नामक एक अन्य राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी में कार्यरत रहे थे । संबद्ध कंपनी ने मै. यांगसिन कैमिकल फैक्ट्री के पुनर्गठन और सुधार के लिए मै. वेनझु ड्रेगन डाईस्टफ प्लांट (इस कंपनी के ब्यौरे घोषित नहीं किए गए हैं) और चीन जनवादी गणराज्य की सरकार के साथ एक त्रिपक्षीय करार पर हस्ताक्षर किए थे और इस राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी की परिसंपत्ति को संयुक्त रूप से अधिग्रहीत किया था और राज्य की पर्याप्त सब्सिडियां और अनुदान प्राप्त किए थे और इसके अलावा उन्हें विदेशी व्यापार के प्रयोजनार्थ पर्याप्त सब्सिडियां भी प्राप्त हुई थीं । कंपनी के व्यक्तिगत शेयरधारकों और निवेशकों के द्वारा निधियों के स्रोत के संबंध में कोई संतोषजनक उत्तर/दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया जा सका है । कंपनी ने इस बात को प्रदर्शित करने के लिए कोई साक्ष्य प्रदान नहीं किया है कि उनके द्वारा प्रयुक्त प्रमुख निविष्टियों की कीमतें पर्याप्त रूप से बाजार मूल्यों को प्रदर्शित करती हैं ।

मै. लिनयानयुन गैंग लिबेन एग्रोकैमिकल कं. लि. और मै. जिंगताई पेस्टीसाइड्स कं. लि.

57. इन दो उत्पादकों/निर्यातकों के संबंध में प्राधिकारी ने निर्यातक सत्यापन रिपोर्ट जारी की थी, जिससे इस बात का पर्याप्त संकेत मिलता था कि ये गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों के प्रचालन कर रही हैं । तथापि सत्यापन रिपोर्ट के संबंध में कोई टिप्पणी प्राधिकारी द्वारा उनसे प्राप्त नहीं की गई है । प्राधिकारी ने प्रकटन विवरण में भी बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार के दावे से संबंधित इनमें से प्रत्येक मुद्दे पर ध्यान आकर्षित किया था, जिस पर उन उत्पादकों/निर्यातकों ने कोई उत्तर नहीं दिया था । उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि इन दोनों उत्पादकों/निर्यातकों ने गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की दशाओं के अंतर्गत

प्रचालनरत होना स्वीकार कर लिया था और इसलिए प्राधिकारी वर्तमान जांच के लिए इन्हें एन एम ई का दर्जा प्रदान करते हैं ।

58. प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणामों में बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी व्यवहार प्रदान नहीं किया था क्योंकि कोई भी उत्पादक/निर्यातक सत्यापन योग्य साक्ष्यों के साथ यह सिद्ध नहीं कर पाया था कि "प्रमुख निविष्टियों की कीमतें पर्याप्त रूप से बाजार मूल्यों को प्रदर्शित करती हैं।" प्रारंभिक जांच परिणामों में आगे यह भी देखा गया था कि ऐसी स्थिति में जहां कच्ची सामग्री की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रचलित बाजार दरों से काफी कम हैं, न केवल बाजार अर्थव्यवस्था के व्यवहार संबंधी एक प्रमुख शर्त पूरी नहीं होती है बल्कि लागतों का भी अल्प अनुमान लगाया जा सकता है । अतः प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणामों में यह मत अपनाया था कि यदि बाजार अर्थव्यवस्था के व्यवहार का एक भी महत्वपूर्ण मापदंड पूरा नहीं होता है तो प्रतिवादी कंपनियों को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्रदान करना व्यवहार्य नहीं होगा ।

59. स्वामित्व और नियंत्रण से संबंधित मुद्दों, लागत और कीमतों तथा कंपनी के व्यापारित निर्णयों पर उनके प्रभाव और उनके सत्यापन के मद्देनजर प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारणार्थ किसी भी संबद्ध उत्पादक/निर्यातक को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्रदान नहीं किया है ।

अ. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन

अ.1. हितवद्ध पक्षकारों के विचार

60. मै. सेठ एसोसिएट्स ने मै. लियानयुन गैंग लिवेन एग्रोकैमिकल्स कंपनी लि. और जिगताई पेस्टीसाइट कंपनी लि. की ओर से प्रारंभिक जांच परिणामों के बाद निम्नलिखित अनुरोध किए थे परंतु प्रकटन के बाद कोई टिप्पणियां प्रस्तुत नहीं की थीं । :-

(क) प्राधिकारी इस संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के सामान्य मूल्य का परिकलन जैसे कच्ची सामग्री की लागत, परिवर्तन लागत, एस जी ए व्यय और वित्त लागत तथा लाभ मार्जिन की राशि का परिकलन कैसे किया गया है । परिकलित सामान्य मूल्य को गोपनीय माना गया है जिससे इस गणना के संबंध में टिप्पणी करने और प्राधिकारी के निर्णय का खंडन करने में हमारा मुवक्किल सक्षम नहीं है ।

(ख) राज्य परिषद के सीमाशुल्क टैरिफ आयोग ने कतिपय वस्तुओं के संबंध में निर्यात टैरिफ के समायोजन संबंधी परिपत्र जारी किया था जो 1 जुलाई, 2009 से लागू हुआ । यह परिपत्र डी ई टी पी सी के विनिर्माण के लिए प्रमुख कच्ची सामग्री यलो फास्फोरस के संबंध में पूर्व में लागू 50% के विशेष निर्यात टैरिफ को रद्द करता है । इस परिपत्र के लागू होने के बाद चीन जन.गण. से यलो फास्फोरस के निर्यात के लिए लागू निर्यात टैरिफ 20% होगा जो

समायोजन पूर्व 70% से काफी कम है । चूंकि भारतीय डी ई टी पी सी उत्पादक डी ई टी पी सी के विनिर्माण के लिए चीन जन.गण. से भारी मात्रा में यलो फास्फोरस का आयात करते हैं इसलिए हमारे मुवक्किल यह मानते हैं कि यलो फास्फोरस के निर्यात टैरिफ का समायोजन भारतीय उत्पादकों के उत्पादन लागत को काफी कम कर देगा । अतः हमारे मुवक्किल डी जी ए डी से यह निवेदन करते हैं कि वह इस कारक पर विचार करें और आगामी अंतिम जांच परिणामों में तदनुसार पाटन मार्जिन और/या क्षति मार्जिन को कम करें ।

61. मै. यांगसिन चेनचियान कैमिकल इंडस्ट्रीज कैमिकल लि. झेजियांग जिनोंग कैमिकल कं. लि. और चाइना क्राप प्रोटक्शन एसो. का प्रतिनिधित्व करने वाले दुआ एसोसिएट्स ने प्रारंभिक जांच परिणामों और प्रकटन के बाद निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

(क) चीन के उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर में सामान्य मूल्य के निर्धारणार्थ विस्तृत आंकड़े उपलब्ध कराए हैं और उन पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विचार किया जाना चाहिए था और निर्दिष्ट प्राधिकारी को पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैराग्राफ 1 से 6 के प्रावधानों के साथ पठित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 ("अधिनियम") की धारा 9 (1)(ग)(i) के आधार पर संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए आधार के रूप में चीन जन.गण. में डी टी पी सी की घरेलू बिक्री कीमत पर विचार करना चाहिए था ।

(ख) माननीय प्राधिकारी ने "उपलब्ध तर्कसंगत आधार" के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करके और "उपलब्ध तथ्यों के आधार पर" उसका परिकलन करके गलती की है ।

(ग) निर्दिष्ट प्राधिकारी ने ऐसा करते समय ऐसे कुछ कारकों की उपेक्षा की है जो कीमतों और लागतों की तुलनीयता को प्रभावित करते हैं और वह तत्संबंधी समायोजन करने में विफल रहे हैं ।

(घ) चीनी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा उनकी पैमाने की किफायतों, संभार तंत्र की प्राप्ति, प्रक्रिया अवसंरचना, भौगोलिक कारण और कच्ची सामग्री की उपलब्धता के संबंध में प्राप्त किए जा रहे लाभों की पाटन और क्षति, दोनों संबंधी विश्लेषण में पूरी संगतता और संबंध है क्योंकि इनके चलते उत्पादन की लागत कम हो जाती है। तथापि, माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा सामान्य मूल्य का निर्धारण करते समय उक्त लाभों की पूर्णतः उपेक्षा की गई है ।

(ङ) भारत को एक प्रतिनिधि देश के रूप में प्रयोग करके और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य का परिकलन करके तथा चीन के उत्पादकों को प्राप्त लाभों पर ध्यान नहीं देकर और इसके बजाए निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर में प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य का आकलन करके कृत्रिम रूप से एक उच्च सामान्य मूल्य

ज्ञात किया गया है जिसके कारण पाटन का त्रुटिपूर्ण निष्कर्ष निकला है जिससे चीन की कंपनियों को हानि पहुंची है ।

(च) माननीय प्राधिकारी निर्यात बिक्रियों और घरेलू बिक्रियों के बीच अंतर करने में विफल रहे हैं और यह कि इसी के कारण निस्संदेह माननीय प्राधिकारी ने एक कृत्रिम कारखाना द्वारा निर्यात कीमत की गणना की है जो वास्तविक कारखाना द्वारा निर्यात कीमत से काफी कम हो सकती है । चीन जन.गण. में असंबद्ध व्यापारियों की बिक्रियां उसके द्वारा घरेलू बिक्रियों के रूप में दर्ज की गई हैं और यह समझा नहीं गया है कि किस आधार पर माननीय प्राधिकारी द्वारा इन्हें निर्यात बिक्रियों का हिस्सा माना गया है ।

(छ) प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के निर्धारणार्थ बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश या प्रतिनिधि देश के चयन के संबंध में गैर-बाजार अर्थव्यवस्था निर्धारित करने के लिए नियम 7 की प्रक्रिया का पालन नहीं किया है ।

(ज) निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत, पाटन मार्जिन और क्षति रहित कीमत ज्ञात करने की पूरी पद्धति का खुलासा नहीं किया गया है ।

अ.2. प्राधिकारी द्वारा जांच

62. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध के पैरा 8 (2) के अनुसार चीन जन.गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना गया है जो उपर्युक्त नियमों के अनुसार निर्यातक देश या अलग-अलग उत्पादक और निर्यातक द्वारा खंडन के अधीन है । चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तु के सहयोगी निर्यातकों/उत्पादकों को बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार प्रश्नावली के उत्तर में पैराग्राफ 8 के उप पैराग्राफ (3) में यथाउल्लिखित आवश्यक सूचना/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने अपेक्षित हैं ताकि निर्दिष्ट प्राधिकारी बाजार अर्थव्यवस्था के व्यवहार संबंधी उनके दावे पर विचार कर सकें ।

63. जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना में प्राधिकारी ने यह दर्शाया था कि आवेदक ने दावा किया है कि चीन जन.गण. एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था है और यह कि केवल भारत, चीन और डेनमार्क विश्व में विचाराधीन उत्पाद के ज्ञात उत्पादक हैं । आवेदक घरेलू उद्योग ने सामान्य बिक्री और प्रशासन व्यय तथा लाभ सहित भारत में उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया था । प्राधिकारी ने अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार सभी हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियां आमंत्रित की थी तथापि आवेदकों तथा चीन के उत्पादकों, निर्यातकों समेत किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने इस प्रयोजनार्थ उचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के लिए प्राधिकारी के समक्ष कोई वास्तविक तथ्य नहीं रखा था । घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि इस मामले में भारत को चीन जन.गण. के लिए एक उचित प्रतिनिधि देश माना जाना चाहिए और तदनुसार सामान्य मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए । केवल तीन देशों- चीन, भारत और डेनमार्क ने उत्पादन सुविधाएं उपलब्ध होने को देखते हुए किसी भी

विरोधी पक्षकार ने घरेलू उद्योग के दावे पर प्रश्न नहीं उठाया है। तथापि, उन्होंने यह तर्क दिया है कि भारत को एक प्रतिनिधि देश मानकर और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य परिकलित करके तथा चीन के उत्पादकों को प्राप्त लाभों पर ध्यान नहीं देकर बल्कि बजाए इसके निर्यातक प्रश्नावली के उनके उत्तर में प्रस्तुत तथ्यों के आधार पर सामान्य मूल्य का आकलन करके प्राधिकारी द्वारा एक कृत्रिम रूप से उच्च सामान्य मूल्य परिकलित किया गया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन.गण. एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है और चीन के उत्पादकों/निर्यातकों को मिल रहे लाभों पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के समय विचार नहीं किया जा सकता है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि डेनमार्क एक विकसित देश है और चीन के उत्पादकों के लिए वह एक उचित देश नहीं हो सकता है।

64. प्राधिकारी समय-समय पर यथासंशोधित सी.शु. टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 9 के अनुसार प्रत्येक सहयोगी उत्पादक/निर्यातक के लिए अलग-अलग सामान्य मूल्य निर्धारित करेंगे। तथापि, अलग-अलग सामान्य मूल्य केवल चीन जन.गण. के प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों के मामले में तभी निर्धारित किया जा सकता है यदि वे एन एम ई की पूर्व धारणा का प्राधिकारी के समक्ष संतोषजनक ढंग से खंडन करने में सक्षम हो जाएं। चूंकि वर्तमान मामले में संबद्ध देश का कोई भी प्रतिवादी उत्पादक/निर्यातक प्राधिकारी के सामने संतोषजनक ढंग से एन एम ई की पूर्व धारणा का खंडन नहीं कर पाया है इसलिए प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 के अनुसार सामान्य मूल्य निर्धारित किया है।

65. जैसा ऊपर रिकार्ड किया गया है चीन जन.गण. से प्रतिवादी उत्पादकों और निर्यातकों की लागत और कीमतें गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति द्वारा काफी प्रभावित होती हैं और इसलिए सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 1 से 6 के अनुसार नहीं किया जा सकता है। अतः प्राधिकारी संबद्ध वस्तुओं के लिए चीन जन.गण. में सामान्य मूल्य के निर्धारण उक्त अनुबंध के पैरा 7 का संदर्भ ग्रहण करते हैं।

66. इस संबंध में पाटनरोधी नियम के अनुबंध-1 के पैरा-7 में यह प्रावधान है कि :-

"गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत सहित, सामान्य मूल्य का निर्धारण तीसरे देश की बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकलित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहाँ यह संभव नहीं है, किसी अन्य आधार पर किया जाएगा। संबद्ध देश के विकास के स्तर तथा उक्त उत्पाद को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा समुचित पद्धति से एक उचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चुनाव किया जाएगा और चुनाव के समय उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर विचार किया जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य देश के संबंध में इसी प्रकार के किसी अन्य विषय पर की गई जांच हेतु, जहाँ उचित हो, समय सीमा

पर विचार किया जाएगा । जांच से संबंधित सभी हितबद्ध पक्षकारों को उपर्युक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के संबंध में अविलम्ब सूचना दी जाएगी और अपनी टिप्पणियाँ देने के लिए उचित समय दिया जाएगा ।"

67. प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत, पाटन मार्जिन और क्षतिरहित कीमत निर्धारित करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया और संगत प्रथा का पालन किया है और इनके निर्धारण की पद्धति का खुलासा प्रकटन विवरण में किया गया है ।

68. प्राधिकारी ने प्रारंभिक जांच परिणामों में यह रिकॉर्ड किया था कि किसी उपयुक्त तीसरे देश में संबद्ध वस्तु की लागत और कीमतों के संबंध में किसी विश्वसनीय आंकड़े के अभाव में सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली में उपलब्ध तीसरे विकल्प के आधार पर किया गया है जिसमें भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से दी गई अथवा देय कीमत जिसे यदि आवश्यक हो तो संगत लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए समायोजित किया गया हो, सहित किसी अन्य तर्कसंगत आधार को अपनाए जाने की व्यवस्था है । तदनुसार चीन जन.गण. के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए विचाराधीन उत्पाद का कारखाना द्वार सामान्य मूल्य उपलब्ध तथ्यों के आधार पर परिकलित किया गया है । सामान्य मूल्य का परिकलन सभी प्रमुख निविष्टियों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर विचार करते हुए किया गया है । खपत संबंधी मानकों पर प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा किए गए दावों के आधार पर विचार किया गया है । परिवर्तन लागत और एस जी ए व्यय कुशल घरेलू उत्पादक के आधार पर अपनाए गए थे । ब्याज को छोड़कर कारखाना द्वार लागत के 5% के तर्कसंगत ब्याज मार्जिन को जोड़ने के बाद प्रारंभिक जांच परिणामों में परिकलित मूल्य *** अम. डॉ./किग्रा. के रूप में परिकलित किया गया था ।

69. संबद्ध देश से उत्पादक/निर्यातक के आंकड़ों के सत्यापन के बाद और उन्हें दिए गए गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे के मद्देनजर और चूंकि किसी हितबद्ध पक्षकार ने किसी उचित तीसरे देश के आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए हैं, प्राधिकारी ने नियमावली में उपलब्ध तीसरे विकल्प को अपनाया है जिसमें समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तविक रूप से दी गई या देय कीमत, जिसे यदि आवश्यक हो तो एक तर्कसंगत लाभ मार्जिन शामिल करने के लिए समायोजित किया गया हो, सहित किसी अन्य तर्कसंगत आधार को अपनाए जाने की व्यवस्था है और संबद्ध देश के संबंध में सामान्य मूल्य परिकलित किया है । सामान्य मूल्य का परिकलन सभी प्रमुख निविष्टियों की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर विचार करते हुए किया गया है । चीन के सहयोगी उत्पादकों के भारत और खपत मानकों पर विचार किया गया है और परिवर्तन लागत और एस जी ए व्यय को सर्वाधिक कुशल घरेलू उत्पादक के आधार पर अपनाया गया है और ब्याज को छोड़कर कारखाना द्वार लागत के 5% का तर्कसंगत लाभ मार्जिन जोड़ने के बाद परिकलित सामान्य मूल्य अब निम्नानुसार ज्ञात किया गया है:-

अम.डॉ./प्रति किग्रा.

कच्ची सामग्री की लागत	***
परिवर्तन लागत	***
एस जी ए व्यय और वित्त पोषण लागत	***
लाभ मार्जिन	***
परिकलित सामान्य मूल्य	***

अ. निर्यात कीमत**अ.1. सहयोगी निर्यातक****अ.1.क. मै. झेजियांग जिनोंग कैमिकल कं. लि.**

70. मै. झेजियांग जिनोंग कैमिकल कं. लि. ने जांच अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तु के *** मी.ट. के निर्यात की जानकारी दी है। इस कंपनी ने कारखाना द्वार निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए समुद्री भाड़ा, बीमा, वैट समायोजन, कमीशन, अंतरदेशी परिवहन, अन्य अनुषंगी शुल्कों और बैंक प्रभारों के लिए समायोजन का दावा किया है। प्राधिकारी ने इस उत्पादक/निर्यातक के लिए कारखाना द्वार निर्यात कीमत *** अम.डॉ. प्रति किग्रा. के रूप में निर्धारित की है, यह निर्धारण नीचे पैरा 74 में दी गई तालिका के अनुसार किए गए व्यय को समायोजित करने के बाद किया गया है।

अ.1.ख. मै. यांगजिन चेतियांन कैमिकल इंडस्ट्री कं. लि.

71. मै. यांगजिन चेतियांन कैमिकल इंडस्ट्री कं. लि. ने जांच अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तु के *** मी.ट. के निर्यात की जानकारी दी है। निर्यातक ने कारखाना द्वार निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए समुद्री भाड़ा, बीमा, कमीशन, अंतरदेशीय परिवहन, अन्य अनुषंगी शुल्कों और बैंक प्रभारों के लिए समायोजन का दावा किया है। तथापि, निर्यातक के आंकड़ों के सत्यापन के दौरान यह नोटिस किया गया है कि प्रदत्त वैट और प्राप्त रिफंड के संबंध में कोई समायोजन नहीं किया गया है। यद्यपि, निर्यातक के लिए बीजक मूल्य के 17% की दर से वैट का भुगतान करना अपेक्षित है और वह निर्यातों पर प्रदत्त वैट के एक भाग की वापसी का हकदार है। अतः यह समायोजन बीजक मूल्य के आधार पर किए गए हैं। अतः प्राधिकारी ने इस उत्पादक/निर्यातक के लिए नीचे पैरा 74 में दी गई तालिका के अनुसार व्ययों को समायोजित करने के बाद कारखाना द्वार निर्यात कीमत *** अम. डॉ. प्रति किग्रा. के रूप में निर्धारित की है।

अ.1.ग.मै. जियांताई पेस्टीसाइड्स कं. लि.

72. मै. जियांताई पेस्टीसाइड्स कं. लि. ने जांच अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तु के *** मी.ट. के निर्यात की जानकारी दी है। निर्यातक ने कारखाना द्वार निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए विदेशी परिवहन, अंतरदेशीय भाड़ा, पत्तन प्रभार, बैंक प्रभार, ऋण लागत और विदेशी बीमा, के लिए समायोजन का दावा किया है। तथापि, निर्यातक के आंकड़ों के सत्यापन के दौरान यह नोटिस किया गया है कि प्रदत्त वैट और प्राप्त रिफंड के संबंध में कोई समायोजन नहीं किया गया है। यद्यपि, निर्यातक के लिए बीजक मूल्य के 17% की दर से वैट का भुगतान करना अपेक्षित है और वह निर्यातों पर प्रदत्त वैट के एक भाग की वापसी का हकदार है। अतः यह समायोजन बीजक मूल्य के आधार पर किए गए हैं। अतः प्राधिकारी ने इस उत्पादक/निर्यातक के लिए नीचे पैरा 74 में दी गई तालिका के अनुसार व्ययों को समायोजित करने के बाद कारखाना द्वार निर्यात कीमत *** अम. डॉ. प्रति किग्रा. के रूप में निर्धारित की है।

अ.1.घ. मै. लियानयुनगैंग लिबेन एग्रो कैमिकल कं. लि.

73. मै. लियानयुनगैंग लिबेन एग्रो कैमिकल कं. लि. ने जांच अवधि के दौरान भारत को संबद्ध वस्तु के *** मी.ट. के निर्यात की जानकारी दी है। निर्यातक ने कारखाना द्वार निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए विदेशी परिवहन, विदेशी बीमा, ऋण लागत, वैट, अंतरदेशीय भाड़ा और पत्तन प्रभारों के लिए समायोजन का दावा किया है। प्राधिकारी ने इस उत्पादक/निर्यातक के लिए नीचे पैरा 74 में दी गई तालिका के अनुसार व्ययों को समायोजित करने के बाद कारखाना द्वार निर्यात कीमत *** अम. डॉ. प्रति किग्रा. के रूप में निर्धारित की है।

74. उपर्युक्त सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए कारखाना द्वार निर्यात कीमत निम्नानुसार निर्धारित की गई है: -

	इकाई	यांगजिन चैन्चियान	लियानयुनगैंग लिबेन	जिंगताई पेस्टीसाइड्स	झेजियांग जिनांग
निर्यात मात्रा	मी.ट.	***	***	***	***
प्रति इकाई निर्यात कीमत	अम.डॉ./किग्रा.	***	***	***	***
कीमत समायोजन					
□ समुद्री भाड़ा	अम.डॉ./किग्रा.	***	***	***	***
□ बीमा	अम.डॉ./किग्रा.	***	***	***	***
□ कमीशन	अम.डॉ./किग्रा.	***	***	***	***
□ अंतरदेशीय भाड़ा	अम.डॉ./किग्रा.	***	***	***	***
□ अन्य अनुषंगी शुल्क	अम.डॉ./किग्रा.	***	***	***	***
□ ऋण लागत	अम.डॉ./किग्रा.	***	***	***	***
□ बैंक प्रभार	अम.डॉ./किग्रा.	***	***	***	***

□ वैट अंतर	अम.डॉ./किग्रा.	***	***	***	***
□ कुल समायोजन	अम.डॉ./किग्रा.	***	***	***	***
कारखानागत निर्यात कीमत	अम.डॉ./किग्रा.	***	***	***	***

अ.1.ड. असहयोगी निर्यातक

75. चूंकि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के किसी अन्य उत्पादक/निर्यातक से कोई अन्य उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है इसलिए प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर असहयोगी निर्यात के संबंध में निर्यात कीमत निर्धारित करने का निर्णय लिया है। सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के मामले में किए गए समायोजनों के समतुल्य समायोजनों की अनुमति कारखाना द्वार स्तर पर निर्यात कीमत ज्ञात करने के लिए दी गई है। इस पद्धति को अपनाकर संबद्ध वस्तु के लिए असहयोगी निर्यातकों के संबंध में प्राधिकारी द्वारा ज्ञात की गई कारखाना द्वार स्तर पर निर्यात कीमत उपलब्ध तथ्यों के आधार पर *** अम.डा. प्रति किग्रा. बनती है।

76. जहां तक पाटन मार्जिन की गणना के ब्यौरे उपलब्ध कराने के लिए मै. एपीजे-एस एल जी के अनुरोध का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि निर्यात कीमत के ब्यौरे पहले ही प्रकटन विवरण में अलग-अलग प्रतिवादी उत्पादक/निर्यातक को उपलब्ध करा दिए गए हैं। परिकलित सामान्य मूल्य के निर्धारण की पद्धति को भी ज्ञात पाटन मार्जिन के % के साथ प्रकटन विवरण में उचित ढंग से प्रकट कर दिया गया था।

77. मै. दुआ एसोसिएट्स के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि समायोजनों के साथ ज्ञात की गई निर्यात कीमत उसके निर्धारण के लिए अपनाई गई पद्धति के साथ अलग-अलग प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों को प्रकट कर दी गई थी। परिकलित सामान्य मूल्य के निर्धारण की पद्धति भी ज्ञात पाटन मार्जिन के % के साथ प्रकटन विवरण में उचित ढंग से बता दी गई थी।

78. जहां तक यलो फास्फोरस की कीमतों के प्रभाव के संबंध में मै. दुआ एसोसिएट्स के अनुरोध का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि फास्फोरस पैंटा सल्फाइड (पी 2 एस 5) एक मध्यवर्ती वस्तु है और यलो फास्फोरस से उत्पादित होती है। फास्फोरस पैंटासल्फाइड की कीमतें इस उत्पाद की तुलना में यलो फास्फोरस की कीमतों द्वारा अधिक शासित होती हैं। यदि यलो फास्फोरस की कीमतें बढ़ती हैं तो फास्फोरस पैंटासल्फाइड की कीमतें भी बढ़ जाती हैं।

79. जहां तक चीन के उत्पादक/निर्यातकों को पैमाने की किफायतों, संभार तंत्र की प्राप्ति, प्रक्रिया अवसंरचना, भौगोलिक कारणों और कच्ची सामग्री की उपलब्धता के संबंध में मिलने वाले लाभों संबंधी मै.दुआ एसो. के अनुरोध का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि चूंकि चीन के उत्पादक/निर्यातकों को बाजार अर्थव्यवस्था का व्यवहार प्रदान नहीं किया गया है,

इसलिए प्राधिकारी ने पैरा 69 में दी गई पद्धति के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है ।

80. प्रकटन के बाद के स्तर पर घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित विचार व्यक्त किए गए हैं:

- i) जिनताई पेस्टीसाइड की निर्यात कीमत को उन पर कम शुल्क लगाए जाने के कारण उनके माध्यम से निर्यातों के विचलन के मद्देनजर अवश्य अस्वीकार किया जाना चाहिए ।
- ii) सभी निर्यातकों को उनके उत्तरों में अनिवार्य तथ्यों को घोषित नहीं किए जाने के कारण असहयोगी घोषित किया जाना चाहिए ।

81. जहां तक घरेलू उद्योग के इस विचार का संबंध है कि मै. जिनताई पेस्टीसाइड के निर्यात कीमत को उन पर लगाए गए कम शुल्क के कारण उनके माध्यम से निर्यातों के विचलन के मद्देनजर निश्चित रूप से अस्वीकृत किया जाना चाहिए, प्राधिकारी यह समुक्ति करते हैं कि यह आरोप निराधार हैं और जांच अवधि के बाद की गतिविधियां संबद्ध जांच का हिस्सा नहीं बन सकती हैं । इसके अलावा, प्राधिकारी यह समुक्ति करते हैं कि सबद्ध उत्पादकों/निर्यातकों ने उत्तर दिया था और उनके आंकड़ों के सत्यापन में सहयोग किया था और इसलिए उन्हें असहयोगी घोषित किया जाना उचित नहीं होगा, जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा दावा किया गया है ।

ट. पाटन मार्जिन

82. निर्धारित सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत पर विचार करते हुए, जैसाकि उपर स्पष्ट किया गया है, प्राधिकारी ने निम्नानुसार पाटन मार्जिन का निर्धारण किया है :-

	इकाई	यांगजिन चेनटेन	लियांनयंगगैंग लिबेन	जिंगताई	झेजियांग	असहयोगी निर्यातक
सामान्य मूल्य	अम.डॉ./किग्रा.	***	***	***	***	***
निर्यात कीमत	अम.डॉ./किग्रा.	***	***	***	***	***
पाटन मार्जिन	अम.डॉ./किग्रा.	***	***	***	***	***
पाटन मार्जिन %	% रेंज	70-80	40-50	30-40	45-55	85-95

ठ. क्षति एवं कारणात्मक संबंध

83. डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 3.1 तथा पाटनरोधी नियम के अनुबंध-II में (क) पाटित आयातों की मात्रा और समान उत्पाद हेतु घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों के

प्रभाव, तथा (ख) पाटित आयातों के मात्रा प्रभाव के संबंध में ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामी प्रभाव हेतु एक विषयपरक जांच का प्रावधान किया गया है। प्राधिकारी द्वारा इस बात की जांच की जानी अपेक्षित है कि क्या भारत में समग्र अर्थों में या उत्पादन अथवा खपत की तुलना में आयातों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। पाटित आयातों के कीमत प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी द्वारा इस बात की जांच की जानी अपेक्षित है कि क्या आयातक देश में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों का उद्देश्य अन्यथा मूल्यों को काफी हद तक कम करना है अथवा ऐसी मूल्य वृद्धि को रोकना है जो अन्यथा काफी हद तक बढ़ गई होती।

84. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 11 और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए घरेलू उद्योग की क्षति और पाटित आयातों तथा क्षति के बीच कारणात्मक संबंध को निर्धारित किया है।

85. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति संबंधी विश्लेषण क्षमता उपयोग, बिक्री, स्टॉक, बाजार हिस्सा आदि जैसे क्षति संबंधी मापदंडों के संबंध में संख्या के अनुसार उचित ढंग से किया गया है। जहां तक घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, पाटनरोधी नियम के अनुबंध-II के पैरा (IV) में निम्नानुसार उल्लिखित है :-

"संबद्ध घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में सभी संबद्ध आर्थिक कारकों का एक मूल्यांकन करना और उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले संकेतकों का मूल्यांकन करना शामिल होगा, इसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर प्राप्ति या क्षमता का उपयोग कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह, सामान, रोजगार, मजदूरी वृद्धि, पूंजीगत निवेश को बढ़ाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव शामिल हैं।"

ठ.1 घरेलू उद्योग के विचार

86. प्रारंभिक जांच परिणामों के बाद घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

(क) चीन जन.गण. से आयातों में समग्र रूप से तथा भारत में उत्पादन और खपत की दृष्टि से भी वृद्धि हुई है।

(ख) इस उत्पाद के आयातों से बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है।

(ग) यद्यपि, क्षति अवधि के दौरान उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है, यहां तक कि बिक्री कीमतों में भी वृद्धि हुई है परंतु बिक्री कीमतों में हुई वृद्धि उत्पादन लागत में हुई वृद्धि से काफी कम है। आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतें कम हुई हैं और ऐसी कीमत वृद्धि रूक गई है जो पाटित आयातों के अभाव में अन्यथा बढ़ गई होती।

(घ) वर्ष 2006-07 में उत्पाद की मांग में गिरावट आई है और इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्रियों में भी गिरावट आई है तथापि घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्रियों में हुई गिरावट मांग में आई गिरावट से अधिक रही थी। परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग ने 2006-07 तक काफी बाजार हिस्सा गंवा दिया था। यद्यपि, जांच अवधि में घरेलू उद्योग ने कुछ बाजार हिस्सा पुनः प्राप्त कर लिया, तथापि, यह पूर्व में दर्ज स्तरों से काफी कम रहा था। घरेलू उद्योग को ऐसी स्थिति में काफी अप्रयुक्त क्षमताओं का सामना करना पड़ रहा था जहां बाजार में उत्पाद की मांग काफी अधिक थी।

(ङ) घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में लगातार गिरावट आई है और यह गिरावट इतनी तेज रही है कि घरेलू उद्योग को 2006-07 से वित्तीय घाटे उठाने पड़े थे जो जांच अवधि के दौरान और अधिक बढ़ गए थे।

(च) लगाई गई पूंजी पर आय तथा नकद लाभों में भी लाभों जैसी ही प्रवृत्ति देखी गई थी। जांच अवधि के दौरान नियोजित पूंजी पर आय और नकद लाभ दोनों ऋणात्मक हो गए थे। 2006-07 तक अनेक मापदंडों की दृष्टि से घरेलू उद्योग की वृद्धि नकारात्मक रही थी जो मात्रात्मक मापदंड के संबंध में तत्पश्चात सकारात्मक हो गई थी (यद्यपि पाटन के अभाव में घरेलू उद्योग काफी अधिक मात्राएं प्राप्त कर सकता था)। तथापि, कीमत मापदंडों में वृद्धि पूरे समय नकारात्मक रही है।

(छ) आयातों के कारण बाजार में कीमत कटौती हो रही थी। परिणामस्वरूप आयातों की मात्रा में वृद्धि होना ऐसी स्थिति में भी जारी रहा जबकि घरेलू उद्योग के पास अप्रयुक्त क्षमताएं मौजूद थीं।

(ज) घरेलू उद्योग द्वारा की गई कीमत कटौती के परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जिसमें घरेलू उद्योग उत्पादन लागत में हुई वृद्धि के अनुपात में अपनी बिक्री कीमत में वृद्धि करने में सक्षम नहीं था।

(झ) पाटित आयातों के कारण कीमतों में हुई कमी के परिणामस्वरूप लाभप्रदता की स्थिति इतनी अधिक खराब हो गई कि घरेलू उद्योग जो 2005-06 तक लाभ कमा रहा था, उसने 2006-07 में वित्तीय घाटे उठाना शुरू कर दिया जिनमें जांच अवधि के दौरान और अधिक वृद्धि हो गई।

(ज) पाटित आयातों द्वारा लाभप्रदता में आई विकृति के कारण नियोजित पूंजी पर आय नकद लाभों और परिणामस्वरूप नकद प्रवाह की दृष्टि से घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में विकृति आ गई ।

ठ.2 उत्पादकों/निर्यातकों के विचार

87. मै. लिबेन एग्रो और मै. जिन्ताई का प्रतिनिधित्व करने वाले मै. सेठ एसोसिएट्स ने प्रारंभिक जांच परिणाम के बाद के स्तर पर क्षति के संबंध में कोई विचार प्रस्तुत नहीं किए हैं।

88. मै. यांगजिन चैनचियांग कैमिकल इंडस्ट्रीज कं. लि. झेजियांग जिनांग कैमिकल कं. लि. और चाइना क्राफ प्रोटक्शन इंडस्ट्री एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने वाले मै. दुआ एसोसिएट्स ने प्रारंभिक जांच परिणामों के बाद निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:-

(क) घरेलू उद्योग के संबंध में अनेक संकेतक सकारात्मक प्रवृत्ति दर्शाते हैं और प्रारंभिक जांच परिणामों में स्वयं यह रिकार्ड किया गया है कि पूर्वोक्त अनेक कारकों में सुधार का संकेत मिलता है जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि कथित पाटन वह कारण नहीं है जिससे याचिकाकर्ता और/या उसके कथित समर्थक एक्सल को कोई कथित क्षति हुई है । दुर्भाग्यवश माननीय प्राधिकारी ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया है ।

(ख) प्राधिकारी ने अन्य मापदंडों का आकलन करते समय एक मापदंड में दर्ज किए गए सुधार की उपेक्षा कर दी है और इस प्रकार वे घरेलू उद्योग से संबंधित विभिन्न मापदंडों का समग्र आकलन करने में विफल रहे हैं जो अकेले ही कथित क्षति के संबंध में वास्तविक तस्वीर दर्शा सकता है । इसके अलावा, प्राधिकारी ने चीन जन.गण. से आयातों के कारण कथित क्षति के विरुद्ध बातों को दर्शाने वाले संकेतकों पर ध्यान नहीं देने का फैसला किया है और इस प्रकार क्षति का आकलन अधूरा और त्रुटिपूर्ण है ।

(ग) यद्यपि, प्राधिकारी ने यह टिप्पणी करना उचित माना है कि जांच अवधि के दौरान चीन के आयातों में वृद्धि काफी अधिक रही थी, तथापि वे इस बात पर विचार करने में विफल रहे हैं कि इससे भी अधिक वृद्धि घरेलू उद्योग की बिक्रियों में हुई थी ।

(घ) जिनांग और चीन के अन्य निर्यातकों से आयातों में वृद्धि बाजार मांग में हुई वृद्धि से कम रही है ।

(ङ) प्राधिकारी जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में हुई सकारात्मक वृद्धि को भी देखने में विफल रहे हैं और उन्होंने चीन जन.गण. से हुए आयातों के बाजार हिस्से में कमी को भी नहीं देखा तथा यह कि चीन से हुए आयातों में 2004-05 से 2007-08 (जांच अवधि) तक केवल 58.66% से 60.94% अर्थात् केवल 2% की वृद्धि हुई थी ।

(च) प्राधिकारी ने अपने इस अंतरनिहित निष्कर्ष का आधार स्पष्ट नहीं किया है कि मांग में

होने वाली किसी वृद्धि को घरेलू उत्पादन में समतुल्य वृद्धि से सह-संबद्ध होना चाहिए या घरेलू उत्पादन कुछ कथित क्षति उठा रहा है । इस मान्यता में यह पूर्व धारणा है कि घरेलू उत्पादन घरेलू मांग के लगभग बराबर है ।

(छ) घरेलू उद्योग घरेलू मांग को पूरा नहीं कर सकता है और आयात आवश्यक हैं । घरेलू उद्योग किसी भी समय भारत में मांग को पूरा नहीं कर सकता है ।

(ज) प्रारंभिक जांच परिणामों में बाजार में मांग और घरेलू उद्योग के उत्पादन से संबंधित प्राधिकारी के स्वयं के आंकड़ों की तुलना और उपर्युक्त नोट की गई बात स्पष्ट रूप से यह संकेत करती है कि घरेलू उद्योग घरेलू मांग को पूरा करने में पूर्णतः अक्षम है जो अच्छे मानसून के मौसम में इस उद्योग के उत्पादन से काफी अधिक रहती है । इसके अलावा इससे यह भी बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि ऐसा चीन के निर्यातकों द्वारा निर्यात किए जाने के कारण नहीं हुआ है ।

(झ) इससे यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि भारत में उपभोक्ताओं के आयात अपरिहार्य हैं और यदि चीन से आयातों पर शुल्क लगाया जाता है तो इससे केवल उत्पादन और निर्यात के अन्य स्रोत अर्थात् याचिकाकर्ता की डेनमार्क स्थित मूल कंपनी को ही लाभ होगा ।

(ञ) इसलिए केवल यह निष्कर्ष कि क्योंकि मांग में 14% की वृद्धि हुई और उत्पादन में केवल लगभग 6% की वृद्धि हुई और इसलिए घरेलू उद्योग पाटित आयातों के कारण अपने उत्पादन में वृद्धि नहीं कर पाया, पूर्णतः गलत है ।

(ट) प्राधिकारी ने इस बात को भी नजरअंदाज कर दिया है कि उनके खुद के आंकड़ों में जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा डी टी पी सी के उत्पादन में भारी वृद्धि अर्थात् 53.70% दर्शायी गई है । प्राधिकारी ने जांच अवधि के दौरान चीन के आयातों में हुई वृद्धि पर टिप्पणी करते समय इस बात को नोट नहीं किया है कि जांच अवधि के दौरान डेनमार्क से आयातों में 84% तक की वृद्धि हुई है । इसके अलावा प्राधिकारी ने इस बात की भी उपेक्षा की है कि यदि चीन से हुए आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाया जाता है तो डेनमार्क से होने वाले आयातों को भारी लाभ होगा क्योंकि उस समय के आयातों, जो आवश्यक हैं का एकमात्र स्रोत होंगे क्योंकि घरेलू उद्योग घरेलू मांग को पूरा नहीं कर सकता है और इस प्रकार वर्तमान जांच के माध्यम से एकाधिकार सृजित करने का प्रयास किया गया है जिससे अंततः भारत में उपभोक्ताओं को नुकसान होगा ।

(ठ) क्षति जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की कीमतों में गिरावट केवल 0.2% रही है और जांच अवधि के दौरान यह केवल 2.08% रही है । यद्यपि इसी अवधि के दौरान चीन की आयात कीमतों में वस्तुतः क्षति जांच अवधि में 1.98% की वृद्धि हुई है और जांच अवधि के दौरान 16% की वृद्धि हुई है । इस प्रकार कीमत संबंधी कोई प्रभाव नहीं पड़ा है जिससे कोई कथित क्षति सिद्ध होती हो ।

(ड) चीन से डी टी पी सी के आयातों द्वारा घरेलू उद्योग को कोई वास्तविक क्षति नहीं हुई है या किसी वास्तविक क्षति का खतरा नहीं है । कथित क्षति केवल एक आरोप, कल्पना और सुदूर संभावना है तथा साक्ष्यों द्वारा इसे साबित नहीं किया गया है ।

(ढ) यह बात दोहराई गई है कि डी टी पी सी के आयात भारत में मांग और भारतीय घरेलू उत्पादन के बीच के अंतर के कारण किए गए हैं । यह आयात इस अंतर को पाटने के लिए किए गए हैं । आयातों की मात्रा में वृद्धि मुख्यतः संबद्ध वस्तु की मांग में हुई वृद्धि के कारण हुई है जिसे घरेलू उत्पादन द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता है ।

(ण) "अन्य कारक" किसी भी कारणात्मक संबंध के लिए उत्तरदायी नहीं हैं । घरेलू उद्योग को हुई क्षति, यदि कोई हो, उसके द्वारा उठाए गए नुकसानों के कारण हुई है जो चीन के निर्यातकों के द्वारा नहीं उठाए गए हैं ।

(त) घरेलू उद्योग द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि वह हमेशा से पूर्ववर्ती वर्षों में कम लाभ अर्जित करता रहा है और हाल के वर्षों में हुए घाटे "अन्य कारकों" के कारण हुए हैं और न कि चीन के निर्यातकों द्वारा डी टी पी सी के पाटन के कारण ।

(थ) याचिकाकर्ता द्वारा उठाई गई क्षति यदि कोई है, उसके आंतरिक प्रतिस्पर्धी के बाजार हिस्से में घाटे के कारण हुई है ।

(द) याचिकाकर्ता के उत्पादन में 6% की कमी के कारण समर्थक, एक्सल के उत्पादन में 6% की वृद्धि हुई है अतः याचिकाकर्ता के उत्पादन में आई गिरावट भारतीय बाजार में एकमात्र उत्पादक के साथ आंतरिक प्रतिस्पर्धा के कारण आई है और न कि चीन जन.गण. से आयात या पाटन के कारण, जैसा कि आरोप लगाया गया है ।

(ध) घरेलू मांग और घरेलू उत्पादन और बिक्रियों के बीच काफी बड़ा अंतर है । इस प्रकार संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयात आवश्यक हो जाते हैं, विशेष रूप से इस तथ्य के मद्देनजर कि भारत में संबद्ध वस्तु का उत्पाद चीन और अब डेनमार्क से किया जाता है ।

ठ.3 आयातकों/प्रयोक्ताओं के विचार

89. आयातकों/प्रयोक्ताओं ने प्रारंभिक जांच परिणाम के बाद के स्तर पर क्षति के संबंध को विचार प्रस्तुत नहीं किए हैं ।

ठ.4 प्रकटन के बाद क्षति संबंधी विश्लेषण के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित मुद्दे उठाए गए हैं:-

90. निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा भारतीय बाजार में बिक्री सौदेबाजी प्रक्रिया की कोई जांच नहीं की गई है ।

91. निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा एक्सल और कैमिनोवा के बीच प्रतिस्पर्धा की जांच करने के लिए कोई विश्लेषण नहीं किया गया है।

92. निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यह जानने के लिए कोई जांच नहीं की गई है कि क्या घरेलू उद्योग द्वारा की गई आबद्ध बिक्रियों की कीमत क्या थी और क्या ऐसी आबद्ध बिक्रियों या संबंधित कंपनियों को बिक्रियों को क्षति के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

ठ.5 प्राधिकारी द्वारा जांच

93. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 11 के अनुसार सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए घरेलू उद्योग की क्षति और पाटित आयात तथा क्षति के बीच कारणात्मक संबंध को निर्धारित किया है।

94. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षमता, उत्पादन, बिक्रियों, स्टॉक, बाजार हिस्से जैसे क्षति संबंधी मापदंडों के संबंध में संख्या की दृष्टि से क्षति संबंधी विश्लेषण उचित ढंग से किया गया है।

95. चीन जन.गण.से पाटन की मात्रा की मात्रा और सीमा की जांच करने के बाद प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को हुई क्षति यदि कोई हो और पाटित आयातों तथा घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध की जांच की है। प्राधिकारी मानते हैं कि घरेलू उद्योग के पास पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु के भारतीय उत्पादन का प्रमुख हिस्सा रहा है। अतः क्षति निर्धारण के प्रयोजनार्थ आवेदक कंपनी और समर्थक कंपनी को नियमों के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग माना गया है।

96. अनुबंध-II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम-11 में यह उपबंध है कि किसी क्षति जांच में "..... पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए " ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी जिनसे घरेलू उद्योग को हुई क्षति का पता चल सकता हो। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात की जांच करना आवश्यक है कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है, या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रुकावट आई है, जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती।"

97. प्राधिकारी ने क्षति और कारणात्मक संबंध के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों को नोट किया है और उठाए गए प्रासंगिक मुद्दों का उचित स्थानों पर समाधान किया है। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के तथ्यों और तर्कों को ध्यान में रखते हुए क्षति संबंधी मापदंडों की वस्तुनिष्ठ जांच की है।

98. भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, स्टॉक, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि संबंधित नियमावली के अनुबंध-11 के अनुसार विचार किया गया है।

99. प्रकटन के बाद हितबद्ध पक्षकारों ने यह बताया है कि प्राधिकारी ने घरेलू बाजार में बिक्री सौदेबाजी की प्रक्रिया की जांच नहीं की है और यह कि मै. कैमिनोवा के पास उपभोक्ता उद्योगों के साथ दीर्घावधिक बिक्री संविदाएं हैं जिसमें अंतरनिहित कीमत निर्धारण फार्मूला शामिल होता है। प्राधिकारी यह समुक्ति करते हैं कि कार्यवाही की प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा इस संबंध में ऐसा कोई तर्क नहीं दिया गया था। प्राधिकारी मानते हैं कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार को प्रकटन विवरण के बाद के स्तर पर ऐसे अत्यधिक तथ्यात्मक तर्कों (जिन पर विचार करने के लिए मौके पर सत्यापन की भी जरूरत है) को नहीं उठाना चाहिए। फिर भी प्राधिकारी ने इस मुद्दे की जांच की है और घरेलू उद्योग को वस्तु स्थिति को स्पष्ट करने का निर्देश दिया है और इसी के साथ दीर्घावधिक संविदाओं और संविदात्मक बिक्रियों तथा सामान्य बिक्रियों को अलग-अलग दर्शाने वाले विवरण की प्रतियां प्रस्तुत करने के लिए कहा है। घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना/दस्तावेज से प्राधिकारी यह समुक्ति करते हैं कि जांच अवधि के दौरान मै. कैमिनोवा के पास *** रु. प्रति कि.ग्रा. की भारित औसत दर पर संविदाओं के जरिए ***% की कुल घरेलू बिक्रियां रही हैं और अन्यथा *** रु. प्रति कि.ग्रा. की भारित औसत दर पर ***% बिक्रियां की गई हैं। उपर्युक्त विश्लेषण से प्राधिकारी यह समुक्ति करते हैं कि जांच अवधि के दौरान मै. कैमिनोवा की दोनों तरह की घरेलू बिक्रियों के बीच कीमत निर्धारण के ढांचे में कोई खास अंतर नहीं है। प्राधिकारी आगे यह समुक्ति करते हैं कि घरेलू उद्योग के अन्य संघटक मै. एक्सल की भारित औसत कीमत जांच अवधि के दौरान मै. कैमिनोवा की भारित औसत संविदात्मक कीमत और भारित औसत गैर संविदात्मक कीमत से कम रही है। इसके अलावा, प्राधिकारी द्वारा कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत ह्रास और कीमत न्यूनीकरण की जांच अनन्य रूप से एक्सल के आंकड़ों पर आधारित है और उसमें घरेलू उद्योग के आंकड़ों की जांच करने पर क्षति संबंधी मापदंडों के समान प्रवृत्ति पाई है।

कीमत कटौती

विवरण	इकाई	2004-05	2005-06	2006-07	जांच अवधि
एक्सल पर आधारित कीमत कटौती	रु./किग्रा.	***	***	***	***
घरेलू उद्योग पर आधारित कीमत कटौती	रु./किग्रा.	***	***	***	***
एक्सल पर आधारित कीमत कटौती	%	10-20	15-25	15-25	5-12
घरेलू उद्योग पर आधारित कीमत कटौती	%	10-20	15-25	15-25	7-15

कम कीमत पर बिक्री

विवरण	इकाई	एक्सल	घरेलू उद्योग
पहुंच कीमत	रू./किग्रा.	85.40	85.40
क्षति रहित कीमत	रू./किग्रा.	***	***
कम कीमत पर बिक्री	रू./किग्रा.	***	***
कम कीमत पर बिक्री	%	30-40	35-45

कीमत ह्रास और न्यूनीकरण

विवरण	इकाई	2004-05	2005-06	2006-07	जांच अवधि
बिक्री लागत - एक्सल	रू./किग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106.07	109.94	107.90
बिक्री लागत - घ. उ.	रू./किग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106.60	114.71	110.55
बिक्री कीमत - एक्सल	रू./किग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	99.06	89.57	85.06
बिक्री कीमत - घ.उ.	रू./किग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	101.22	94.67	88.85

100. हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों के मद्देनजर घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन की अलग-अलग जांच की गई है। यह देखा गया है कि कीमत कटौती सकारात्मक है और दोनों कंपनियों में अलग-अलग कीमत न्यूनीकरण प्रदर्शित हुआ है। इसके अलावा, दोनों इकाइयों की लाभप्रदता में भी यही प्रवृत्ति दर्शायी गई है। रिकॉर्ड में उपलब्ध आंकड़ों से यह देखा गया है कि दोनों घरेलू उद्योग की लाभप्रदता की स्थिति खराब हुई है। दोनों इकाइयां आधार वर्ष में लाभ में चल रही थीं और लाभों में तेजी से गिरावट आई और 2006-07 और 07-08 के दौरान दोनों को वित्तीय घाटे उठाने पड़े थे। दोनों कंपनियों के निवेश पर आय आधार वर्ष में सकारात्मक रही थी और जांच अवधि के दौरान यह तेजी से घटकर ऋणात्मक स्तर पर पहुंच गई। इस प्रकार रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना यह नहीं दर्शाती है कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति के संबंध में प्राप्त निष्कर्ष हितबद्ध पक्षकारों द्वारा बताए गए कारणों से इससे अलग हो सकते हैं। इसके विपरीत यदि मै. कैमिनोवा की बिक्री कीमत संविदा आधार पर कथित बिक्री के कारण उच्च रही है तो इसका अर्थ यह है कि कंपनी के वित्तीय घाटे और निवेश पर आय जांच अवधि के दौरान पाए गए स्तरों की तुलना से भी अधिक कम हो गई होती।

101. हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क देते हुए क्षति संबंधी निर्धारण पर भी प्रश्न उठाया है कि बिक्री, बाजार हिस्से, आयात में गिरावट, उत्पादन और क्षमता उपयोग में सुधार के कारण घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में सुधार हुआ है। तथापि, यह पाया गया है कि उन्होंने पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना जांच अवधि के साथ की है और यह मान लिया है कि पाटन केवल

जांच अवधि में ही शुरू हुआ है । यदि प्राधिकारी द्वारा पाटन मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ जांच अवधि तय की जाती तब भी उसका यह अर्थ नहीं है कि पाटन केवल जांच अवधि के दौरान ही हुआ है । कीमत और मात्राओं की प्रवृत्ति वस्तुतः यह दर्शाती है कि पाटन लंबे समय से चल रहा है । अपनी मात्रात्मक क्षति पर काबू पाने के लिए घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के दौरान लाभप्रदता को घटा दिया जिसके परिणामस्वरूप जांच अवधि के दौरान मात्राओं में कुछ वृद्धि हुई है जबकि लाभप्रदता और निवेश पर आय में गिरावट आई है । तथापि, जांच अवधि के दौरान मापदंड पहले दो वर्षों की तुलना में काफी प्रतिकूल रहे हैं । प्राधिकारी के लिए क्षति अवधि के दौरान मौजूद समग्र स्थिति को देखना और तब किसी निष्कर्ष पर पहुंचना अपेक्षित है ।

102. उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि भारतीय बाजार में कीमत प्रतिस्पर्धा के कारण संबंधित पक्षकार एक्सल द्वारा आयात किए जा सकते हैं । इस तरह के तर्क केवल कल्पनाएं हैं और निराधार हैं । जांच अवधि के दौरान भारत में 12361 मी.ट. के कुल आयातों की तुलना में मै. एक्सल क्राप केयर लि. द्वारा किए गए *** मी.ट. के मामूली आयातों जैसा कि डी जी सी आई एंड के आंकड़ों से स्पष्ट है, घरेलू बाजार में कोई कीमत प्रतिस्पर्धा शुरू नहीं कर सकते हैं । जब कोई हितबद्ध पक्षकार यह दावा करता है कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति किसी अन्य कारण से हुई है तो ऐसे अन्य कारक की मौजूदगी को सिद्ध करने और उसके कारण हुई क्षति की मात्रा बताने का दायित्व उस हितबद्ध पक्षकार का ही होता है । यद्यपि, निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए क्षति के अन्य ज्ञात कारक की जांच करना अपेक्षित है और यद्यपि, प्राधिकारी अब भी ऐसे अन्य ज्ञात कारक पर विचार कर सकते हैं, जिन्हें प्राधिकारी की जानकारी में लाया गया है । परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि अन्य असूचीबद्ध कारकों की मौजूदगी की जांच करने और उनके द्वारा हुई क्षति की मात्रा का पता लगाने का दायित्व प्राधिकारी का है जबकि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा कोई समर्थक साक्ष्य और आवश्यक सूचना प्रस्तुत नहीं की गई है । वस्तुतः हितबद्ध पक्षकारों के लिए ऐसे अन्य कारकों की मौजूदगी को दर्शाना और ऐसे किसी अन्य कारक के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति की मात्रा बताना अपेक्षित है ।

103. जहां तक घरेलू उद्योग की आबद्ध बिक्रियों की कीमत और उससे ऐसी आबद्ध बिक्रियों के कारण क्षति की संभावना या संबंधित सत्ताओं को बिक्रियों के कारण क्षति की संभावना का संबंध है, प्राधिकारी यह समुक्ति करते हैं कि मै. एक्सल के पास कोई आबद्ध बिक्री नहीं है । जहां तक मै. कैमिनोवा का संबंध है, उनकी आबद्ध बिक्रियां कुल घरेलू बिक्रियों (*** मी.ट.) की तुलना में काफी मामूली (*** मी.ट.) हैं और इसलिए इनसे क्षति पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ सकता है ।

104. हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क देते हुए क्षति संबंधी निर्धारण पर भी प्रश्न उठाया है कि बिक्री, बाजार हिस्से, आयात में गिरावट, उत्पादन और क्षमता उपयोग में सुधार के कारण घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में सुधार हुआ है । तथापि, यह पाया गया है कि उन्होंने पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना जांच अवधि के साथ की है और यह मान लिया है कि पाटन केवल जांच अवधि में ही

शुरू हुआ है जो सत्य से बहुत दूर है। प्राधिकारी के लिए क्षति अवधि के दौरान मौजूद समग्र स्थिति को देखना और तब किसी निष्कर्ष पर पहुंचना अपेक्षित है।

105. यह विचार कि मै. एक्सल के संबंधित पक्षकार द्वारा किए गए आयातों से भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई होगी, केवल एक कल्पना प्रतीत होता है और यह निराधार है। उस संबंधित पक्षकार द्वारा आयातों की मात्रा शेष आयातों की तुलना में इतनी कम है कि उससे कोई कीमत प्रतिस्पर्धा शुरू नहीं हो सकती है।

ड पाटित आयातों के मात्रात्मक प्रभाव

क) मांग और बाजार हिस्सा

106. प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्रियों तथा सभी स्रोतों से आयातों के जोड़ को भारत में मांग अथवा उत्पाद की अनुमानित खपत के रूप में परिभाषित किया है। इस प्रकार आकलित मांग नीचे तालिका में दी गई है।

मांग	इकाई	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08 (जांच अवधि)
कुल आयात	मी. टन	10,470	8,055	8,758	12,616
बिक्री-घरेलू उद्योग	मी. टन	7,378	6,154	4,622	7,669
मांग	मी. टन	17,848	14,209	13,380	20,285
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	79.61	74.97	113.66

107. उपर्युक्त तालिका से यह देखा गया है कि वर्ष 2005-06 तथा वर्ष 2006-07 के बीच उत्पाद की मांग में अत्यधिक गिरावट आई थी और तत्पश्चात उसमें उल्लेखनीय वृद्धि प्रदर्शित हुई है।

(ख) आयात मात्रा एवं बाजार हिस्सा

108. प्राधिकारी ने (क) याचिकाकर्ता (सहायक स्रोतों से प्राप्त आयात आँकड़ों के आधार पर) (ख) डीजीसीआई एण्ड एस से प्राधिकारी द्वारा प्राप्त सूचना तथा (ग) उत्तर देने वाले निर्यातक द्वारा प्रस्तुत संबद्ध वस्तुओं के आयातों की मात्रा संबंधी आँकड़ों की जांच की है। यह नोट किया गया है कि डीजीसीआई एण्ड एस में सूचित आयातों की मात्रा व्यापक नहीं है, जो इस बात के कारण हो सकता है कि आयातों को अलग-अलग सीमाशुल्क वर्गीकरण में निकासी प्रदान की गई है, जैसा कि सहायक स्रोत के आँकड़ों से देखा जा सकता है। डीजीसीआई एण्ड एस से प्राप्त एक विशिष्ट आयातक से संबंधित सभी आयातों से यह बात पुनः साबित हो गई थी। अतः प्राधिकारी ने सहायक

स्रोतों से प्राप्त सूचना पर विश्वास किया है। रिकॉर्ड में उपलब्ध में विभिन्न आयात आंकड़ों के आधार पर चीन जन.गण. की आयात मात्रा को न्यूनतम सीमा से अधिक पाया गया है।

109. संबद्ध देश एवं अन्य देशों की आयात मात्राएं निम्नानुसार रही हैं :-

आयात मी.ट. में	इकाई	2004-05	2005-06	2006-07	जांच अवधि
चीन जन.गण.	मी.ट.	10,470	8,055	8,620	12,361
अन्य देश	मी.ट.	-	-	138	255
कुल आयात	मी.ट.	10,470	8,055	8,758	12,616

110. यह देखा गया है कि चीन के आयातों में वर्ष 2005-06 में गिरावट आई थी परंतु इसके पश्चात इसमें वृद्धि हुई थी। जांच अवधि के दौरान हुई वृद्धि अत्यधिक उल्लेखनीय थी। यह भी नोट किया गया है कि चीन जन.गण. के आयात भारत में विचाराधीन उत्पाद के कुल आयातों का एक अत्यधिक उल्लेखनीय हिस्सा बनते हैं।

ग) मांग में बाजार हिस्सा

111. भारतीय उत्पादकों को विभिन्न स्रोतों से हुए आयातों एवं बिक्री को देखते हुए भारत में मांग में संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से की जांच की गई है। वास्तविक स्थिति निम्नानुसार है :-

	इकाई	2004-05	2005-06	2006-07	जांच अवधि
घरेलू उद्योग	%	41.34	43.31	34.55	37.81
चीन जन.गण.	%	58.66	56.69	64.42	60.94
अन्य देश	%	0.00	0.00	1.03	1.25

112. यह देखा गया है कि चीन जन.गण. से मांग में पाटित आयातों के बाजार हिस्से में आधार वर्ष में 58.66% की तुलना में जांच अवधि में 60.94% की वृद्धि हुई है तथापि समनुरूपी अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा 41.34% से घटकर 37.81% रह गया। यद्यपि पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई तथा निर्यातों में गिरावट आई तथापि जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा पूर्व में प्राप्त स्तरों से कम था।

(घ) घरेलू उत्पादन के संबंध में पाटित आयातों का हिस्सा

113. प्राधिकारी ने पाया कि घरेलू उद्योग के उत्पादन के संबंध में संबद्ध देश से पाटित आयातों में वृद्धि हुई है, जैसाकि निम्नलिखित तालिका से देखा जा सकता है :-

	इकाई	2004-05	2005-06	2006-07	जांच अवधि
चीन से आयात	मी.ट.	10,470	8,055	8,620	12,361
घरेलू उद्योग का उत्पादन	मी.ट.	9003	7938	6200	9335
घरेलू उद्योग के उत्पादन के संबंध में पाटित आयात	%	116.29	101.47	139.03	132.42

(ड.) क्षमता एवं क्षमता उपयोग

114. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता एवं क्षमता उपयोग को निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है :-

	इकाई	2004-05	2005-06	2006-07	जांच अवधि
क्षमता मी.ट.	मी.ट.	11,500	11,500	11,500	12,000
क्षमता उपयोग %	%	78	69	54	78

115. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में वर्ष 2006-07 तक गिरावट आई, परंतु उसके बाद जांच अवधि के दौरान इसमें वृद्धि हुई। यद्यपि, जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन में पुनः वृद्धि हुई, परंतु इस बात के मद्देनजर कि देश में इस उत्पाद की मांग अत्यधिक है, यह अभी भी बहुत कम है।

च) उत्पादन

116. घरेलू उद्योग के उत्पादन का ब्यौरा निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है :

	इकाई	2004-05	2005-06	2006-07	जांच अवधि
उत्पादन मी.ट. में	मी.ट.	9003	7938	6200	9335
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	88.17	68.87	103.68
मांग	मी.ट.	17,848	14,209	13,380	20,285
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	79.61	74.97	113.66
मांग के संबंध में उत्पादन	%	50.45	55.87	46.34	46.02

117. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के उत्पादन में वर्ष 2006-07 तक गिरावट आई। तथापि, उत्पादन में आई कमी, मांग में आई कमी की तुलना में अधिक थी, जो यह दर्शाता है

कि पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग ने विगत में अत्यधिक बाजार हिस्सा गंवाया । जांच अवधि के दौरान जब मांग में तेजी से वृद्धि हुई, पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग उत्पादन में वृद्धि नहीं कर सका । मांग में जहां लगभग 14% की वृद्धि हुई, वहीं उत्पादन केवल 6% बढ़ा ।

छ) बिक्री मात्रा

118. घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा का ब्यौरा निम्नलिखित तालिका में दिया गया है :-

	इकाई	2004-05	2005-06	2006-07	जांच अवधि
घरेलू बिक्री	मी.ट.	7378	6154	4622	7670
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	83.41	62.65	103.96
मांग	मी.ट.	17,848	14,209	13,380	20,285
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	79.61	74.97	113.66
मांग में घरेलू उद्योग का हिस्सा	%	41.34	43.31	34.55	37.81

119. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग की बिक्री में वर्ष 2006-07 तक तेजी से गिरावट आई थी, तथापि बिक्री में आई गिरावट, मांग में आई गिरावट से कहीं अधिक थी । इसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को काफी बाजार हिस्सा गंवाना पड़ा । उत्पाद की मांग में जांच अवधि के दौरान उल्लेखनीय वृद्धि हुई । इसके बावजूद घरेलू उद्योग अपने उत्पादन और बिक्री की सीमा तक अपनी बिक्री की मात्रा में वृद्धि करने में असमर्थ रहा । वास्तव में बाजार हिस्सा भी बढ़कर पूर्ववर्ती स्तर पर नहीं आ सका था । पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की बिक्री प्रभावित हो रही है ।

ढ. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

क. कीमत कटौती

120. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी के लिए इस बात पर विचार करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों से भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव अन्यथा कीमतों को महत्वपूर्ण सीमा तक कम करना अथवा कीमत में वृद्धि को रोकना था जो अन्यथा एक महत्वपूर्ण सीमा तक हो गई होती । इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ भारित औसत उत्पादन लागत (सी ओ पी), भारित औसत निवल बिक्री प्राप्ति (एन एस आर) तथा घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत (एन आई पी) की तुलना संबद्ध देशों से हुए आयातों की पहुंच लागत से की गई है ।

121. निवल बिक्री प्राप्ति सभी छूटों एवं करों को घटाने के बाद ज्ञात की गई है। आयातों के पहुंच मूल्य की गणना हेतु संबद्ध आयातों के सी आई एफ मूल्य में 1 प्रतिशत का प्रहस्तन प्रभार तथा लागू मूल सीमाशुल्क को उसमें जोड़ दिया गया है। आयातों के पहुंच मूल्य की तुलना घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति से की गई और यह पाया गया कि पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमत में कटौती हो रही है।

घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति के आधार पर कीमत कटौती:

विवरण	इकाई	2004-05	2005-06	2006-07	जांच अवधि
सीआईएफ निर्यात कीमत	रु./किग्रा.	76.98	72.18	67.22	78.49
आयातों की पहुंच कीमत	रु./किग्रा.	93.61	84.06	76.64	85.40
निवल बिक्री प्राप्ति	रु./किग्रा.	***	***	***	***
कीमत कटौती	रु./किग्रा.	***	***	***	***
कीमत कटौती %	%	10-20	15-25	15-25	7-15
बिक्री की लागत	रु./किग्रा.	***	***	***	***

122. इसके अलावा, निम्नांकित तालिका से यह देखा गया है कि केवल मै. एक्सल इंडस्ट्रीज लि. के आंकड़ों के आधार पर की गई गणना के अनुसार और कुछेक अलग-अलग सहयोगी आयातकों के आंकड़ों के आधार पर की गई गणना, दोनों में कीमत कटौती सकारात्मक है अतः प्रकटन के बाद हितबद्ध पक्षकारों का यह आरोप कि मै. कैमिनोवा के पास दीर्घावधिक संविदाएं हैं जिनमें अंतर्निहित कीमत निर्धारण फॉर्मूला है और इसलिए घरेलू उद्योग के दोनों घटकों के लिए समग्र रूप से कीमत निर्धारण के आधार पर परिकलित कीमत कटौती त्रुटिपूर्ण है, सही नहीं है।

मै. एक्सल इंडस्ट्रीज लि. के आंकड़ों पर आधारित कीमत कटौती

विवरण	इकाई	2004-05	2005-06	2006-07	जांच अवधि
सीआईएफ आयात कीमत	रु./किग्रा.	76.98	72.18	67.22	78.49
आयातों की पहुंच कीमत	रु./किग्रा.	93.61	84.06	76.64	85.40
निवल बिक्री प्राप्ति	रु./किग्रा.	***	***	***	***
कीमत कटौती	रु./किग्रा.	***	***	***	***
कीमत कटौती %	%	10-20	15-25	15-25	5-12

जांच अवधि के लिए अलग-अलग आयातकों के आंकड़ों पर आधारित कीमत कटौती

विवरण	इकाई	मेघमणि	गर्दा	भगीरथ
-------	------	--------	-------	-------

सीआईएफ आयात कीमत	अम. डॉ./कि.ग्रा.	***	***	***
आयातों की पहुंच कीमत	अम. डॉ./कि.ग्रा.	***	***	***
घरेलू उद्योग से खरीद कीमत	रु./कि.ग्रा.	***	***	***
घरेलू उद्योग से खरीद कीमत	अम. डॉ./कि.ग्रा.	***	***	***
कीमत कटौती	अम. डॉ./कि.ग्रा.	***	***	***
कीमत कटौती	रु./कि.ग्रा.	***	***	***
कीमत कटौती %	%	5-15	1-10	10-20

123. उपर्युक्त तालिका से यह देखा गया है कि आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही है। यह भी नोट किया गया है कि वर्ष 2006-07 के दौरान भारी बाजार हिस्सा गंवाए जाने पर घरेलू उद्योग ने अपने बाजार हिस्से को पुनः प्राप्त करने की दृष्टि से आयातित उत्पाद और घरेलू उत्पाद के बीच के कीमत अंतर को कम किया है जिसके परिणामस्वरूप जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में सुधार हुआ है।

ख) कम कीमत पर बिक्री

124. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कम कीमत पर बिक्री क्षति के आकलन का एक महत्वपूर्ण सूचक है। कम कीमत पर की गई बिक्री की सीमा ज्ञात करने के लिए क्षति रहित कीमत ज्ञात की गई और इसकी तुलना संबद्ध वस्तुओं के पहुंच मूल्य से की गई। घरेलू उत्पादकों के लिए क्षति रहित कीमत का आकलन प्राधिकारी पद्धति के अनुसार तथा उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए किया गया है। विश्लेषण से ज्ञात होता है कि संबद्ध आयातों का पहुंच मूल्य क्षति रहित कीमत से बहुत कम था, जिसका निर्धारण निम्नानुसार किया गया है :-

विवरण	रु./कि.ग्रा.
सीआईएफ कीमत	78.49
पहुंच कीमत	85.40
क्षति रहित कीमत	***
कम कीमत पर बिक्री	***
कम कीमत पर बिक्री रेंज (%)	35-45

ग) कीमत ह्रास/न्यूनीकरण

125. कीमत ह्रास तब मौजूद होता है जब उद्योग की कीमतें पूर्ववर्ती अवधि के स्तर से कम

रही हो। कीमत न्यूनीकरण तब विद्यमान होता है जब पाटन के कारण कीमत में वृद्धि रुक जाती है जो अन्यथा लागत में वृद्धि के कारण बढ़ गई होती।

विवरण	इकाई	2004-05	2005-06	2006-07	जांच अवधि
बिक्री की लागत	रु/ किग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106.60	114.71	110.55
बिक्री कीमत	रु/ किग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	101.22	94.67	88.85

126. उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि कीमत हास हुआ है। चूंकि जांच अवधि के दौरान उद्योग की कीमत पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान कीमत की तुलना में कम रही है। इसके अलावा, कीमत न्यूनीकरण भी हुआ है क्योंकि पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान बिक्री लागत में कटौती का अनुपात 4% है जबकि इसी अवधि के दौरान बिक्री कीमत में 6% तक की कमी की गई है।

127. उपर्युक्त विश्लेषण यह दर्शाता है कि पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल मात्रात्मक और कीमत प्रभाव पड़ा है। यह प्रभाव पाटित आयातों की मात्रा में समग्र और सापेक्ष दृष्टि से वृद्धि के अनुसार और घरेलू बाजार कीमत को कम करके पड़ा है जिससे घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा छिन गया है।

घ) लाभ/हानि

128. घरेलू उद्योग की लाभप्रदता का ब्यौरा निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:-

	इकाई	2004-05	2005-06	2006-07	जांच अवधि
कर पूर्व लाभ (पीबीटी)	लाख रुपए	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	46.57	-53.30	-
					105.53
कर तथा ब्याज पूर्व लाभ (पीबीआईटी)	लाख रुपए	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	62.83	-28.33	-63.71
ब्याज पूर्व लाभ (पीबीआईटी)	रु./किग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	75.33	-45.21	-61.28
कर पूर्व लाभ (पीबीटी)	रु./मी.ट.	***	***	***	***

प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100.00	54.33	-79.92	-	100.16
-----------	----------	--------	-------	--------	---	--------

129. उपर्युक्त तालिका से यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में उल्लेखनीय गिरावट आई। घरेलू उद्योग जहां पहले लाभ अर्जित कर रहा था (चाहे लाभ का स्तर कम रहा हो), उसे वर्ष 2006-07 से वित्तीय घाटा शुरू हो गया। यद्यपि याचिकाकर्ता ने स्वीकार किया है कि वर्ष 2006-07 के दौरान उसका घाटा एक अतिरिक्त कारक अर्थात् उत्पादन में कमी (मांग में आई कमी के कारण) के कारण हुआ था, तथापि यदि इस कारक को समायोजित किया जाए तो यह देखा जा सकता है कि जांच अवधि के दौरान लाभप्रदता में बहुत ही तेजी से गिरावट आई।

ण. क्षति से संबंधित अन्य मापदंडों की जांच

130. घरेलू उद्योग की मात्रा एवं कीमतों पर पाटित आयातों और आयातों की मात्रा तथा मूल्य, क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग एवं घरेलू उद्योग की बिक्री तथा विभिन्न खंडों के बाजार हिस्सों के मांग के पैटर्न जैसे क्षति के प्रमुख सूचकों के प्रभाव की जांच के बाद प्राधिकारी द्वारा अन्य आर्थिक मानदंडों, जो घरेलू उद्योग को हुई क्षति के अस्तित्व को इंगित कर सकते हैं, की जांच भी निम्नानुसार की गई है:-

क) नियोजित पूंजी पर आय

131. नियोजित पूंजी पर आय से संबंधित सूचना नीचे तालिका में दी गई है:-

	इकाई	2004-05	2005-06	2006-07	जांच अवधि
नियोजित कर्मचारियों पर आय - एनएफए आधार	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	64.38	-40.04	-81.14

132. प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के लिए नियोजित पूंजी पर आय में इस सीमा तक गिरावट आई कि वह वर्ष 2006-07 तथा जांच अवधि में ऋणात्मक हो गई थी।

ख) नकद प्रवाह

133. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के नकद प्रवाह की स्थिति पर पाटन के प्रभाव की जांच करने के लिए नकद लाभ की प्रवृत्ति की जांच की है। घरेलू उद्योग के नकद लाभ से संबंधित सूचना निम्नलिखित तालिका में दी गई है।

	इकाई	2004-05	2005-06	2006-07	जाँच अवधि
नकद लाभ	लाख रुपए	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	65.57	1.43	-23.50

134. यह देखा जा सकता है कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के नकद लाभों में तेजी से गिरावट आई। यह कमी प्रत्येक वर्ष निरंतर जारी रही और इस सीमा तक पहुँच गई कि जाँच अवधि में घरेलू उद्योग को नकद हानि का सामना करना पड़ा।

ग) घरेलू उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक

135. पाटित आयातों से इतर अन्य कारकों, जो घरेलू बाजार में कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं, के विश्लेषण के लिए लागत संरचना में परिवर्तन, घरेलू उद्योग में प्रतिस्पर्धा और प्रतिस्पर्धी स्थानापन्नों की जाँच की गई है। संबद्ध आयातों की पहुँच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है। अतः यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि आपसी प्रतिस्पर्धा इतनी अधिक है कि उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की कीमतों में कमी आई।

घ) मालसूचियां

136. आधार वर्ष की तुलना में घरेलू उद्योग की मालसूची धारिता में गिरावट आई है। तथापि, जैसा कि निम्नांकित तालिका से देखा जा सकता है कि पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में जाँच अवधि के दौरान इसमें वृद्धि हुई है।

विवरण	इकाई	2004-05	2005-06	2006-07	जाँच अवधि
प्रारंभिक स्टॉक	मी.ट.	458	502	403	369
अंतिम स्टॉक	मी.ट.	502	403	369	421
औसत स्टॉक	मी.ट.	480	452	386	395

ड) लाभप्रदत्ता

137. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग की उत्पादकता की प्रवृत्ति उत्पादन की प्रवृत्ति के समान रही है। वर्ष 2006-07 तक उत्पादकता में कमी आई लेकिन जाँच अवधि के दौरान उसमें वृद्धि हुई।

	इकाई	2004-05	2005-06	2006-07	जाँच अवधि
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	85.25	72.17	110.63

प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	88.17	68.87	103.68

च) रोजगार और मजदूरी

138. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्ष 2005-06 को छोड़कर क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के रोजगार में गिरावट आई है जबकि प्रदत्त मजदूरी पूर्ववर्ती वर्ष तथा आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान वृद्धि की प्रवृत्ति प्रदर्शित होती है ।

	इकाई	2004-05	2005-06	2006-07	जांच अवधि
रोजगार	सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	103.43	95.43	93.71
मजदूरी	लाख रुपए	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	97.34	79.76	142.67

छ) वृद्धि

139. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्ष 2006-07 तक अनेक मानदंडों पर घरेलू उद्योग की वृद्धि नकारात्मक थी जिसका आंशिक कारण माँग में कमी होना था । यद्यपि जाँच अवधि में मात्रा संबंधी मानकों में वृद्धि सकारात्मक थी तथापि वह माँग में वृद्धि से कम थी । किसी भी स्थिति में कीमत संबंधी मानदंडों में वृद्धि निरंतर नकारात्मक ही रही ।

ज) पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

140. प्रारंभिक जांच परिणामों में यह उल्लेख किया गया था कि घरेलू उद्योग द्वारा कोई बड़ा निवेश नहीं किया गया है । परंतु घरेलू उद्योग के आंकड़ों के सत्यापन के बाद यह देखा गया था कि घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के दौरान *** लाख रुपए मूल्य का निवेश किया है । तथापि, इस उत्पाद के लगातार पाटन से निश्चित रूप से पूंजी निवेश जुटाने की घरेलू उद्योग की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा होगा ।

त. विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए अन्य मुद्दों की जांच

141. याचिका में अनेक मानदंडों से संबंधित सूचना के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि दायर की गई याचिका में विभिन्न क्षति मानदंडों के संबंध में अलग-अलग सूचना दी गई है । किसी भी प्रकार से याचिकाकर्ता द्वारा आबद्ध खपत बहुत अधिक उल्लेखनीय नहीं है । इसके अतिरिक्त

याचिका में मालसूचियों, लाभ, रोजगार तथा विस्तार हेतु पूँजीगत निवेश के संबंध में सूचीबद्ध आधार पर सूचना शामिल हैं।

142. प्राधिकारी नोट करते हैं कि गत वर्ष की तुलना में जाँच अवधि के दौरान उत्पाद की माँग में पर्याप्त वृद्धि हुई है। वास्तव में याचिकाकर्ता ने अपने आवेदन में आरोप लगाया है कि वर्ष 2006-07 में माँग में उल्लेखनीय गिरावट आई थी जिसके कारण बिक्री मात्रा में कमी आई।

143. तथापि यह नोट किया जाता है कि क्षति अवधि के दौरान उत्पादन तथा खपत की तुलना में आयातों में सापेक्ष रूप से वृद्धि हुई है। यद्यपि पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में जाँच अवधि में आयातों के बाजार हिस्से में कमी आई तथापि यह पिछले वर्षों की तुलना में फिर भी अधिक है।

144. जाँच अवधि में कीमतों में वृद्धि के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति अवधि के दौरान कीमतों में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है। यहाँ तक कि जाँच अवधि में भी कीमतें *** रूपए प्रति किग्रा. के निम्न स्तर से बढ़कर *** रूपए प्रति किग्रा. के स्तर पर पहुँच गई थीं। समग्र आयात कीमत में ***% की वृद्धि का अर्थ यह नहीं है कि घरेलू उद्योग पर आयातों का प्रतिकूल प्रभाव नहीं हो रहा है।

145. उत्पादन, बिक्री तथा क्षमता उपयोग के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षमता उपयोग का स्तर पाटित आयातों की अनुपस्थिति में घरेलू उद्योग द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले स्तर से बहुत कम है। इसके अतिरिक्त घरेलू उद्योग द्वारा प्राप्त की गई मात्रा पर उस कीमत के साथ विचार किया जाना चाहिए जिस पर उस वस्तु की बिक्री की गई है। यह नोट किया गया है कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में तेजी से गिरावट आई।

146. हालांकि इस पर ध्यान दिया गया है कि उत्पाद की माँग में वृद्धि हुई है, यह नोट किया गया है कि घरेलू उद्योग पाटित आयातों की अनुपस्थिति में अप्रयुक्त क्षमताओं का प्रयोग करके और अधिक मात्रा का उत्पादन तथा बिक्री कर सकता था। यह नोट किया गया है कि वर्ष 2004-05 और जाँच अवधि के बीच आयातों में 2146 मी. टन की वृद्धि हुई थी जबकि घरेलू उद्योग की अप्रयुक्त क्षमता 2665 मी. टन थी। दूसरे शब्दों में यदि उस अवधि में पाटित आयातों में वृद्धि न हुई होती तो घरेलू उद्योग अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग कर सकता था। अतः यह नहीं माना जा सकता है कि आयातों में समस्त वृद्धि का कारण देश में कमी का होना था। किसी भी स्थिति में लाभ/हानि, निवेश पर आय तथा नकद लाभ जैसे मानदंडों के रूप में घरेलू उद्योग के निष्पादन में कमी आई।

147. प्रस्तावित पाटनरोधी शुल्क के अधिरोपण के परिणामस्वरूप कीटनाशकों के उत्पादन में घरेलू उद्योग को कथित रूप से अनुचित लाभ मिलने के संबंध में प्राधिकारों का मत है कि पाटनरोधी शुल्क का प्रयोजन अनुचित कीमत निर्धारण को समाप्त करना है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों के विपरीत यह कहा जा सकता है कि अन्य कीटनाशक विनिर्माताओं की

अनुचित कीमत वाले आयातों तक पहुंच उन्हें उन विनिर्माताओं की तुलना में अनुचित लाभ दे रही है जो डी ई टी पी सी का स्वयं आबद्ध उत्पादन कर रहे हैं ।

148. वर्ष 2006-07 की तुलना में 2007-08 के दौरान कीमत कटौती में कमी वर्ष 2006-07 में आयातों में अत्यधिक वृद्धि के कारण हुई, जब मांग बढ़ गई थी और घरेलू उद्योग ने बाजार हिस्सा गंवा दिया था । घरेलू उद्योग का तर्क है कि वर्ष 2006-07 के दौरान बाजार हिस्से के नुकसान के कारण घरेलू उद्योग ने सुधारात्मक कार्रवाई करते हुए घरेलू एवं आयातित उत्पाद के कीमत अन्तर को कम कर दिया जिसका परिणाम जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में हुई वृद्धि के रूप में देखा जा सकता है । तथापि यह स्पष्ट है कि जहां क्षति अवधि के दौरान मांग में 2438 मी. टन की वृद्धि हुई, वहीं घरेलू उद्योग की बिक्री में केवल 292 मी. टन की वृद्धि हुई, जबकि आयातों में 2146 मी. टन की वृद्धि हुई थी । साथ ही, जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के पास 2665 मी. टन की अप्रयुक्त क्षमता थी । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि ऐसी स्थिति में जब घरेलू उद्योग के पास मांग में हुई वृद्धि के बराबर अप्रयुक्त क्षमता उपलब्ध थी, तब मांग में हुई समस्त वृद्धि पर पाटित आयातों ने कब्जा कर लिया ।

149. जहां तक इस तर्क का संबंध है कि याचिकाकर्ता को "अन्य कारकों" के कारण घाटा हुआ होगा अथवा लाभ कम हुआ होगा, प्राधिकारी के ध्यान में ऐसा कोई "अन्य कारण" नहीं लाया गया । जाँच के दौरान अब तक ऐसा कोई अन्य कारक नहीं देखा गया, जिसने घरेलू उद्योग की लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला हो ।

थ. क्षति संबंधी निष्कर्ष

150. क्षति से संबंधित विभिन्न मानदण्डों की जांच से प्राधिकारी ने देखा है कि चीन से हुए आयातों में निरपेक्ष रूप से तथा भारत में उत्पादन एवं खपत के सापेक्ष वृद्धि हुई । उत्पाद के आयातों से बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही थी । इसके अलावा जहां क्षति अवधि के दौरान बिक्री कीमतों में बढ़ोतरी होने के बावजूद उत्पादन लागत में वृद्धि होती रही, वहीं उत्पादन लागत में वृद्धि बिक्री कीमत में हुई वृद्धि से बहुत ही कम थी । इस प्रकार आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में मन्दी आई और कीमत वृद्धि पर रोक लग गई जिनमें अन्यथा पाटित आयातों के अभाव में वृद्धि हुई होती । घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में यह पाया गया कि उत्पाद की मांग में वर्ष 2006-07 तक अत्यधिक गिरावट आई और इसके परिणामतः 2006-07 तक घरेलू उद्योग के उत्पादन और बिक्री में भी गिरावट आई । इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2006-07 तक घरेलू उद्योग को बाजार हिस्से में उल्लेखनीय नुकसान का सामना करना पड़ा । यद्यपि जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग ने कुछ बाजार हिस्सा फिर हासिल कर लिया था, तथापि यह पहले दर्ज स्तर की तुलना में बहुत ही कम था ।

151. ऐसी स्थिति में जब बाजार में इस उत्पाद की मांग बहुत अधिक थी, घरेलू उद्योग को अप्रयुक्त क्षमता का सामना करना पड़ा । घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में निरंतर गिरावट आई और इतनी तेजी से आई कि घरेलू उद्योग को 2006-07 से वित्तीय घाटा होने लगा, जो जांच अवधि के

दौरान और भी बढ़ गया। नियोजित पूंजी से आय और नकद लाभ का रुख भी वही था जो लाभ का था। जांच अवधि के दौरान नियोजित पूंजी से आय और नकद लाभ दोनों नकारात्मक हो गए। वर्ष 2006-07 तक घरेलू उद्योग की वृद्धि अनेक मानदण्डों के संदर्भ में नकारात्मक थी, जो तत्पश्चात् मात्रात्मक मानदण्डों (हालांकि घरेलू उद्योग पाटन के अभाव में अधिक मात्रा प्राप्त कर सकता था) के संदर्भ में सकारात्मक हो गई। तथापि कीमत संबंधी मानदण्डों के संदर्भ में वृद्धि सदैव नकारात्मक बनी रही। इस प्रकार अनन्तिम रूप से यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

द. कारणात्मक संबंध और अन्य कारक

152. वास्तविक क्षति की मौजूदगी और घरेलू उद्योग की कीमतों पर कीमत कटौती, कम कीमत पर बिक्री, कीमत न्यूनीकरण और कीमत हास प्रभावों की दृष्टि से पाटित आयातों के मात्रात्मक और कीमत प्रभावों की जांच करने के बाद भारतीय नियमावली और पाटनरोधी करार के अंतर्गत सूचीबद्ध अन्य संकेतात्मक मापदंडों की जांच यह देखने के लिए की गई है कि क्या पाटित आयातों के अलावा इनमें से कोई कारक घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा सकता है। तदनुसार निम्नलिखित मापदंडों की जांच की गई है:-

(क) तीसरे देश से आयातों की मात्रा एवं कीमतें

153. प्राधिकारी नोट करते हैं कि अन्य देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयात नगण्य हैं। तीसरे देश से हुए आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती थी।

(ख) व्यापार प्रतिबंधात्मक पद्धतियां एवं विदेशी तथा घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा

154. प्राधिकारी ने ऐसी कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक पद्धति नहीं देखी जिसे घरेलू उद्योग तथा अन्य भारतीय उत्पादकों ने अपनाया हो। प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध वस्तु मुक्त रूप से आयात योग्य है और घरेलू बाजार में कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक पद्धति नहीं है।

(ग) मांग में संकुचन एवं खपत की पद्धति में परिवर्तन

155. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान उत्पाद की मांग में अत्यधिक गिरावट आई। परिणामतः घरेलू उद्योग की बिक्री की मात्रा और उसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग पर इस अवधि तक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। तथापि, यह भी नोट किया गया कि घरेलू उद्योग की बिक्री की मात्रा में गिरावट इस उत्पाद की मांग में आई गिरावट से अधिक थी। जांच अवधि के दौरान मांग में एक बार फिर उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। यद्यपि घरेलू उद्योग ने कुछ बाजार हिस्सा फिर हासिल कर लिया था, परंतु यह पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में बहुत कम था। इसके अलावा, क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में

निरंतर गिरावट आती रही। अतः प्राधिकारी का निष्कर्ष है कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति मांग में संकुचन के कारण नहीं हुई।

(घ) प्रौद्योगिकी विकास

156. इस उत्पाद की उत्पादन प्रौद्योगिकी में कोई विकास नहीं हुआ है। अतः प्रौद्योगिकी का सम्भावित विकास घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण नहीं है।

(ङ) घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन

अवधि	2004-05	2005-06	2006-07	जांच अवधि
मात्रा मी.ट. में	***	***	***	***
सूचीबद्ध	100	96	96	122

157. उत्पाद के सन्दर्भ में घरेलू उद्योग का कोई उल्लेखनीय निर्यात कार्यकलाप नहीं है। तथापि निर्यात निष्पादन में वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान गिरावट आई और आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान इसमें वृद्धि देखी गई। अतः निर्यात निष्पादन में संभावित गिरावट घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण नहीं है। तथापि प्राधिकारी ने कीमत संबंध मानदण्डों पर प्रभाव का आकलन करने के उद्देश्य से केवल घरेलू प्रचालनों पर ही विचार किया है।

(च) घरेलू उद्योग की उत्पादकता

158. घरेलू उद्योग की उत्पादकता में 2006-07 तक गिरावट आई परंतु उसके बाद जांच अवधि के दौरान इसमें वृद्धि हुई। तथापि उत्पादकता के स्तरों में हुए परिवर्तनों के बावजूद घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में निरंतर गिरावट देखी गई।

159. उपर्युक्त गैर-आरोपण विश्लेषण यह दर्शाता है कि पाटित आयातों के अलावा, किसी अन्य ज्ञात कारक से घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है।

छ: कारणात्मक संबंध को स्थापित करने वाले कारक

160. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में वास्तविक गिरावट आई। पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध को निम्नलिखित आधारों पर सिद्ध किया जाता है :-

(क) आयातों के परिणामस्वरूप बाजार में कीमत कटौती हुई। परिणामतः ऐसी स्थिति में भी, जब घरेलू उद्योग के पास अप्रयुक्त क्षमता उपलब्ध थी, आयातों में वृद्धि होती रही।

(ख) घरेलू उद्योग द्वारा की जा रही कीमत कटौती के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जब घरेलू उद्योग को अपनी बिक्री कीमतों में जांच अवधि के दौरान उत्पादन लागत में हुई कमी के अनुपात से अधिक कटौती करने के लिए बाध्य होना पड़ा।

(ग) पाटित आयातों से हुए कीमत ह्रास के परिणामस्वरूप लाभप्रदता में गिरावट इस सीमा तक आई कि घरेलू उद्योग, जो वर्ष 2005-06 तक लाभ अर्जित कर रहा था, वर्ष 2006-07 से वित्तीय घाटे का सामना करने लगा, जो जांच अवधि के दौरान और भी बढ़ गया।

(घ) पाटित आयातों के कारण लाभप्रदता में आई गिरावट से नियोजित पूंजी से प्राप्त आय, नकद लाभ और परिणामतः नकद प्रवाह के रूप में घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन में भी गिरावट आई।

161. अतः प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है और घरेलू उद्योग को यह क्षति संबद्ध देश से पाटित आयातों के मात्रा और कीमत प्रभावों के कारण हुई है।

ज. क्षति की सीमा एवं क्षति मार्जिन

162. प्राधिकारी का अभिमत है कि उपर्युक्त आधार, पाटित आयातों और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के अस्तित्व को स्पष्ट रूप से सिद्ध करते हैं :

	इकाई	यांगजिन चेतियान	लियोनयुग लेबियान	जिंगताईपेस्टीसाइडटस	झेजियांग जियानोंग	असहयोगी
क्षति रहित कीमत	अम.डॉ./किग्रा.	***	***	***	***	***
आयातकों की पहुंच कीमत	अम.डॉ./किग्रा.	***	***	***	***	***
क्षति मार्जिन	अम.डॉ./किग्रा.	***	***	***	***	***
क्षति मार्जिन	रेंज %	50-60	30-40	15-25	30-40	85-95

झ. निष्कर्ष:

163. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों एवं किए गए निवेदनों तथा प्राधिकारी के पास उपलब्ध तथ्यों, जिन्हें इस जांच परिणाम में दर्ज किया गया है, की जांच करने पर प्राधिकारी अनन्तिम रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि :-

- (क) चीन जन.गण. द्वारा भारत को विचाराधीन उत्पाद का निर्यात इसके सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर किया गया है, जिसकी परिणति उत्पाद के पाटन में हुई है।
- (ख) विचाराधीन उत्पाद के पाटन के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।
- (ग) वास्तविक क्षति चीन जन.गण. से पाटित आयातों के कारण हुई है।

ट. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे

ट.1 हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दे

164. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित मुद्दे उठाए गए थे:-

क) घरेलू मांग और घरेलू उत्पादन तथा बिक्रियों के बीच भारी अंतर है। इस प्रकार संबद्ध देश से विशेष रूप से इस तथ्य के मद्देनजर संबद्ध वस्तुओं का आयात आवश्यक है कि भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात केवल चीन जन.गण. और अब डेनमार्क से किया जाता है।

ख) अधिकांश सामान्य फसलों के लिए आम तौर पर प्रयोग की जाने वाली और लोकप्रिय कीटनाशी उत्पादों जैसे क्लोर पाइरोफोस, कीनलफोस, प्रोपेनोफोस, ट्राइजोफोस और अनिलोफोस की लागत में प्रारंभिक जांच परिणामों में प्राधिकारी द्वारा अनुशंसित उच्च पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के कारण कम से कम 15 से 20% की वृद्धि हो जाएगी और इस प्रकार किसानों के हित प्रभावित होंगे।

ग) चीन जन.गण. से डी टी पी सी के आयातों पर प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की स्थिति में भारतीय निर्यातकों को अपनी कीमतों में कम से 5 से 7% की वृद्धि करनी होगी और इसलिए वे विश्व भर में अन्य निर्यातकों की तुलना में अपनी प्रतिस्पर्धी बढ़त को गंवा देंगे। इससे देश के तौर पर भारत के गिरते हुए निर्यात निष्पादन की स्थिति और बदतर हो जाएगी।

घ) अनेक भारतीय कंपनियां ऐसे उत्पाद जैसे क्लोर पाइरोफोस, कीनलफोस, प्रोपेनोफोस, ट्राइजोफोस और अनिलोफोस का विनिर्माण करती हैं जिनमें डी टी पी सी एक प्रमुख कच्ची सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाता है। याचिकाकर्ता के हित के संरक्षण के लिए उन 20 या उससे अधिक विनिर्माताओं को दंडित करना विवेकपूर्ण नहीं होगा जो इस उत्पाद का प्रयोग करते हैं।

ङ) दोनों भारतीय उत्पादक मिलकर घरेलू मांग को पूरा नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना नुकसानदायक होगा और इससे घरेलू बाजार में डी टी पी सी की कमी हो जाएगी।

ट.2 प्राधिकारी द्वारा जांच

165. प्राधिकारी नोट करते हैं पाटनरोधी शुल्कों का उद्देश्य आम तौर पर पाटन की अनुचित व्यापारिक प्रथाओं द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति बहाल की जा सके जो देश के सामान्य हित में पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से संबद्ध देश से आयात किसी भी तरह से प्रतिबंधित नहीं होंगे और इसलिए उपभोक्ताओं को इस उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी। पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का उद्देश्य आयातों को रोककर घरेलू बाजार में दुर्लभता उत्पन्न करना नहीं है। वस्तुतः संबद्ध वस्तुएं मुक्त रूप से आयात योग्य हैं और यदि संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क लगाया भी जाता है तो संबद्ध वस्तु का आयात मुक्त रूप से होना जारी रहेगा। पाटनरोधी शुल्क का मौलिक सिद्धांत पाटन को रोकना है और उचित व्यापारिक प्रथाएं सुनिश्चित करना है तथा पाटन का सहारा लेने वाले विदेशी उत्पादकों/निर्यातकों के विरुद्ध घरेलू उत्पादकों को समान प्रतिस्पर्धा का अवसर प्रदान करना है।

166. यह स्वीकार किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क के अधिरोपण से संबद्ध वस्तु के प्रयोग से विनिर्मित उत्पादों के कीमत स्तर प्रभावित होंगे और परिणामस्वरूप इन उत्पादों की सापेक्ष प्रतिस्पर्धात्मकता पर कुछ प्रभाव पड़ेगा। तथापि, पाटनरोधी उपायों से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा में कमी नहीं होगी, विशेष रूप से तब जब कि पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण घरेलू उद्योग की क्षति के निवारण हेतु आवश्यक राशि तक सीमित है। इसके विपरीत पाटनरोधी उपायों के अधिरोपण से पाटन प्रथाओं से हुए अनुचित लाभ समाप्त होंगे, घरेलू उद्योग की गिरावट रुकेंगी और संबद्ध वस्तु के उपभोक्ताओं के लिए अधिक विकल्प बनाए रखने में सहायता मिलेगी। पाटनरोधी उपाय लागू किए जाने से संबद्ध देशों से आयात किसी भी रूप में प्रतिबंधित नहीं होंगे और इससे उपभोक्ताओं को इस उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।

ठ. सिफारिशें

167. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरुआत की सूचना सभी हितबद्ध पक्षकारों को दी गई थी और पाटन, क्षति तथा कारणात्मक संबंध के विभिन्न पहलुओं पर सकारात्मक जानकारी प्रस्तुत करने के लिए निर्यातकों, आयातकों तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को समुचित अवसर दिया गया था। निर्धारित नियमों के अनुसार पाटन, क्षति तथा पाटन एवं घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कारणात्मक संबंध पर प्रारंभिक जांच शुरू करके पूर्ण करने के बाद और संबद्ध देशों के विरुद्ध सकारात्मक पाटन मार्जिन की अनंतिम रूप से पुष्टि करने के बाद तथा यह निष्कर्ष निकालने के पश्चात कि ऐसे पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है, प्राधिकारी का विचार है कि जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को हो रही क्षति को रोकने के लिए अनंतिम उपाय लागू करने की आवश्यकता है। अतः प्राधिकारी संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयात पर निम्नलिखित रूप में और तरीके से अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लागू करना आवश्यक समझते हैं और उसकी सिफारिश करते हैं।

168. प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए कमतर शुल्क के नियम को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी, पाटन मार्जिन तथा क्षति मार्जिन, जो भी कम हो, के बराबर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त किया जा सके। तदनुसार केन्द्र सरकार द्वारा ये सिफारिशें स्वीकार कर लिए जाने की स्थिति में चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के सभी आयातों पर इस अधिसूचना की तिथि से इसके साथ संलग्न शुल्क तालिका के कॉलम 8 में दी गई राशि के बराबर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की जाती है।

क्र.सं.	शीर्ष/उपशीर्ष	वस्तु विवरण	उद्गम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	शुल्क राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	29.30	डाई ईथाइल थायो फॉस्फोराइल क्लोराइड (डीईटीपीसी)	चीन जन.गण.	चीन जन.गण.	यांगजिन चेन्शियान केमिकल्स इंडस्ट्री कं. लि.	यांगजिन चेन्शियान केमिकल्स इंडस्ट्री कं. लि.	1.024	प्रति कि.ग्रा.	अम.डॉ.
2	29.30	डाई ईथाइल थायो फॉस्फोराइल क्लोराइड (डीईटीपीसी)	चीन जन.गण.	चीन जन.गण.	लियानयूनगांग लिबेन एग्रो केमिकल्स कं.लि.	लियानयूनगांग लिबेन एग्रो केमिकल्स कं.लि.	0.754	प्रति कि.ग्रा.	अम.डॉ.
3	29.30	डाई ईथाइल थायो फॉस्फोराइल क्लोराइड (डीईटीपीसी)	चीन जन.गण.	चीन जन.गण.	जिंगताई पैस्टीसाइड कं.लि.	जिंगताई पैस्टीसाइड कं.लि.	0.516	प्रति कि.ग्रा.	अम.डॉ.
4	29.30	डाई ईथाइल थायो फॉस्फोराइल क्लोराइड (डीईटीपीसी)	चीन जन.गण.	चीन जन.गण.	झेजियांग जिनांग केमिकल कं. लि.	झेजियांग जिनांग केमिकल कं. लि.	0.798	प्रति कि.ग्रा.	अम.डॉ.
5	29.30	डाई ईथाइल थायो फॉस्फोराइल क्लोराइड (डीईटीपीसी)	चीन जन.गण.	चीन जन.गण.	उपरोक्त से इतर उत्पादक तथा निर्यातक का कोई संयोजन		1.157	Per Kg	प्रति कि.ग्रा.
6	29.30	डाई ईथाइल थायो फॉस्फोराइल क्लोराइड (डीईटीपीसी)	चीन जन.गण.	चीन जन.गण. से इतर अन्य कोई देश	कोई	कोई	1.157	प्रति कि.ग्रा.	अम.डॉ.
7	29.30	डाई ईथाइल थायो फॉस्फोराइल क्लोराइड (डीईटीपीसी)	चीन जन.गण. से इतर अन्य कोई देश	चीन जन.गण.	कोई	कोई	1.157	प्रति कि.ग्रा.	अम.डॉ.

169. उपर्युक्त के अधीन प्राधिकारी दिनांक 25 मई, 2009 के प्रारंभिक जांच परिणामों की पुष्टि करते हैं।

170. केन्द्र सरकार द्वारा इसे स्वीकार किए जाने के बाद इन जांच परिणामों के विरुद्ध कोई अपील 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ नियमावली, 1995 के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण (सेस्टेट) के समक्ष की जाएगी।

पी. के. चौधरी, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th May, 2010

FINAL FINDINGS

Subject:- Anti-Dumping Investigations concerning imports of Diethyl Thio Phosphoryl Chloride (DETPC) originating in or exported from China PR.

F. No. 14/18/2008-DGAD.—Whereas the Designated authority, having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time, (hereinafter referred to as the Rules) hereof:

1. WHEREAS M/s Cheminova India Limited, Mumbai (hereinafter referred to as the applicant) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority), in accordance with the Act, and the Rules, alleging dumping of Diethyl Thio Phosphoryl Chloride (DETPC) (hereinafter referred to as the subject goods) originating in or exported from the China PR (hereinafter referred to as subject country) and requested for initiation of an investigation for levy of anti-dumping duties on the subject goods.

2. AND WHEREAS, the Authority on the basis of sufficient evidence submitted by the applicant issued a public notice dated 17th November, 2008, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating Anti-Dumping investigations concerning imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country, in accordance with the sub-Rule 5(5) of the Rules, to determine the existence, degree and effect of the alleged dumping and to recommend the amount of anti-dumping duty, which, if levied would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

3. AND WHEREAS, the Designated Authority having regard to the Act and the Rules investigated and recommended imposition of provisional Anti Dumping Duties on imports of the subject goods falling under subheading 29.30 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) originating in or exported from the subject country, vide Preliminary Findings of even number dated 25th May, 2009 and Provisional Anti Dumping Duties were imposed on the subject goods vide Customs Notification No. 73/2009 dated 22.6.2009.

A. Background Of The Case:

4. The background of the case is as follows:

i) The Designated Authority had received a written application from M/s Cheminova India Limited, Mumbai and supported by M/s Excel Industries Ltd., Mumbai for and on behalf of the domestic industry, alleging dumping of Diethyl Thio Phosphoryl Chloride (DETPC) originating in or exported from China PR.

ii) The Authority on the basis of sufficient evidence submitted by the applicant on behalf of the domestic industry, issued a public notice dated 17th November, 2008 initiating Anti-Dumping investigations concerning imports of Diethyl Thio Phosphoryl Chloride originating in or exported from China PR, in accordance with the sub-Rule 6(1) of the Anti-dumping Rules to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of anti dumping duty, which, if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

iii) The initiation notification issued by the Designated Authority was challenged by M/s. Meghmani Organics Ltd., Ahmedabad before the Hon'ble Gujarat High Court vide Special Civil Application No. 2201/2009. The matter was heard by the Hon'ble Division Bench of the Gujarat High Court on 8.4.2009 and disposed of with the directions that the preliminary objection raised by the petitioners as to jurisdiction of the Designated Authority shall be dealt with and decided by the Designated Authority within a period of four weeks i.e. on or before 07.05.2009, after hearing the petitioners in this regard in accordance with law.

iv) As per the directions of the Hon'ble Division Bench of the Gujarat High Court dated 8.4.2009, a hearing was granted by the Designated Authority on 24.4.2009. M/s. Meghmani Organics Ltd., along with other interested parties were invited for the hearing.

v) The representatives of M/s. Meghmani Organics Ltd., domestic industry and exporters attended the hearing and were given opportunity to present their arguments before the Designated Authority. After hearing the interested parties and their representatives, the Designated Authority instructed to submit written submissions by 28.4.2009 and rejoinders by 1.5.2009.

vi) After detailed examination and careful consideration of the submissions made on behalf of M/s. Meghmani Organics Ltd., Ahmedabad and other interested parties, and relying upon relevant Rules and judgements, the Designated Authority passed a speaking order vide order dated 6th May, 2009.

vii) The Designated Authority, having regard to the Act and the AD Rules; recommended imposition of provisional Anti Dumping duty on imports of the subject goods originating in or exported from the subject country. The preliminary findings were published vide Notification No 14/18/2008-DGAD dated 25th May 2009 and provisional duty was imposed on the subject goods vide Customs notification No. 73/2009-Customs dated 22nd June 2009.

viii) M/s. Meghmani Organics Ltd., Ahmedabad again filed a Petition being Special Civil Application No.6881 of 2009 before Hon'ble High Court of Gujarat, challenging the initiation notification dated 17.11.2008, Speaking Order dated 6.5.2009, passed by the Designated Authority in compliance with the earlier orders dated 8.4.2009 of the Hon'ble Division Bench of the Gujarat High Court, Preliminary Finding dated 25.5.2009 and Customs Notification No. 73/2009 dated 22.6.2009 on the grounds that initiation notification was without jurisdiction and the entire investigation suffers from excessive confidentiality.

ix) The Hon'ble Division Bench of the High Court of Gujarat vide order dated 09.10.2009 disapproved the preliminary finding of the Designated Authority on the issue of confidentiality. The Hon'ble Division Bench also directed the Designated Authority to provide all necessary details of findings which are kept blank while recording his preliminary findings and to permit the petitioners to raise their objections in this regard and while recording the final finding, consider such objections and submissions. The Designated Authority was also directed to consider as to whether Excel Industries Limited (erstwhile Respondent No.4) and their allied concerns have made any import of subject goods from China PR. Further, till such exercise is undertaken by the Designated Authority and final finding is arrived at, the petitioner was exempted from levy of provisional anti-dumping duty on an import of subject goods from China PR. The exemption was made conditional upon submission of an undertaking, before the Designated Authority within one week from the date of order, stating that in the event they are held to be liable to pay anti-dumping duty on the import of subject goods that may be made, while recording final finding on this issue, they will pay such anti-dumping duty subject to their right to appeal and obtaining stay against such duty from any competent Court or Tribunal.

x) The Designated Authority vide Special Leave petition No. 887 of 2010 (and separately, Cheminova Industries Ltd vide Special Leave petition No. 34374 of 2009 and Excel Industries Ltd vide Special Leave petition no. 35243 of 2009), challenged the impugned orders dated 9.10.2009 of Hon'ble Division Bench of the Gujarat High Court before the Hon'ble Supreme Court of India. After hearing the parties, the Hon'ble Supreme Court was pleased to order as follows:

"Leave granted.

Hearing expedited.

Pending disposal of the appeals, there shall be stay of the impugned order.

Place the appeals on 26th August, 2010."

xi) M/s Siris Crop Sciences Limited vide Writ Petition No. 190 of 2010, M/s Sabero Organics Gujarat Ltd vide Writ Petition No. 173 of 2010, M/s Rotam India Ltd vide Writ Petition No. 191 of 2010 and M/s P. I. Industries Limited vide Writ Petition No. 183 of 2010, M/s GSP Crop Sciences Private Limited vide Writ Petition No 736 of 2010, M/s Bhagirdha Chemicals Industries Limited vide Writ Petition No 737 of 2010 and M/s Gharda Chemicals Limited vide Writ Petition No 738 of 2010, have filed Writ Petitions challenging the initiation notification dated 17.11.2008, Order dated 6.5.2009, passed by the Designated Authority in compliance with the orders of Hon'ble Division Bench of the Gujarat High Court dated 8.4.2009, Preliminary Finding dated 25.5.2009 and Customs Notification No. 73/2009 dated 22.6.2009, before Hon'ble High Court of Delhi on the grounds that initiation notification was without jurisdiction and the entire investigation suffers from excessive confidentiality.

xii) After hearing the parties, the Hon'ble High Court of Delhi was pleased to issue the notices and fix the matters for hearing on 24.05.2009. While the writ petitioners had also filed application for interim stay order as well, no interim stay order has been passed by the Hon'ble High Court of Delhi.

B. Procedure

5. In these proceedings the procedure described herein below has been followed:

- i. The Authority notified the Embassy of China PR in India about the receipt of the anti-dumping application made by the domestic industry before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub-rule (5) of Rule 5 supra.
- ii. The Authority on the basis of sufficient evidence submitted by the applicant on behalf of the domestic industry, issued a public notice dated 17th November, 2008 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating Anti-Dumping investigations concerning imports of Diethyl Thio Phosphoryl Chloride originating in or exported from China PR, in accordance with the sub-Rule 6(1) of the Anti Dumping Rules to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of anti dumping duty, which, if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.
- iii. The Designated Authority sent a copy of Initiation Notification dated 17th November 2008 to the Embassy of China PR in India, known exporters from China PR, importers, consumers and the domestic industry as per the addresses made available by the applicant and requested them to make their views known in writing within 40 days of the Initiation Notification.
- iv. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known exporters and to the Embassy of China PR in India in accordance with Rule 6(3) supra.
- v. The Embassy of China PR in India was informed about the initiation of the investigation in accordance with Rule 6(2) of the Anti Dumping Rules with a

request to advise the exporters/producers from their country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the exporters was also sent to them along with the names and addresses of the known exporters.

- vi. The Authority sent questionnaires to elicit relevant information to the known exporters in the subject country in accordance with Rules 6(4) of the Anti Dumping Rules.
- vii. In response to the above notification, the following producers/exporters/associations have responded:

S.N	Company's Name
1.	Yangxin Chentian Chemical Industry Co., Ltd.
2.	Lianyungang Liben Agro-chemical Co., Ltd.
3.	Xingtai Pesticides Co., Ltd.
4.	Zhejiang Xinnong Chemical Co., Ltd.
5.	China Crop Protection Industry Association

- viii. Questionnaire was sent to the known importers and/or consumers of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Anti Dumping Rules.

- ix. In response, information has been received from the following importers/ users:

S.N.	Company's Name
1.	Meghmani Organics Ltd.
2.	Bhagiratha Chemicals & Industries Ltd
3.	Gharda Chemicals Ltd.
4.	P. I. Industries
5.	Siris Crop Science Ltd.

- x. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties.
- xi. Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to arrange details of imports of subject goods for the past three years and the period of investigation. Information has been received from the DGCI&S, which has been used to the extent deemed necessary.
- xii. Optimum cost of production and cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the applicant on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) was worked out so as to ascertain if anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to Domestic Industry.

- xiii. Investigation was carried out for the period starting from 1st April 2007 to 31st March, 2008 (POI). The examination of trends, in the context of injury analysis, covered the periods April 2004-March 2005, April 2005-March 2006, April 2006-March 2007 and the POI.
- xiv. In accordance with Rule 6(6) of the Anti Dumping Rules, the Authority also provided opportunity to all the known interested parties to present their views orally in a public hearing held on 7th October, 2009. The parties, which presented their views in the public hearing, were requested to file written submissions of the views expressed orally. The interested parties were advised to file written submission and rejoinder submission by 15.10.2009 and 21.10.2009 respectively.
- xv. The submissions made by the interested parties prior to notification of the preliminary findings, which have been brought out in the notified preliminary finding, have not been repeated ~~herein~~ for the sake of brevity. However, the submissions made in response to the preliminary findings and arguments made in the written submissions/ rejoinders received from the known interested parties after the public hearing and issues raised by interested parties before various courts have been considered, wherever found relevant, in this finding.
- xvi. Verification to the extent deemed necessary was carried out in respect of the information & data submitted by the domestic industry and the co-operating Chinese producers/exporters.
- xvii. In accordance with Rule 16 of the Anti Dumping Rules, the essential facts considered by the Authority were disclosed to the known interested parties vide Disclosure Statement dated 13th April, 2010. The comments received on the disclosure statement have been duly examined and considered wherever relevant in this finding.
- xviii. The views expressed by various interested parties earlier had been considered in the preliminary findings and also in the disclosure statement. The views which have not been considered earlier in the preliminary findings and in the disclosure statement and those raised in response to the disclosure statement are also examined and considered in the relevant paragraphs of this finding to the extent relevant as per Rules and have a bearing upon the case.
- xix. Information provided by the known interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.

- xx. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has recorded these findings on the basis of the facts available.
- xxi. *** in this notification represents information furnished by the interested parties on confidential basis and so considered by the Authority under the Anti-Dumping Rules.
- xxii. The exchange rate adopted for the POI is Rs. 40.75=1 US \$

C. Product Under Consideration And Domestic Like Article

C.1 Views Of The Domestic Industry

6. Following submissions have been made by the domestic industry with regard to products under consideration and like article:

i) The product under consideration in the present investigation is Diethyl Thio Phosphoryl Chloride (DETPC); a colourless or light yellow/amber organic liquid having disagreeable odor. It has density of 1.196 g/cm³. Diethyl Thio Phosphoryl Chloride is insoluble in water, but soluble in organic solvents. It is a highly toxic chemic which may irritate eyes and lungs. It is also known as O,O-Diethyl Phosphorochloridothioate or DETPC. Diethyl Thio Phosphoryl Chloride is having chemical formula C₄H₁₀ClO₂PS. It is an intermediate used in the production of pesticides.

ii) Diethyl Thio Phosphoryl Chloride is being imported under different synonyms and different Customs Classifications such as;

- CHLORURE DE DIÉTHYLTHIOPHOSPHORYLE (DOT FRENCH)
- O,O-DIETHYL THIONOPHOSPHORIC CHLORIDE
- CLORURO DE DIETILTIOFOSFORILO (DOT SPANISH)
- DIETHOXYTHIOPHOSPHORYL CHLORIDE
- DIETHYL CHLOROTHIOPHOSPHATE
- DIETHYL PHOSPHOROCHLORIDOTHIOATE
- ETHYL PHOSPHOROCHLORIDOTHIOATE ((ETO) 2CLPS)
- O,O-DIETHYL PHOSPHOROTHIONOCHLORIDATE
- PHOSPHOROCHLORIDOTHIOIC ACID, O,O-DIETHYL ESTER .

iii) Since these are common synonyms of the product under consideration, all these synonyms may be included within the scope of the product under consideration.

iv) The product is classified under Chapter 29 in the Customs Tariff Act. But as per available information the product under consideration is being imported under several customs classifications as indicated below:

S.No.	ITC-CODE	Imports in Mt			
		2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
1	28121090	-	-	-	1,160
2	28129000	180	-	-	20
3	28273990	320	210	160	-
4	29051100	-	120	160	380
5	29091900	40	-	-	-
6	29095090	20	-	-	-
7	29190090	460	40	240	-
8	29199010	-	-	80	560
9	29199090	-	-	-	600
10	29201000	7,523	6,989	3,220	-
11	29201010	-	-	400	-
12	29201020	-	-	920	-
13	29201100	-	-	80	100
14	29201910	-	-	-	2,078
15	29201920	-	-	160	220
16	29201990	-	-	40	2,175
17	29209010	-	140	40	-
18	29209020	-	-	440	596
19	29209030	-	-	240	760
20	29209090	480	-	-	-
21	29209099	-	-	1,990	3,553
22	29241900	-	-	138	254
23	29310090	270	100	10	140
24	29420011	700	360	-	20
25	29420090	300	95	440	-
26	38089010	178	-	-	-

v) Since the product under consideration has been imported under Chapter 28, 29 and 38, the investigation extends to imports of the product under consideration in all the three chapters. However, the customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

C.2 Views Of The Importers/Users, Exporters And Other Interested Parties:

7. None of the opposing interested parties has raised any objection in this regard. Subject goods produced by the Domestic Industry has been treated by them as like article to the subject goods imported from subject country.

C.3 Examination By The Authority

8. With regard to like article, Rule 2(d) of the Anti-Dumping Rules provides as under:

"like article " means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation;

9. With regard to the possible difference between the product sold by the producers/exporters in the Indian market and the product sold by the domestic industry, the Authority notes that there is no known difference in product under consideration produced by the domestic industry, and exported from the subject country. Product under consideration produced by the Indian industry and imported from the subject country are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably. None of the opposing interested parties has raised any objection in this regard. Subject goods produced by the Domestic Industry is therefore being treated as like article to the subject goods imported from subject country in accordance with the Anti-Dumping Rules.

D. Litigation Before Various Courts

D.1 Special Civil Application No. 2201/2009 before Hon'ble Bench of the High Court of Gujarat, Ahmedabad

10. The initiation notification issued by the Designated Authority was challenged by M/s. Meghmani Organics Ltd., Ahmedabad before the Hon'ble Bench of the Gujarat High Court vide Special Civil Application No. 2201/2009. The matter was heard by the Hon'ble Division Bench on 8.4.2009 and disposed of with the following orders:

"Mr. Harin P. Raval, Learned Assistant Solicitor General of India, upon instructions of the Designated Authority, states that the preliminary objection raised by the petitioners as to jurisdiction of the Designated Authority shall be dealt with and decided by the Designated Authority within a period of four weeks i.e on or before 07.05.2009, after hearing the petitioner in this regard in accordance with law. In light of the statement made by the learned counsel for respondent No.2 authority, learned advocate for petitioners seeks permission to withdraw the petition, under instructions. Permission granted. The petition stands disposed of accordingly."

11. As per the directions of the Hon'ble Division Bench of the Gujarat High Court dated 8.4.2009, a hearing was granted by the Designated Authority on 24.4.2009. M/s. Meghmani Organics Ltd., along with other interested parties were invited for the hearing.

12. The representatives of M/s. Meghmani Organics Ltd., domestic industry and exporters attended the hearing and given opportunity to present their arguments before the Designated Authority. After hearing the interested parties and their representatives, the Designated Authority instructed to submit written submissions by 28.4.2009 and rejoinders by 1.5.2009.

13. The submissions made by various interested parties in pursuance of the hearing by the Designated Authority are summarized below:

a) **M/s. Meghmani Organics Ltd. And Exporters from China PR**

- (i) Rule 5(1) contemplates filing of application "by or on behalf of the Domestic Industry". The term "Domestic Industry" referred to in Rule 5(1) has been defined in Rule 2(b). The application has been filed by M/s. Cheminova who does not qualify to be referred to as "Domestic Industry" as defined under Rule 2(b). The applicant accounts for a mere 28% of the domestic production, which cannot be considered as a major or significant proportion of the domestic production.
- (ii) Prior to the initiation, the Designated Authority was informed by the applicant that there were three producers of the subject goods in India. At the time of initiation, the Designated Authority did not resort to polling, as has been done in other cases, to ascertain total production in India, despite the fact that the applicant constituted only 28% of the domestic production. Without information about the third producer, the Designated Authority would not have examined whether the application was filed by domestic industry as he could not have reached any conclusion on "major proportion" of the total domestic production.
- (iii) Rule 2(b) excludes producers who have relationship with exporters of product under consideration (alleged dumped article). Fact of relationship of M/s. Cheminova with their related entity in Denmark has been suppressed in the non-confidential version of the application. In the absence of such information, the Designated Authority can not take a view whether to include or exclude such producers in terms of Rule 2(b).
- (iv) The initiation notification does not indicate in any manner, whatsoever that the Designated Authority had exercised its discretion and the reasons in support thereof to allow the applicant as an eligible domestic industry despite its relationship with the Denmark entity exporting the subject goods to India.

- (v) The Authority ignored the production of M/s Sabero Organics Ltd. despite having the information that there were three producers of the subject goods in India.
- (vi) As per settled law, captive consumption cannot be included while reaching pre-initiation determination as mandated under law. M/s. Cheminova failed to disclose the details of any captive consumption of goods in the non-confidential version of application and further, there is no determination in respect thereto reflected in the initiation notification.
- (vii) Subsequent filing of information by M/s. Excel, who was not the applicant at the time of initiation, cannot be permitted at this stage as it seriously jeopardizes the interest of the interested parties.
- (viii) The antidumping investigations in the present case may be quashed by the Designated Authority as the same are without jurisdiction and against statutory law.
- (ix) There is no case for retrospective imposition of duty since none of the requirements of Section 9A(3) of Customs Tariff Act, 1975 have been met.
- (x) The copy of index to the public file, copies of the submissions etc should be provided.

b) **Domestic Industry**

- i. There is no merit in the objections raised by the interested parties which are based on incorrect and misplaced legal understanding. The application satisfied the requirement of the standing under Rule 5(3) read with Rule 2(b). Hence, the applicant constituted domestic industry within the meaning of Anti-Dumping Rules.
- ii. Standing and scope of domestic industry are two different requirements. In the name of jurisdiction, M/s. Meghmani has raised the issue of "scope of domestic industry" and has not referred to how the standing is not established in this case. Hence the argument of M/s. Meghmani with regard to standing requirement does not hold good.
- iii. As per Anti-Dumping Rules, M/s. Cheminova qualifies as Domestic Industry whose production constitutes a major proportion. The interested parties repeatedly stating "major proportion" whereas the requirement is "a major proportion". Hence, omission of "a" is not accidental but it is deliberate on the part of these interested parties.
- iv. There is no prescribed legal requirement to resort to polling at pre-initiation of investigation.

- v. Exports made by M/s. Cheminova's affiliated Company in Denmark are from a country other than the subject country (China PR) and does not come within the definition under Rule 2(b).
- vi. Regarding exclusion of M/s. Sabero Organics, the same was excluded on the grounds that (a) the Company curtailed or stopped production substantially and resorted to imports and (b) the Company substantially captively consumed the Product Under Consideration.
- vii. Regarding non-consideration of captive consumption, it would be seen that if such captive consumption is excluded, the production of M/s. Cheminova still remains much higher than the minimum threshold limit. Moreover, M/s. Sabero Organics does not sell DETPC in the market and consumes entire production captively. Hence, on this ground, the production of M/s. Sabero could not have been included.
- viii. As per Anti-Dumping Rules, the application would satisfy standing requirement if the applicant makes more than 25% of Indian production. In the instant case, the production of the applicant is more than 28% of Indian production and the application has been supported by M/s. Excel Industries whose production accounts for about 71%.
- ix. There are massive imports in a relatively short period which is established by the fact that at least 1,500 MT DETPC was imported during March, 2009 and approximately 2,000 MT imports are to be cleared in the current month which are being imported at a price below the normal value.
- x. Due to substantial imports, both the domestic industries have been forced to reduce their production and suffering injury due to massive dumping at a price much below their cost of production.
- xi. DETPC is used for manufacturing agro-chemicals (insecticides) which are seasonal products largely consumed in Kharif Season. Delaying the imposition of duty by another two months, the importer would get advantage for one full year. The whole purpose for approaching the High Court at premature stage is to delay the imposition of anti-dumping duty and thereby gaining the period of seasonal consumption of the product concerned.
- xii. M/s. Excel Industries has not only supported the application for imposition of anti-dumping duty but also provided costing and injury information to the Authority.
- xiii. As there is no merit in the submissions made by other interested parties with regard to standing of the application or scope of the domestic

industry, there is full justification in imposition of anti-dumping duties on retrospective basis.

c) Examination By The Authority

14. The views/submissions expressed by the interested parties pursuant to the hearing are examined hereunder:

i) Regarding qualification of M/s Cheminova India Ltd. as Domestic Industry, it is observed that in terms of Rule 2(b) read with Rule 5(3) of the Anti-Dumping Rules, the Authority needs to be satisfied whether the application has been filed by or on behalf of the domestic industry.

Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules provides as follows:

"domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in which case such producers may be deemed not to form part of domestic industry ;

Rule 5(3) of the Anti-Dumping Rules provides as follows:

"The designated authority shall not initiate an investigation pursuant to an application made under sub-rule (1) unless –

a) *it determines, on the basis of an examination of the degree of support for, or opposition to the application expressed by domestic producers of the like product, that the application has been made by or on behalf of the domestic industry :*

Provided that no investigation shall be initiated if domestic producers expressly supporting the application account for less than twenty five per cent of the total production of the like article by the domestic industry, and

(b) *it examines the accuracy and adequacy of the evidence provided in the application and satisfies itself that there is sufficient evidence regarding –*

(i) dumping,

(ii) injury, where applicable; and

(iii) where applicable, a causal link between such dumped imports and the alleged injury, to justify the initiation of an investigation.

Explanation. - For the purpose of this rule the application shall be deemed to have been made by or on behalf of the domestic industry, if it is supported by those domestic producers whose collective output constitute more than fifty per cent of the total production of the like article produced by that portion of the domestic industry expressing either support for or opposition, as the case may be, to the application."

ii) It is observed that in the instant case the applicant accounts for 27.33% of the domestic production, while excluding production of M/s Sabero Organics, if any, being an importer of the subject goods. Moreover, the application was supported by M/s Excel Industries Limited, a major producer, whose collective production constitutes more than 50% of the domestic production, from the initial stage.

iii) Regarding requirement of polling before initiation it is stated that there is no prescribed legal requirement to resort to polling before initiation of investigation. At the stage of initiation of investigation, the Authority is not required to hold a detailed enquiry but to satisfy prima-facie the requirements prescribed under the Rule 5(3). However, to confirm about the domestic producers and their production the concerned administrative department was requested to provide relevant details.

iv) The contention that the Authority ignored the production of M/s. Sabero Organics, despite the information to the Authority that there were three producers of the subject goods in India does not hold good. The concerned Administrative Department was requested to provide details about the domestic producers and their production including M/s. Sabero Organics. Department of Chemicals & Petrochemicals provided information about M/s. Cheminova and M/s. Excel Industries only. This information further reinforced the information submitted by the applicant in their application in this regard. After initiation of the investigation, M/s. Sabero Organics was also requested to submit their response, but there is no response till date. It is further observed from the submissions made by the Domestic Industry that M/s. Sabero Organics curtailed or stopped production substantially and resorted to imports and also consumed the product captively. Further, as per the data provided by the DGCI&S, M/s. Sabero Organics has imported a substantial quantity (***) Mt constituting about 5% of the total imports of the subject goods from the subject country) of the subject goods from the subject country during the POI.

v) The contention that M/s. Cheminova suppressed their relationship with their parent Company in Denmark in the non-confidential version of the application does not hold good. In fact there was no suppression of facts regarding relationship with the parent Company in Denmark. The Authority had specifically called for information in this regard before initiation and the facts were submitted by the applicant.

vi) The submission that the exports made by M/s Cheminova Denmark, the parent company of M/s Cheminova India Ltd., to India, disqualify the status of the later as domestic industry, is not correct. The exports made by the parent Company were not from the subject country i.e. China PR and hence, the same cannot be treated as dumped article. Hon'ble CESTAT in its various judgments has clearly indicated that the relationship between the domestic industry and related exporters must be examined in the context of subject countries only. In the matter of Birla Ericsson Ltd. Versus Designated Authority [2001 (127) E.L.T. 363 (Tri. - Del.)] Hon'ble CESTAT held as under:

"The above argument of Counsel representing the appellants is solely based on the exclusion contained in Rule 2(b) of the Rules, which defines domestic industry. After stating that domestic industry means domestic producers whose collective output of the article constitutes a major proportion of the total domestic production, certain categories are excluded there from. The categories excluded are those domestic producers who are related to exporters of the alleged dumped article, those who are related to importers of the alleged dumped article or those who themselves are importers thereof. What is the scope of the words "importers thereof?" This group of domestic producers who are importers thereof are to be grouped along with domestic producers related to exporters of the alleged dumped article and domestic producers related to importers of the alleged dumped article. So taken, the domestic producers who are themselves importers should mean domestic producers who are themselves importers of alleged dumped article. In other words, domestic producers who are not importers of alleged dumped article from the subject country are not to be excluded from the definition of "domestic industry."

vii) It has been alleged that M/s Cheminova has got captive consumption of the subject goods and as per settled law captive consumption cannot be included while reaching pre-initiation determination. Failure of M/s Cheminova to disclose the details of their captive consumption of the subject goods in the non-confidential version of the application makes them ineligible to become domestic industry. It is observed that M/s Cheminova has declared its captive consumption in its petition under Proforma IV A at Sl. No. 1 under the heading sales, however it is very nominal (** Mt constituting about 1% of the total production). Further, if the quantity of captive consumption is excluded, the balance quantity still remains 26.53% which is higher than the prescribed threshold limit of 25% under the Anti-Dumping Rules.

viii) The argument that subsequent submission of information by M/s Excel Industries Ltd., who was not the applicant at the time of initiation of investigation and therefore cannot be permitted, does not hold good. It is observed that M/s Excel Industries Ltd., a major producer having more than 72.67% of the domestic production, supported the petition from initial stage along with relevant information/data to the Authority regarding their production and domestic sales during the entire injury period and POI.

ix) As prescribed under the Rules 6(7), a public file containing non-confidential copies of submissions furnished by various interested parties have been made available by the Authority. The same have been visited by the interested parties and collected copies of the non-confidential submissions, whichever required. The opposing interested parties are fully aware of this practice of maintenance of Public file and could have inspected the Public file for obtaining requisite copies of the submissions required by them.

15. After detailed examination and careful consideration of the submissions made on behalf of M/s. Meghmani Organics Ltd., Ahmedabad and other interested parties, and relying upon relevant Rules and judgements, the Designated Authority passed a speaking order vide order dated 6th May, 2009. It was observed that M/s Cheminova India Ltd., supported by M/s Excel Industries Ltd., constitutes Domestic Industry and the initiation of the anti-dumping investigations by the Authority is well within its jurisdiction under Anti-Dumping Rules and Law in this regard. Accordingly the anti-dumping investigations in respect of imports of Di-ethyl Thio Phosphoryl Chloride (DETPC) originating in or exported from China PR was ordered to be continued for recommending further necessary action in accordance with Anti Dumping Rules and Law.

D.2. Special Civil Application No.6881 of 2009 before Hon'ble High Court of Gujarat, Ahmedabad

16. M/s. Meghmani Organics Ltd., Ahmedabad again filed a Petition being Special Civil Application No.6881 of 2009 before Hon'ble Bench of the High Court of Gujarat, challenging the initiation notification dated 17.11.2008, Order dated 6.5.2009 passed by the Designated Authority in compliance with the earlier orders of Hon'ble Bench of the Gujarat High Court dated 8th April, 2009, Preliminary Finding dated 25.5.2009 and Customs Notification No. 73/2009 dated 22.6.2009 on the grounds that initiation notification was without jurisdiction and the entire investigation suffers from excessive confidentiality.
17. The Hon'ble Division Bench of the High Court vide judgment and order dated 09.10.2009 disapproved the preliminary finding of the Designated Authority on the issue of confidentiality. The Hon'ble Bench also directed the Designated Authority to provide all necessary details of findings which are kept blank while recording his preliminary findings and to permit the petitioners to raise their objections in this regard and while recording the final finding, consider such objections and submissions. The Designated Authority was also directed to consider as to whether Excel Industries Limited (erstwhile Respondent No.4) and their allied concerns have made any import of subject goods from China PR. Further, till such exercise is undertaken by the Designated Authority and final finding is arrived at, the petitioner was exempted from levy of provisional anti-dumping duty on an import of subject goods from China PR. The exemption was made conditional upon submission of an undertaking, before the Designated

Authority within one week from the date of order, stating that in the event they are held to be liable to pay anti-dumping duty on the import of subject goods that may be made, while recording final finding on this issue, they will pay such anti-dumping duty subject to their right to appeal and obtaining stay against such duty from any competent Court or Tribunal.

The relevant portions of the impugned orders are quoted below:

"We, therefore, while not expressing any opinion on other issues decided by the designated authority in the impugned notification and reserving the petitioners' right to challenge at the time of final finding, we disapprove the preliminary finding of the designated authority on the issue of confidentiality and direct the designated authority to provide all necessary details of findings which are kept black while recording his preliminary findings and permit the petitioners to raise their objections in this regard and while recording the final finding, the designated authority shall take into consideration such objections and submissions that may be made in this regard. Not only this, designated authority shall take into consideration the issues raised by the petitioners with regard to the respondent No. 4 and to decide as to whether they or their allied concerns have made any import of subject goods from China. The details as to finding recorded by the D.A. shall be provided to the petitioners. Till such exercise is undertaken by the designated authority and final finding is arrived at, the petitioners shall not be saddled with the levy of provisional anti-dumping duty on an import of subject goods from China on condition that the petitioners shall file an undertaking within one week from today before the designated authority that in the event they are held to be liable to pay anti-dumping duty on the import of subject goods that may be made, hereinafter from China, while recording final finding on this issue, they will pay such anti-dumping duty subject to their right to appeal and obtaining stay against such duty from any competent Court or Tribunal.

It is once again made it clear that we have not expressed any opinion on the other issues which are raised before this Court or on findings recorded by the designated authority and they are kept open and parties are at liberty to agitate before the appropriate forum while challenging final findings, if the occasion so arises.

Subject to the aforesaid observations and directions, this petition is accordingly disposed of. Rule is made absolute to the above extent only, without any order as to costs.

At this state, a request is made on behalf of respondent Nos. 3 & 4 to stay operation of this order to enable them to approach the higher forum, because the confidentiality aspect hurts them. In view of our finding on

confidentiality, there is no question of any damage being caused to these respondents. It is also argued that direction not to impose anti-dumping duty on the goods to be imported by the petitioner is likely to affect the interest of the respondent Nos. 3 & 4. In our opinion, as a consequence, legal judicial orders are not to be stayed on individual grounds. Therefore, the request cannot be acceded to."

D.3. Special Leave Petition No. 887 of 2010

18. The Designated Authority vide Special Leave petition No. 887 of 2010, and separately, M/s Cheminova Industries Ltd vide Special Leave petition No. 34374 of 2009 and M/s Excel Industries Ltd (the domestic industry) vide Special Leave petition no. 35243 of 2009, had challenged the order dated 9.10.2009 of Hon'ble Bench of the Gujarat High Court before the Hon'ble Supreme Court.

After hearing the parties, the Hon'ble Supreme Court vide their order dated 8th February, 2010 was pleased to order as follows :

"Leave granted.

Hearing expedited.

Pending disposal of the appeals, there shall be stay of the impugned order.

Place the appeals on 26th August, 2010."

D.4 Writ petitions filed before the Hon'ble High Court of Delhi by various interested parties

19. M/s Siris Crop Sciences Limited vide Writ Petition No. 190 of 2010, M/s Sabero Organics Gujarat Ltd vide Writ Petition No. 173 of 2010, M/s Rotam India Ltd vide Writ Petition No. 191 of 2010, M/s P I Industries Limited vide Writ Petition No. 183 of 2010, M/s GSP Crop Sciences Private Limited vide Writ Petition No 736 of 2010, M/s Bhagirdha Chemicals Industries Limited vide Writ Petition No 737 of 2010 and M/s Gharda Chemicals Limited vide Writ Petition No 738 of 2010, have filed Writ Petitions challenging the initiation notification dated 17.11.2008, Order dated 6.5.2009, passed by Designated Authority in compliance with the orders of Hon'ble Bench of the Gujarat high Court, Preliminary Finding dated 22.5.2009 and Customs Notification No. 73/2009 dated 22.6.2009, before Hon'ble High Court of Delhi on the grounds that initiation notification was without jurisdiction and the entire investigation suffers from excessive confidentiality.
20. After hearing the parties, the Hon'ble High Court of Delhi was pleased to issue the notices and fix the matters for 24.05.2009. While the writ petitioners had also filed application for interim stay order as well, no interim stay order has been passed by the Hon'ble High Court of Delhi.

E. Scope of Domestic Industry & Standing

E.1. Views of the Exporters

21. In the Post-preliminary findings stage M/s Dua Associates on behalf of Yangxin Chentian Chemical Industry Co., Ltd., Zhejiang Xinnong Chemical Co., Ltd. and China Crop Protection Industry Association made the following submissions:

- (i) The Petitioner does not constitute "Domestic Industry" under Rule 2(b) and the Petition fails to meet the standing requirements contrary to Rules 5(1) and 5(3) of the Anti Dumping Rules and deserves to be terminated.
- (ii) The Petitioner is neither the sole domestic producer engaged in the manufacture of the like article nor does Petitioner's output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article.
- (iii) Cheminova India Limited is clearly related to Cheminova Denmark, the exporter of the alleged dumped article.
- (iv) Authority has erroneously rejected the submission that the exports made by M/s Cheminova Denmark, the parent company of M/s Cheminova India Ltd., to India disqualify the latter as domestic industry, stating that the exports made by the parent company were not from the subject country i.e. China PR and hence the same cannot be treated as of the dumped article.
- (v) Full investigation has not been done of the presence of Cheminova's parent company in China whilst arriving at the finding as to status of Cheminova as domestic industry. Cheminova Shanghai Representative Office of the parent company, Cheminova Denmark, and Cheminova, the Petitioner which is subsidiary of the said parent company are both directly and/or indirectly controlled by said Cheminova Denmark. Accordingly even if the exclusionary words of Rule 2(b) are considered to only refer to the subject country i.e. China PR, even by that test Cheminova fails to meet the test of domestic industry.
- (vi) The Authority whilst seeking to declare that Cheminova India Ltd. supported by M/s Excel Industries Ltd. constitutes domestic industry has wholly failed to examine if Excel fulfills the test of "domestic industry" as per the Anti Dumping Rules. In fact the Hon'ble Designated Authority has itself recorded in the Preliminary Findings the aspect that there has been a subsequent submission of information by M/s Excel Industries Ltd. although it has held that the argument that subsequent submission cannot be permitted does not hold good as Excel allegedly supported the Petition from the initial stage with relevant information/data. Thus it is submitted that this is an erroneous approach and it is reiterated that a subsequent filing, which would itself require to be tested for standing, cannot be used to retrospectively give jurisdiction to the Authority which it did not have

at the relevant time i.e. initiation.

- (vii) Cheminova India Limited does not constitute "domestic industry" as also submitted herein above. Further even assuming without admitting that the application was sought to be made by "on behalf of" domestic industry, information relating to the "domestic industry" was not part of Cheminova India Limited's application based on which the present investigation has been initiated.
- (viii) Excel, as a group, has itself imported DTPC through Excel Crop Care Ltd and therefore is not eligible to seek protection under Anti Dumping law.

E.2. Views of the Importers

22. Post preliminary findings, M/S APJ-SLG, Law Offices on behalf of M/s Gharda Chemicals Ltd., Meghmani Organics Ltd., Siris Crop Sciences Ltd. and PI Industries Ltd. made the following submissions:

- a) Section 5(1) contemplates filing of application "by or on behalf of the Domestic Industry". Admittedly the application has been filed by M/s. Cheminova who does not qualify to be referred to as "Domestic Industry" as defined under Rule 2(b).
- b) No determination as mandated under Rule 5(3) has been made by the Authority to reach a conclusion that application has been filed by on behalf of Domestic Industry.
- c) The application has been filed by a sole producer viz. M/s. Cheminova and not by or on behalf of Domestic Industry, the injury information contained in the application is that of sole producer viz. M/s. Cheminova and not for Domestic Industry or after inclusion of information of M/s. Excel. Thus, the adequacy and accuracy of the information coupled with conditions of Rule 5(3) could not have been applied or examined. Further, examination of exclusion of related parties with exporters has been not taken into consideration. No examination of captive consumption has also been undertaken to reach correct determinations as mandated under law.
- d) Cheminova India is not a major producer of the subject goods as Excel is having 71% of total Indian Production.
- e) Cheminova India is related to exporter of the alleged dumped article i.e; Cheminova Denmark. Authority has erroneously held that the exports made by M/s Cheminova Denmark, were not from the subject country i.e. China PR and hence the same cannot be treated as dumped article.

- f) Initiation is based on information filed by Cheminova India which is not domestic industry. M/s Excel, the supporter, has not filed any information at the time of initiation.
- g) Excel cannot be constituted part of domestic industry unless it is not being examined by the Designated Authority that Excel fulfills the criteria mentioned under Rule 2(b).
- h) Applicant, M/s Cheminova does not constitute domestic industry as it accounts only for 28% of the total Indian production and is related to a Danish exporter of PUC.
- i) There are in all three producers of subject goods in India. At the time of initiation DA should have, like in other cases, resorted to polling to ascertain total production in India.
- j) Test of supporter is not envisaged under Rule 2 (b) but only those constituting major proportion. If Sabero buys from Excel, then it does not entail its exclusion from domestic industry as per rule 2 (b). Also such a fact does not necessitate reduction in production of Sabero.
- k) The Authority whilst seeking to declare that "Cheminova India Ltd. supported by M/s Excel Industries Ltd. constitutes Domestic Industry" has wholly failed to examine if Excel fulfills the test of "domestic industry" as per the Anti Dumping Rules.
- l) It is denied that Excel Crop Care Ltd. is not a related company of the Petitioner. Under its obligations as per Company Law, the same is being shown as a related entity in the records of Excel. In any case, the submissions made by them are allowed to be treated as confidential despite the fact that no non-confidential versions of the same have been filed.
- m) Reply of Excel Crop Care is being claimed as confidential without stating reasons for such claims of confidentiality and why indexation is not possible. Such an approach is contrary to requirements of Rule 7.
- n) The backdoor entry of Excel is evident from the record as if they were included at the time of initiation, the case would not have passed the pre-conditions of initiation and injury would have been diluted. Clearly, such an approach was strategic and commercial advantage has already been obtained by way of imposition of provisional duties.
- o) The Petitioner does not constitute "Domestic Industry" and the Petition fails to meet the standing requirements. The present investigation is contrary to Rules 5(1) and 5(3) of the Anti Dumping Rules and deserves to be terminated.

- p) The Domestic Industry has admitted that the application was filed by M/s. Cheminova and which was only a minor proportion of the total production in India as per Rule 2(b). In other words, it failed to qualify as Domestic Industry and failed to provide data on injury and causal link in terms of Rule 5(2)(b) and Rule 5(2)(c) for the Domestic Industry as a whole. In the absence of such data and information available in the application itself for the Domestic Industry as a whole the Designated Authority could not have proceeded further with the initiation of the present case they being pre-conditions for initiation. Additionally, the deeming fiction under Rule 2(b) for relationship with exporters and imports by related entities are being applied to Excel after initiation of the investigation. In other words, this examination being a pre-condition of initiation is being applied post-initiation. This factor alone is a good reason for termination of the present investigation.
- q) The discretion provided under 2(b) cannot be exercised unless the necessary cogent material was available to the Designated Authority at the appropriate time. Clearly, at the stage of initiation, all this information was not even on record and hence it cannot be said that the Designated Authority exercised discretion under Rule 2(b). This being a pre-condition for initiation, exercise of discretion without supporting reasons is hence flawed and contrary to law. In view of the above, the case law cited by the Domestic Industry is not applicable in the facts and circumstances of the present case.

E.3. Views of the Domestic Industry

23. Post preliminary findings the following views have been made by the domestic industry:

- a) The Application has been filed by M/s Cheminova India Limited and has been supported by M/s Excel Industries Ltd from the stage of the application. Both have provided injury information.
- b) Interested parties disputed the standing of the petition. Elaborate submissions were made by the Domestic industry. The Designated Authority has thereafter passed a detailed speaking order dated 6th May, 2009 pursuant to the orders dated 8th April 2009 of the Hon'ble High Court of Gujarat, holding that the petition satisfied standing. Domestic industry submits that there is no merit in the objections raised by the interested parties in this regard. The entire objections are based on incorrect and misplaced legal understanding.
- c) The Rules provide that the petition should be filed by or on behalf of the domestic industry, which means that the petition should be supported by those domestic producers whose collective production constitute more than 50% of total production. Admittedly, the present petition is supported by those domestic producers whose collective production constitute more than 50% of eligible domestic production. Further, the production of petitioner is more than 25% of total production of like article by the domestic industry. It is emphasized that

production of Sabero Organics in any case is required to be excluded in view of (a) the company has curtailed or stopped production substantially (b) the company has been substantially captively consuming the product and both Cheminova and Excel Industries are not aware of any sale of DETPC by Sabero; even when both the companies are in market for such a long period and (c) significant imports made by them. Moreover, Sabero has not preferred to respond to the Authority even till date.

- d) Denmark is not a subject country in the present investigation. Domestic producers who are not importers of alleged dumped article from the subject country are not to be excluded from the definition of domestic industry. Although, Cheminova Denmark is also having related company in China PR, it is submitted that the company is not at all involved in production and sale of the product under consideration, nor has exported the product under consideration to India during the relevant period.
- e) With regard to imports made by Excel's related company it is submitted that Excel Industries and Excel Crop Care are unrelated companies and none of the related parties of Excel Industries have imported the product under consideration. However, M/s. Excel Crop Care is in the category of companies over which key management personnel and/or their relatives have significant influence. "Key management person" as defined in Companies Act having significant influence over other companies does not imply that such key management personnel is legally or operationally in a position to exercise restraint or direction over the latter. Moreover, (i) Excel Crop Care and Excel Industries are not under the "same management", considering the provisions of Section 370(1b) and 372(11) of the Companies Act 1956 and (ii) Excel Crop Care and Excel Industries have only one common director between the two companies.
- f) Without prejudice it is submitted that Excel Crop Care has imported an insignificant volume of the product under consideration from China PR.
- g) The applicant accounts for 27.33% of the domestic production, while excluding production of M/s Sabero Organics, if any, being an importer of the subject goods. Moreover, the application was supported by M/s Excel Industries Limited, a major producer, whose collective production constitutes more than 50% i.e; 72.67% of the domestic industry production. As per Anti-Dumping Rules, M/s. Cheminova qualifies as Domestic Industry whose production constitutes a major proportion. The interested parties repeatedly stating "major proportion" whereas the requirement is "a major proportion". The application satisfied the requirement of the standing under Rule 5(3) read with Rule 2(b). Hence, the applicant constituted domestic industry within the meaning of Anti-Dumping Rules.

E.4. Examination by the Authority.

24. The views/submissions expressed by the interested parties relating to scope of domestic industry and standing in the post preliminary finding stage are examined hereunder:

- (i) Regarding qualification of M/s Cheminova India Ltd. as Domestic Industry, it is observed that in terms of Rule 2(b) read with Rule 5(3) of the Anti-Dumping Rules the Authority needs to be satisfied whether the application has been filed by or on behalf of the domestic industry.

Rule 2(b) of the Anti-Dumping Rules provides as follows:

"domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in which case such producers may be deemed not to form part of domestic industry ;

Rule 2(b) has been further amended vide Notification No. 18-2010-Customs(N.T.) dated 27th February, 2010 as follows:

"domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof; in such case the term 'domestic industry' may be construed as referring to the rest of the producers only.

Rule 5(3) of the Anti-Dumping Rules provides as follows:

The designated authority shall not initiate an investigation pursuant to an application made under sub-rule (1) unless -

- (a) it determines, on the basis of an examination of the degree of support for, or opposition to the application expressed by domestic producers of the like product, that the application has been made by or on behalf of the domestic industry :

Provided that no investigation shall be initiated if domestic producers expressly supporting the application account for less

than twenty five per cent of the total production of the like article by the domestic industry, and

- (b) it examines the accuracy and adequacy of the evidence provided in the application and satisfies itself that there is sufficient evidence regarding -
 - (i) dumping,
 - (ii) injury, where applicable; and
 - (iii) where applicable, a causal link between such dumped imports and the alleged injury, to justify the initiation of an investigation.

Explanation. - For the purpose of this rule the application shall be deemed to have been made by or on behalf of the domestic industry, if it is supported by those domestic producers whose collective output constitute more than fifty per cent of the total production of the like article produced by that portion of the domestic industry expressing either support for or opposition, as the case may be, to the application.

- (ii) Regarding requirement of polling before initiation, Authority observes that there is no prescribed legal requirement to resort to polling before initiation of investigation. Nor has the interested party established why such a recourse would have been necessary or even desirable in this case. The interested party in fact has not been able to establish till date that the petition lacked standing at any stage. It is also important to note that at the stage of initiation of investigation, the Authority is not required to hold a detailed enquiry. The Authority is merely required to satisfy itself prima-facie at the stage of initiation of investigation that the requirements prescribed under the Rule 5(3) are met. Verification of information through various sources with regard to various parameters, including collection of information from concerned administrative department, collection of import data from the DGCI&S or even from customs authorities are a matter of detailed investigation.
- (iii) It is observed that in the instant case the applicant company accounts for 27.33% of the domestic production, while excluding production of M/s Sabero Organics, if any, who has not responded to the investigation. The application was supported by M/s Excel Industries Limited, another major producer from the stage of application itself. Moreover, as per the DGCI&S data, M/s Sabero Organics has imported significant quantity of the subject goods from the subject country during the POI.
- (iv) The concerned Administrative Department was requested to provide details about the domestic producers and their production including M/s. Sabero Organics. Department of Chemicals & Petrochemicals provided information about M/s. Cheminova and M/s. Excel Industries only. In other words, the information available with the concerned administrative Ministry of the Govt.

of India with regard to this product does not even include M/s Sabero Organics as a producer. This information further reinforced the information submitted by the applicant in their application in this regard. After initiation of the investigation, M/s. Sabero Organics was also requested to submit their response, but there is no response till date. It is further observed that the submissions made by the applicant that M/s. Sabero Organics curtailed or stopped production substantially and resorted to imports and also consumed the product captively has remained un rebutted by M/s Sabero Organics before the Authority.

- (v) The contention that M/s. Cheminova suppressed information with regard to their relationship with their parent company in Denmark with the Designated Authority does not hold good. In fact there was no suppression of facts regarding relationship with the parent Company in Denmark. The Authority had specifically called for information in this regard before initiation and the facts were submitted by the applicant.
- (vi) It has been alleged that M/s Cheminova has got captive consumption of the subject goods and as per settled law captive consumption cannot be included while reaching pre-initiation determination. It has been further argued that failure of M/s Cheminova to disclose the details of their captive consumption of the subject goods in the non-confidential version of the application makes them ineligible to become domestic industry. However, the data of the domestic industry has already been verified and the Authority observes that:- Firstly, M/s Cheminova has declared its captive consumption in its petition under Proforma IV-A including the non-confidential version of the application available in the public file. Secondly, it is noted that the captive consumption of the company is very nominal, that is about *** Mt which constitutes about 1% of the total production of the domestic industry. Thirdly, if the quantity of captive consumption is excluded, the balance quantity still remains 26.53% and thus does not impact the standing.
- (vii) The submission that the exports made by M/s Cheminova Denmark, the parent company of M/s Cheminova India Ltd., to India disqualify the status of the later as domestic industry is not correct. The exports made by the parent company were not from the subject country, i.e. China PR, nor in significant volumes, nor at lower prices. The imports being from third countries, first and foremost, these imports cannot be treated as "dumped article". Rule 2(b) of the Rules defines domestic industry. After stating what domestic industry means, i.e., domestic producers as a whole or those whose collective output of the article constitutes a major proportion of the total domestic production, certain categories of domestic producers are excluded therefrom. The categories excluded are those domestic producers who are related to exporters of the alleged dumped article, those who are related to importers of the alleged dumped article; or those who themselves are importers thereof. The issue that arises for consideration therefore is what is the scope of the words alleged

dumped article. The group of domestic producers who are importers of alleged dumped article or are related to exporters of the alleged dumped article or are related to importers of the alleged dumped article can be treated differently under this provision. The domestic producers who are themselves importers should mean domestic producers who are themselves importers of alleged dumped article from the subject country. In other words, domestic producers who are not importers of alleged dumped article from the subject country are not to be excluded from the definition of "domestic industry."

- (viii) It has been argued that Excel Industries Ltd. has provided information post initiation of investigations and the same cannot be accepted and used by the Authority for the investigation. The Authority observes that M/s Excel Industries Ltd has expressly supported the petition filed by M/s Cheminova India Ltd at the time of initiation of investigation. Under Rule 6(4), the Authority issued a notice calling for information, in the prescribed form and manner, from various known interested parties, including the exporters, foreign producers and other interested parties. Such information is required to be provided by such parties. Rule 2(c) defines interested party and the same includes a producer of the like article in India or a trade and business association a majority of the members of which produce the like article in India. Thus, the Authority is required to call information from other Indian producers of the subject goods, who are not party to the petition. Such being the case, there is no justification in the argument that the Authority should not call for information from a company who commands a major share in Indian production, that too in an investigation where the product under consideration is being produced only by three producers. In fact, a copy of the initiation notification was also sent to M/s Sabero Organics. They however, preferred not to respond to the Authority.
- (ix) After perusing the information on record and verifying the same, it is noted that Excel Industries Ltd, Mumbai (supporter of the application) has not imported the subject goods during the entire relevant period. Further, the company has a number of related companies. Excel Industries has denied that any of its related company has imported the product under consideration during the relevant period. Information provided by Excel Industries Ltd, however, shows that Excel Crop Care Ltd is a group company and consumes DETPC. It is noted from the DGCI&S data that Excel Crop Care has imported only *** MT DETPC during the period of investigation as against the total Indian production of 9335 MT, demand of 20285 MT and imports of 12361 MT. In any case, the volume of imports made by the company is very insignificant constituting less than 1% of the Indian production.
- (x) The Authority also considered the possible impact of exclusion of Excel Industries Ltd from the fold of eligible domestic industry under the Rule 2(b). However, the Authority observes that in the event of exclusion of M/s Excel Industries Ltd from the purview of the domestic industry then in that case,

Cheminova's share in eligible Indian production would become 100%, since the other alleged producer M/s Sabero Organics is ineligible due to their significant imports of the subject goods from the subject country during POI and has not cooperated with the Authority.

25. In view of the above the Authority holds that imports made by Excel Corp Care does not in any way affect the status of Excel Industries Ltd. as domestic industry under Rule 2(b). Authority further notes that the provisions of Rule 2(b) as amended vide Notification No. 18-2010-Customs (N.T.) dated 27th February, 2010. The Authority examined whether the above drawn conclusion would have been different, considering the present legal provision. The Authority holds that the Excel Industries would have been construed as eligible domestic industry even under the amended Rule 2(b).
26. In the post disclosure, the interested parties have reiterated their arguments with regard to lack of standing of the petitioner. The issue was well considered by the Authority in the Preliminary Findings and also in the disclosure statement. They have argued that the findings of facts reached by the Authority in respect of Excel Industries is flawed and further these findings of facts have come at such a late stage of the proceedings. It is pointed out in this regard that if Excel Industries were to be treated as ineligible under Rule 2(b), the standing of the petitioner to maintain the present petition would have, at least, increased as brought out in the disclosure statement. Therefore, whether or not Excel Industries were to be treated as eligible or ineligible at the stage of initiation, the same would not have vitiated the present decision. Post initiation, since Excel Industries provided relevant information and further since Rule 2(b) provides for considering domestic producers as a whole as the domestic industry; and only in the absence of all the domestic producers, the law permits considering a major proportion as domestic industry; the Authority considered Cheminova and Excel as domestic industry at the stage of Preliminary Findings.
27. Interested parties have also contended that the relevant Rule does not permit exclusion of production of producers that are not being part of the domestic industry. This is because the term used is "a major proportion of the total domestic production". However, they have conveniently ignored the rest of the definition which provides that if any producer is related to the exporters or importers of the alleged dumped articles or itself an importer thereto, in which case such producers shall not be treated as part of the domestic industry. Further, while the Authority has referred to this issue in the context of standing under Rule 5(3), they are referring to this in the context of definition of domestic industry. Rule 5(3) provides that the application shall be deemed to have been made by or on behalf of the domestic industry, if it is supported by those domestic producers whose collective output constitute more than fifty per cent of the total production of the like article produced by that portion of the domestic industry expressing either support for or opposition, as the case may be, to the application. It is in this

context of Rule 5(3) that the Authority has concluded that the production of M/s Cheminova would be 100%, if Excel Industries were to be treated as ineligible.

28. In the above context post disclosure the interested parties have alleged that the Authority has applied different standards in different cases for considering significance of quantum of imports. They have stated that while in the instant case the Authority proposes to examine the significance of quantum of imports as a percentage of the total production, the same test has been applied as a percentage of total imports from the country concerned in the case of viscose filament yarn, diametrically opposite approaches. However, the Authority observes that in the present case imports in relation to all the three possible parameters i.e. in relation to total imports, production and consumption, constituted a small percentage.
29. After detailed examination and careful consideration of the submissions made on behalf of M/s. Meghmani Organics Ltd., Ahmedabad and other interested parties against the initiation of anti-dumping investigations in respect of the subject goods and the submissions made on behalf of the domestic industry in support of the initiation of anti-dumping investigations in the instant case and relying upon relevant Rules and judgments, it is observed that M/s Cheminova India Ltd., supported by M/s Excel Industries Ltd., constitutes Domestic Industry and the initiation of the anti-dumping investigations by the Authority is well within its jurisdiction under Anti-Dumping Rules and Law in this regard.

F. Confidentiality Issue

F.1 Views of the Importers

30. Post Preliminary Findings, M/S APJ-SLG, Law Offices representing M/s Gharda Chemicals Ltd., Meghmani Organics Ltd., Siris Crop Sciences Ltd. and PI Industries Ltd. has disputed the confidentiality of information contained in the submissions before the Authority. They have further disputed non-disclosure of certain information by the Authority in the preliminary findings and reiterated the issues in their post disclosure comments. Their arguments are briefly as follows:-
- a) The Designated Authority has not disclosed data and information obtained to construct normal value, whereas the data relevant to the international prices of all major inputs could not have been allowed to be kept confidential. When the normal value had been constructed by the Authority, the said Authority had no right to claim confidentiality in this regard.
 - b) We have also been denied access to non-confidential version of the questionnaire responses filed by the other participating parties which we presume should be part of the public file. Copies of all documents that have been filed before the Designated Authority ought to be made

available to us. In case of confidential documents, the non-confidential version should be made available in terms of Rule 6(7).

- c) Contrary to requirements of Rule 6(7) we have not been provided with the copies of the written submissions of other interested parties even when these interested parties have not claimed any confidentiality on the same.
- d) The Hon'ble Designated Authority should provide the detailed information as directed by the Hon'ble Bench of the Gujarat High Court vide its order dated 09.10.2009 and grant a fresh opportunity to all the interested parties to present their case.
- e) Interested parties had sought certain information/documents/data in various letters. The same have not yet been provided to them even at this stage of the investigations and they were awaiting receipt of these essential documents. In view thereof, these interested parties were handicapped to file full and meaningful rejoinder submissions.
- f) The interested parties requested the Authority to re-visit its decision and allow access to all documents that have been filed in the investigation. In any case documents which have been relied upon to reach the findings could not have been withheld from interested parties and ought to have been made available or kept in the public file.
- g) Domestic industry has alleged that responding exporters have filed questionnaire response which are grossly deficient and exporters have made excessive claims of confidentiality. In contrast, we notice that Domestic Industry has made excessive claims of confidentiality all throughout their application. Further, all subsequent submissions/data/information filed is contrary to Rule 7.
- h) It appears that claims of confidentiality in the present case are automatically allowed by the Designated Authority without examination of the nature of information.

F.2 Views of the Exporters/Industry Association

- 31. Post Preliminary Findings, M/s Dua Associates, representing M/s Yangxin Chentian Chemical Industry Co., Ltd., Zhejiang Xinnong Chemical Co., Ltd and China Crop Protection Industry Association, has expressed the following views on the confidentiality issue and reiterated the same post disclosure:-
 - a) Non-disclosure of relevant information by the authority which forms basis for its conclusions violates the requirements of transparency and is against the rules of natural justice.

- b) The failure to disclose crucial parameters such as normal value, dumping margin and injury margin and the components of calculations therein is against the rules of natural justice and requirements of transparency, and as such contrary to Rule 12 of Anti Dumping Rules and Article 6 of the Anti-dumping Agreement. As laid down in the case of Birla Ericsson, all these calculations ought to be disclosed by the Hon'ble Authority.
 - c) The non-disclosure of details of the Normal Value, dumping margin and injury margin including non injurious price and landed price calculations, has seriously affected the Chinese producers/exporters rights of defense and amounts to a gross violation of the principles of natural justice.
 - d) The Preliminary Findings and even subsequent thereto despite request thereof, the Hon'ble Authority has failed to disclose relevant information as to normal value, dumping and injury margin which has hampered the ability of the Chinese producers/exporters to respond to the same.
 - e) No information related to normal value has been disclosed with respect to major inputs that were considered such as source of the international prices, prices for each input, conversion cost, SGA expenses used, and profit Margin.
 - f) The Designated Authority has erred in observing that a conclusion drawn by the Authority based on confidential information also becomes confidential. The confidential data and conclusion emanating from the same can at least be disclosed to the concerned producer/exporter to whom the data relates.
32. Post Preliminary Findings, M/s Seth Associates on behalf of M/s Lianyungang Liben Agro-chemical Co. Ltd and Xingtai Pesticides Co., Ltd. has submitted that the Authority has provided no information on how the normal value of the product under consideration is constructed, such as the amount of cost of raw material, conversion cost, SGA expenses and finance cost, and profit margin. The constructed normal value is considered confidential, which substantially prevent our clients from commenting on the calculation and rebutting the Authority's decision. Post disclosure, no comment has been received from the above interested parties.

F.3 Views of the Domestic Industry

33. Post Preliminary Findings, the domestic industry has submitted that the information disclosed by the responding producers/exporters in the non-confidential version of their questionnaire responses are grossly deficient and does not permit reasonable understanding of the substance of information filed on confidential basis. The producers/exporters have not even filed indexed version of

any of the appendices. No reasons have been given for claiming confidentiality on these.

F.4 Examination by the Authority

34. The Authority has examined the confidentiality claims of the interested parties. In the preliminary findings, the data of the domestic industry concerning volumes of capacity, production and sales and imports data have not been kept confidential. The data of domestic industry in respect of customers, cost, prices and the data that would give competitive advantage to their competitors have been kept confidential.
35. The Authority after examining the submissions of the interested parties observed that the methodology of computation of Normal Value has been disclosed in the Preliminary Findings.
36. The Authority made available to all interested parties the public file containing non-confidential version of evidences submitted by various interested parties for inspection, upon request as per Rule 6(7). As regards providing a copy of the written submissions made by the interested parties, the Authority notes that these submissions have also been made available through the public file.
37. With regard to confidentiality issues, the Authority notes that the arguments of the interested parties and the specific requests for disclosure of (a) certain information provided by the interested parties, and (b) information relied upon by the Authority in the preliminary findings for which the Hon'ble Bench of the High Court of Gujarat passed a detailed order dated 9th October, 2009, on a writ petition No. 6881/2009 filed by M/s Meghmani Organics Ltd, directing disclosure of certain information. The Designated Authority vide Special Leave petition No. 887 of 2010, and separately, the domestic industry (M/s Cheminova India Ltd. vide Special Leave petition No. 34374 of 2009 and M/s Excel Industries Ltd. vide Special Leave petition no. 35243 of 2009), had challenged the order dated 9.10.2009 of Hon'ble Bench of the Gujarat High Court before the Hon'ble Supreme Court. After hearing the parties, the Hon'ble Supreme Court vide their order dated 8th February, 2010 was pleased to grant stay of the impugned orders.
38. Even when the contentions raised by the Writ petitioners before the Hon'ble Bench of the High Court of Gujarat are now pending adjudication before the Hon'ble Supreme Court, the Authority has considered various contentions raised in various writ petitions, examined the same and dealt with the same in the present findings.
39. A number of parties have represented before the Designated Authority claiming that the confidentiality claims made by other interested parties are inappropriate or that the Designated Authority has wrongly accepted the confidentiality claims

of the interested parties. In the writ petitions filed before the Hon'ble Bench of the High Court of Gujarat and Delhi, the petitioners have challenged the grounds of confidentiality by the Designated Authority with regard to various data/information in the Preliminary Findings issued by the Designated Authority. The Hon'ble Bench of the High Court of Gujarat, ordered to disclose information which are kept blank while recording the preliminary finding such as the following:

- a) Information relating to normal value -
 - (i) Reasonable Profit margin
 - (ii) Ex-factory cost excluding interest
 - (iii) Cost of raw material
 - (iv) Conversion cost
 - (v) SGA expenses
 - (vi) Normal value

- b) Information relating to export price -
 - (i) Export volume
 - (ii) CIF export price per unit
 - (iii) Price adjustment
 - (iv) Ocean freight
 - (v) Inland freight
 - (vi) Other auxiliary fees
 - (vii) Credit cost
 - (viii) Bank charges

- c) Information relating to injury-
 - (i) Selling Price
 - (ii) Price-undercutting
 - (iii) Cost of Sale for whole injury period
 - (iv) Landed price of import
 - (v) NIP
 - (vi) Injury margin for different exporters
 - (vii) Price underselling
 - (viii) Return on capital employed GFA and NFA basis for whole injury period
 - (ix) Cash flow for whole injury period
 - (x) Cash profit for whole injury period
 - (xi) Export volume for whole injury period

40. After careful examination of various contentions of the interested parties, the orders of the Hon'ble Bench of the High Court of Gujarat, the legal provisions under the Indian Rules & WTO Agreement of Anti Dumping and considering the principles of natural justice, the Authority observes as follows:-

a) With regard to confidentiality of information Rule 7 of Anti-dumping Rules provides as follows:-

Confidential information. (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.

b) The WTO Agreement on Anti Dumping provides as follows with regard to confidentiality of information :-

Article-6.5 Any information which is by nature confidential (for example, because its disclosure would be of significant competitive advantage to a competitor or because its disclosure would have a significantly adverse effect upon a person supplying the information or upon a person from whom that person acquired the information), or which is provided on a confidential basis by parties to an investigation shall, upon good cause shown, be treated as such by the authorities. Such information shall not be disclosed without specific permission of the party submitting it.

Article-6.5.1 The authorities shall require interested parties providing confidential information to furnish non confidential summaries thereof. These summaries shall be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information submitted in confidence. In exceptional circumstances, such parties may indicate that such information is not susceptible

of summary. In such exceptional circumstances, a statement of the reasons why summarization is not possible must be provided.

Article-6.5.2 If the authorities find that a request for confidentiality is not warranted and if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, the authorities may disregard such information unless it can be demonstrated to their satisfaction from appropriate sources that the information is correct.

Footnote to Article 6.5.2 (footnote 18 of the WTO Agreement on Anti Dumping) provides as follows :-

Members agree that requests for confidentiality should not be arbitrarily rejected.

41. It is thus evident that the public notices issued by the authorities are directly subjected to confidentiality provisions and should protect confidentiality of information provided by an interested party. Further, a conclusion drawn by the Authority based on confidential information also becomes confidential, if disclosure of such conclusion can in any way effectively lead to disclosure of information provided on confidential basis.
42. The Authority also examined the legal provisions and practices of other investigating Authorities and observed that similar public notice/communications issued by other investigating Authorities as well, does not include any confidential information while issuing findings.
43. With regard to the submission of the interested parties that the Designated Authority has not disclosed the reasons of confidentiality, the Authority notes as follows in this regard:-
 - (i) The WTO Agreement on anti-dumping and Anti-dumping Rules very clearly specifies what is required to be treated as confidential information.
 - (ii) The Authority holds that any information which is, by nature confidential or which has been provided on confidential basis is required to be treated as confidential information and cannot be disclosed to other interested parties.
 - (iii) While disclosing any information in its communications/orders, the Designated Authority is required to ensure that such disclosure of information should not eventually lead to disclosure of information provided on confidential basis by an interested party. In other words, in case any interested party would be able to reach to confidential information provided by another interested party, the said information cannot be disclosed by the Authority.

- (iv) While the interested parties providing information on confidential basis are required to give reasons for claiming confidentiality, the Authority is not required to give reasons for confidentiality of information contained in the public notice. Under the Rules, the Authority is required to be satisfied with regard to reasons for confidentiality claimed by various interested parties.
- v) Some interested parties have demanded a copy of the communications sent by the Authority to various interested parties. These interested parties have also demanded a copy of the communications between the Authority and the applicant domestic industry prior to initiation. The Authority notes that data/information must be distinguished with documents. The request made by the interested parties includes a number of documents. This request was pressed before the Hon'ble Bench of the High Court of Gujarat. However orders of the Hon'ble Division Bench of High Court of Gujarat does not cover any such request. Further, in any case, the Authority does not consider it appropriate to make available communications made by the Authority to the interested parties before or after initiation of investigations.
- vi) Under the rules, the Authority receives documents from interested parties. Confidentiality provision provides that information provided to the Authority on confidential basis cannot be disclosed to other interested parties. Even if the claim of confidentiality is unwarranted, the Authority is best authorized to disregard such information. As per Rule 7 of the Anti Dumping Rules and Article 6.5 of the Anti Dumping Agreement the Designated Authority is required to keep an information as confidential if submitted to him on confidential basis by any interested party. The Authority is not authorized to disclose or make public such information.
- vii) The provision for disclosure of essential facts before giving final findings has been laid down at Rule 16 of the Anti-dumping Rules. Even under Rule 16, the confidential facts are required to be disclosed to "respective interested parties", while non-confidential facts are required to be disclosed to all interested parties. At no stage the Designated Authority is empowered to disclose the confidential information to the parties with competing and conflicting interests. Thus it would be sufficient if full explanation of the reasons for the methodology used in the establishment and comparison of the export price, normal value and Non-injurious price are disclosed by the Designated Authority instead of disclosing the actual figures. Normal Value, export price and non-injurious price are based on the confidential information submitted by the parties and disclosure of the same would be of significant competitive advantage to a competitor and its disclosure could have a significantly adverse effect upon the person supplying the information.

viii) Disclosure of the commercially sensitive and confidential information, provided by the interested parties to the Designated Authority, by reposing trust and confidence, to facilitate the investigation, will completely vitiate the market atmosphere both in the domestic as well as international fronts. The disclosure of confidential information relating to the cost of production, non-injurious price etc. of the domestic industry will provide undue advantage to its domestic as well as overseas competitors and place them in a disadvantageous position before the consumers. Likewise disclosure of the confidential information relating to the exporters such as normal value, net export price, landed price etc. will jeopardize their commercial interest vis-à-vis their competitors as well as buyers.

44. The interested parties have also disputed the Authority's position that the conclusion drawn on the basis of confidential information is also confidential. Further, they have said that the information can be disclosed at least to the very same party to whom the confidential information pertains. It is reiterated in this regard that any conclusion drawn on the basis of confidential information would indeed remain confidential. Disclosure of any such information would enable other parties to reach to the confidential information of interested parties and would defeat the very purpose for which confidentiality has been granted. This is the position taken by the Designated Authority in the SLP filed before the Supreme Court. As regards disclosure of information to an interested party to whom the information pertains, the Authority observes that the same has already been disclosed to the concerned parties.

G. Other Issues Raised By the Interested Parties

- a) This was not a fit case for imposition of provisional duties. The preliminary findings have been issued by the Designated Authority contrary to the mandatory requirements of Rule 12. In the absence of any material on record to reach such mandatory determination that measures were necessary to prevent injury being caused during the investigation, the recommendations made in the preliminary findings are contrary to Rule 12, read with Rule 20 and Article 7.1(iii).
- b) Written submissions provided by the domestic industry are not serial numbered properly, making it difficult for interested parties to offer para-wise comments as required by the Hon'ble Designated Authority in terms of the Trade Notice No. 1/2007 dated 22nd October 2007.
- c) Response of M/s Excel has been accepted without the support of certificate of truthfulness.
- d) Designated Authority has not recorded any findings in terms of Rule 12 to the effect that the present case was an appropriate case where it was necessary to resort to preliminary findings recommending provisional duties.

G.1 Examination by the Authority

45. The submissions of interested parties have been appropriately dealt with in accordance with law. The Authority has carried out an objective examination of alleged dumping and consequent injury to the domestic industry at preliminary stage and the preliminary findings were recorded based on the sufficiently detailed information and in accordance with the Anti-dumping Rules and established procedure. As regards appropriateness of recommending interim anti dumping duties, the preliminary finding issued by the Authority is self-explanatory vide which the Authority had recommended imposition of interim anti dumping duties.
46. As regards the manner in which the domestic industry filed written submissions, the Authority reiterates that there is no prescribed requirement that an interested party should file written submissions, which are paragraph numbered. Written submissions filed by an interested party cannot be ignored/rejected for such reasons. Nor can it be appreciated that an interested party is unable to offer comments on the written submissions because the same are not paragraph numbered. What the Trade Notice No. 1/2007 dated 22nd October 2007 issued by the Authority requires is that the rejoinders to the written submissions filed by the interested parties should be in the form of exact parawise comments to the written submissions.
47. Regarding the allegation that M/s Excel's information has been accepted without certificate of correctness, it is observed that the data of the concerned constituent of the domestic industry has been verified and a certificate of correctness may not be necessary at this stage.
48. Post disclosure the interested parties have stated that the Authority has not recorded reasons for recommending provisional duties. However, the reasons for recording preliminary findings have been recorded in the Preliminary Findings itself.

H. Determination of Normal Value, Export Price and Dumping Margin**H.1 Examination of Market economy claims**

49. The Authority, notes that in the past China PR has been treated as a non-market economy country in the anti-dumping investigations by other WTO Members. Therefore, in terms of Para 8 (2) of the Annexure-I to the Anti-dumping Rules, China PR has been treated as a non-market economy country subject to rebuttal of the above presumption by the exporting country or individual exporters in terms of the above Rules.

50. As per Paragraph 8, Annexure I to the Anti Dumping Rules as amended, the presumption of a non-market economy can be rebutted if the exporter(s) from China PR provide information and sufficient evidence on the basis of the criteria specified in sub paragraph (3) in Paragraph 8 and prove to the contrary. The cooperating exporters/producers of the subject goods from People's Republic of China are required to furnish necessary information/sufficient evidence as mentioned in sub-paragraph (3) of paragraph 8 in response to the Market Economy Treatment questionnaire to enable the Designated Authority to consider the following criteria as to whether :-
- a) The decisions of concerned firms in China PR regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values;
 - b) The production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation of debts;
 - c) Such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms; and,
 - d) The exchange rate conversions are carried out at the market rate.
51. The Authority notes that following producers/exporters of the subject goods from the subject country have submitted market economy questionnaire responses along with their questionnaire responses consequent upon the initiation notice issued by the Authority and rebutted the non-market economy presumption. The questionnaire responses and the Market economy responses of such responding producers/ exporters as listed below have been examined for determination of dumping margin. For the responding producers/exporters, the Authority has determined individual dumping margin and examined market economy status in accordance with the Anti-dumping Rules :-

S.N.	Name of the producers/exporters
1.	Yangxin Chentian Chemical Industry Co., Ltd.
2.	Lianyungang Liben Agro-chemical Co., Ltd.
3.	Xingtai Pesticides Co., Ltd.
4.	Zhejiang Xinnong Chemical Co., Ltd.

H.2. Views of the Domestic Industry

- a) Market economy status cannot be given in a situation where one of the major shareholders is a State owned/controlled entity.
- b) It is evident from preliminary finding that Authority notes that in a situation where one of the shareholders in the company is a State owned/controlled entity having significant share in the company, possibilities of State interference cannot be ruled out.
- c) Market economy status cannot be given unless the responding Chinese exporters establish that the prices of major inputs substantially reflect market values. Domestic industry submits that "substantially reflect market values" has been widely interpreted to mean that the price of these inputs must be comparable to the prices prevailing in the international market.
- d) Market economy status cannot be given unless the responding exporters establish that their books are audited in line with international accounting standards.
- e) Market economy status cannot be granted even if one of the parameters is not satisfied.
- f) Domestic industry submits that it is not for the Authority to establish that the responding companies are indeed operating under market economy environment and are entitled for market economy treatment. On the contrary, it is for the responding Chinese exporters to establish that they are operating under market economy conditions.
- g) In a situation where the current shareholders have not set up their production facilities themselves but have acquired the same from some other party, market economy status cannot be granted unless process of transformation has been completely established through documentary evidence.
- h) Domestic industry submits that failure to satisfy the conditions mentioned above by the responding Chinese exporters is sufficient to hold that market economy status cannot be granted to responding Chinese companies and thus the normal value should be determined in accordance with Para-7 of the Rules.

H.3. Views of the Exporters

52. Post preliminary findings and post disclosure M/s Dua Associates representing M/s Yangxin Chentian Chemical Industry Co., Ltd., and Zhejiang Xinnong Chemical Co., Ltd made following submissions with regard to MET :-

- a) In the Preliminary Findings, the Hon'ble Designated Authority has directly rejected the market economy treatment request of M/s Yangxin Chentian Chemical Industry Co., Ltd., and Zhejiang Xinnong Chemical Co., Ltd and has

proceeded to construct the Normal Value as per facts available.

- b) M/s Yangxin Chentian Chemical Industry Co., Ltd. and Zhejiang Xinnong Chemical Co., Ltd are purely private companies.
 - c) None of the shareholders of M/s Yangxin Chentian Chemical Industry Co., Ltd. and Zhejiang Xinnong Chemical Co., Ltd are state-owned/controlled company. On the contrary, all of the shares of M/s Chentian are owned by Chinese individuals.
 - d) M/s Yangxin Chentian Chemical Industry Co., Ltd. and Zhejiang Xinnong Chemical Co., Ltd have supplied abundant information about its basic inputs for production, including the name of suppliers, the nature and type of ownership of the same, the quantities and value of the inputs, etc.
 - e) M/s Yangxin Chentian Chemical Industry Co., Ltd. and Zhejiang Xinnong Chemical Co., Ltd both use the spot prices and market conditions drive sales prices of the basic inputs for production. Prices of basic inputs substantially reflect market value as required by the Anti Dumping Rules. Further, the raw materials have been purchased by M/s Chentian and Xinnong at international prices.
 - f) Two major inputs of DTPC are procured from different suppliers, most of which are private companies, purchase price for the same material fluctuates from time to time, which rightly reflects the demand and supply variation trend.
 - g) Phosphorus pentasulphide is not the same as yellow phosphorus. It is submitted that the statement that yellow phosphorus constitutes 20-25% of the costs in DTPC is patently incorrect and all submissions of the domestic industry with regard to price of yellow phosphorus are wholly unsubstantiated and irrelevant to the present case. Hence, they cannot be used to deny market economy treatment to Chinese companies.
 - h) Designated Authority has presumed that if the purchase price of certain inputs is not equal to the international price, then, the purchase price does not reflect the "Market Value" of the input concerned. It is reiterated that the "market value" need not necessarily be equal to "prevailing international price". The connotation of the word "market value" lies in emphasizing that the pricing mechanism of a certain product is decided by market power based on demand and supply.
53. M/s Seth Associates on behalf of M/s Lianyungang Liben Agro-chemical Co. Ltd and Xingtai Pesticides Co., Ltd. made the following submissions with regard to MET, subsequent to preliminary findings, but no comments were received from them on the exporter's verification report and disclosure statement issued by the Authority:-

- a) Our Clients independently make the decision on the management, purchase the inputs at market prices and sell the product under consideration on the supply and demand basis.
- b) No Government or Government agency interferes in the daily operation of the company concerned. Our clients have provided sufficient information in their responses to market economy treatment questionnaire to substantiate the qualification for the market economy status and should be granted the market economy treatment.

H.4 Examination by the Authority

54. The Authority had conducted verification of the above stated four responding producers/exporters. Issues relating to Market Economy Claim made by these responding producers/exporters were also examined during the on the spot verification and a verification report was issued to each one of these responding producers/exporters. Notwithstanding their claim on Market Economy Treatment (MET), the Authority concludes that the status in respect of all the four continues to be "Operating under Non-Market Economy" conditions on account of the following:-

M/s Zhejiang Xinnong Chemical Co., Ltd.

55. Although the company has claimed to have been set-up in 1999 as a limited liability company, it could not substantiate with satisfactory documentary evidence as to how a trademark "Xinnong" existed a decade back predating the establishment of the company. This inter-alia substantiates that the Company existed in 1989 as well, which fact was concealed by the responding producer/exporter. Further, the source of funds, purpose of investment and relationship with M/s Jiangsu Rural Credit Co-operative could not be substantiated with satisfactory documentary evidence. However, in their post-verification comments they have admitted that M/s Jiangsu Rural Credit Cooperative is their subsidiary, the fact they had not declared earlier. That apart, issues related to non-availability of records regarding source of funds, existence of a supervisory board controlled by the Ministry of Audit above the board of directors, the Company getting substantial subsidies/grants from the Government as evidenced by the balance sheet for the year 2007; the Company not providing any evidence whatsoever demonstrating that the prices of major inputs consumed by them substantially reflect market values, amply make it clear that the subject producer/ exporter is operating under Non Market Economy (NME) conditions and therefore, the Authority holds them to be a NME company for the purpose of this investigation.

M/s Yangxin Chentian Chemical Industry Co., Ltd.

56. Although the company claimed to have been set-up in 2002 as a limited liability company, no satisfactory explanation / documents could be provided explaining how the company was set up in 2002 when the Land Use Right was obtained in 2004. The Company had actually grown out of the erstwhile State owned company M/s Huangshi City Fuchi Phosphate Factory (a State-owned Company), although this fact was denied by them. They failed to substantiate that the mode of the transfer of land and assets of this erstwhile State owned company was at market value and also how they dealt with the existing plant and equipments after taking over of the company. Post disclosure the interested party has claimed that the said transfer of land and assets was at market price, but, no documentary evidence was provided to support the claim. Further, Mr. Yin Qian, the Chairman of the subject company, was earlier working in another State owned company namely M/s Yangshin Chemical Factory in the Yangshin District. The subject company had signed a tripartite agreement with M/s Wenzhou Dragon Dyestuff Plant (details of this company not declared) and the Government of the Peoples Republic of China for restructuring and reforming M/s Yangshin Chemical Factory and jointly acquired the assets of this State owned company and received substantial State subsidies and grants. Moreover they had also received substantial subsidy for the purpose of foreign trade development. Regarding the source of the funds by the individual shareholders/ investors in the company, no satisfactory reply/ document could be provided. The company has not provided any evidence whatsoever demonstrating that the prices of major inputs consumed by them substantially reflect market values.

M/s Lianyungang Liben Agro-chemical Co., Ltd. and M/S Xingtai Pesticides Co., Ltd.

57. In respect of these two producers/exporters, the Authority had issued exporter's verification report amply indicating that they are operating under non-market economy conditions. However, no comment on the verification report has been received from them by the Authority. The Authority had also highlighted each of these issues related to MET claim in the disclosure statement as well, which was not responded to by these producers/exporters. In view of the above, the Authority concludes that these two producers/exporters have admitted to be operating under non-market economy conditions and therefore the Authority grants them NME status for the present investigation.
58. The Authority had not granted market economy treatment in the Preliminary Findings as none of the producer/exporter had established with verifiable evidence that "prices of major inputs substantially reflect market values". It was further observed in the Preliminary Findings that in a situation where the raw material prices are significantly lower than the prevailing market rates in the international market, not only a vital condition for market economy treatment is not satisfied but also costs may be underestimated. The Authority had therefore taken a view in the preliminary findings that even if one of the critical parameters

of market economy treatment is not satisfied it would not be feasible to grant market economy status to the responding companies.

59. In view of the issues concerning ownership and control, their impact on the cost and prices and business decisions of the companies, and verification of the same, the Authority has not granted market economy status to any of the subject producers/exporters for the determination of Normal Value.

I. Normal Value, export price and dumping margin.

I.1. Views of the interested parties

60. M/s Seth Associates on behalf of M/s Lianyungang Liben Agro-chemical Co. Ltd and Xingtai Pesticides Co., Ltd. had made the following submissions subsequent to preliminary findings, but offered no comments post disclosure:-

- a) The Authority provides no information on how the normal value of the product under consideration is constructed, such as the amount of cost of raw material, conversion cost, SGA expenses and finance cost, and profit margin. The constructed normal value is considered confidential, which substantially prevent our client from commenting on the calculation and rebutting the Authority's decision.
- b) The Customs Tariff Commission of State Council issued the Circular on adjustment of Export Tariff on Certain Goods which come in to effect as of July 1, 2009. The Circular cancel the special export tariff, 50%, as previously levied on the yellow phosphorus which is a key raw material for the manufacturing the DETPC. After the Circular comes in to effect, the export tariff applicable to the export of yellow phosphorus from China PR shall be 20%, far less than 70% before adjustment. Since Indian DETPC producers import a large volume of yellow phosphorus from China PR for manufacturing DETPC, our clients believe that the adjustment of export tariff of yellow phosphorus will significantly lower the production cost of Indian Producers. Therefore our client respectfully request DGAD to consider this factor and reduce the dumping margin and/or injury margin accordingly in the upcoming final findings.

61. M/s Dua Associates representing M/s Yangxin Chentian Chemical Industry Co., Ltd., Zhejiang Xinnong Chemical Co., Ltd. and China Crop Protection Industry Association, made following submissions subsequent to preliminary findings and post disclosure:

- (a) Chinese producers/exporters have provided detailed data for determination of Normal Value as part of the response to the Exporters Questionnaire and the same ought to have been taken into consideration for determining the Normal Value and the Hon'ble Designated Authority ought to have considered the domestic sale price of DETPC in China PR as the basis for

determining the Normal Value of the subject goods based on Section 9A(1)(c)(i) of the Customs Tariff Act, 1975 ("the Act") read with the provisions of paragraphs 1 to 6 of Annexure I of the Anti Dumping Rules.

- (b) The Hon'ble Authority has committed error in determining normal value on the basis of "available reasonable basis" and constructing the same "based on facts available".
- (c) Designated Authority in so doing has ignored some of the factors which affect comparability of the prices and costs and have failed to make adjustments for the same.
- (d) The advantages enjoyed by Chinese producers/ exporters with regard to their economies of scale, procurement logistics, process infrastructure, geographical reasons and availability of raw material, have complete relevance and bearing to both the dumping and injury analysis since they lead to lower cost of production. However, the said advantages have been completely ignored by the Hon'ble Designated Authority while determining the Normal Value.
- (e) By using India as a surrogate country and constructing normal value on the facts available and disregarding the advantages enjoyed by Chinese producers, instead of basing assessment of normal value on the facts submitted as part of response to exporters questionnaire, an artificially high normal value has been arrived at, which has led to an erroneous conclusion of dumping to the detriment of Chinese companies.
- (f) Hon'ble Authority has failed to distinguish between export sales and domestic sales and that the same has undoubtedly led the Hon'ble Authority to an artificial ex-factory export price which may be far lower than the real ex-factory export price. The sales to unaffiliated traders in China PR are reported as domestic sales by it and it is not understood on what basis these have been considered as part of export sales by the Hon'ble Authority.
- (g) The Authority has not followed the procedure of Rule 7 for establishing non-market economy with regard to selection of third country market economy or surrogate country for determination of normal value.
- (h) The full methodology for arriving at normal value, export price, dumping margin and NIP are not disclosed by the Designated Authority.

1.2. Examination by the Authority

62. In terms of Para 8 (2) of the annexure of Anti-dumping Rules, China PR has been treated as a non-market economy country subject to rebuttal of the same by the

exporting country or individual producer/exporter in terms of the above Rules. The cooperating exporters/producers of the subject goods from People's Republic of China are required to furnish necessary information/sufficient evidence as mentioned in sub-paragraph (3) of paragraph 8 in response to the Market Economy Treatment questionnaire to enable the Designated Authority to consider their claim for market economy treatment.

63. The Authority indicated, in the initiation notification, that the applicant claimed that China PR is a non market economy and that India, China and Denmark are the only known producers of the product under consideration in the World. The applicant domestic industry had determined normal value based on the cost of production in India, including selling general & administration expenses and profit. Authority invited comments from all interested parties in accordance to Para 7 of Annexure I. However, none of the interested parties, including the applicants and Chinese producers/exporters have placed any material fact before the Authority to select an appropriate market economy third country for this purpose. The domestic industry has submitted that India should be treated as an appropriate surrogate country for China PR in this matter and the normal value should be determined accordingly. None of the opposing parties have disputed the claim of the domestic industry with regard to production facilities being available only in three countries – China, India and Denmark. However, they have argued that by using India as a surrogate country and constructing normal value on the facts available and disregarding the advantages enjoyed by the Chinese producers instead of basing assessment of normal value on the facts submitted as part of their responses to exporters questionnaire, an artificially high normal value has been arrived by the Designated Authority. The Authority notes that China PR is a non-market economy country and advantages enjoyed by Chinese producers/exporters cannot be taken in to account while determining Normal Value. The Authority also notes that Denmark is a developed country and may not be an appropriate third country for the Chinese producers.
64. The Authority would determine individual normal value for each co-operating producer/ exporter in accordance with Section 9A of Customs Tariff Act, 1975 amended from time to time. However, individual normal value can only be determined in case of responding producers/exporters from China PR if they are able to rebut the NME presumption to the satisfaction of the Authority. Since in the instant investigation, none of the responding producers/exporters from the subject country could rebut the NME presumption to the satisfaction of the Authority, the Authority has determined normal value as per Para 7 of Annexure 1 of the anti-dumping Rules.
65. As recorded above, cost and prices of the responding producers/exporters from China PR are significantly affected by non-market economy situation and therefore, the normal value cannot be determined in terms of Para 1 to 6 of

Annexure-I to the Rules. Therefore, the Authority refers to Para 7 of the said Annexure for determination of normal value in China PR for the subject goods.

66. In this connection Para 7 of Annexure I of the Anti-dumping Rules provides that:-

In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.

67. The Authority has followed the prescribed procedure and consistent practice for determining the normal value, export price, dumping margin and the non-injurious price and the methodology for determination of the same has been disclosed in the disclosure statement itself.

68. The Authority had recorded in the preliminary findings that in the absence of any reliable data in respect of cost and prices of the subject goods in an appropriate third country, normal value was determined on the basis of the third option available in the Rules, which provides for adoption of any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. Accordingly, the ex-works Normal Value of the product under consideration for all producers/exporters from China PR has been constructed based on the facts available. The Normal Value had been constructed taking into account international prices of all the major inputs. Consumption norms had been considered as per claims made by the responding producers/exporters, conversion cost and SGA expenses had been adopted on the basis of efficient domestic producer. After adding a reasonable profit margin of 5% of ex-factory cost excluding interest, constructed normal value for the preliminary findings was worked out as US\$ ***/Kg.

69. After verification of the producer/exporter's data from the subject country and in view of the non-market economy status meted out to them and since no interested party has provided the data of any appropriate third country, the Authority has adopted the third option available in the Rules, which provides for adoption of

any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin and constructed the normal value in respect of the subject country. The Normal Value has been constructed taking into account international prices of all the major inputs. Weighted average consumption norms of cooperating Chinese producers has been considered and conversion cost and SGA expenses adopted on the basis of the efficient domestic producer, and after adding a reasonable profit margin of 5% of ex-factory cost excluding interest, constructed normal value has now been worked out as follows:-

	US\$ per Kg
Cost of raw materials	***
Conversion Cost	***
SGA Expenses and Finance cost	***
Profit margin	***
Constructed Normal Value	***

J. EXPORT PRICE

J.1. CO-OPERATIVE EXPORTERS

J.1.a. M/s Zhejiang Xinnong Chemical Co. Ltd.

70. M/s Zhejiang Xinnong Chemical Co. Ltd. has reported export of *** Mt of the subject goods to India during the POI. This company has claimed adjustments towards ocean freight, insurance, VAT adjustment, commission, inland transportation, other auxiliary fees and bank charges to arrive at ex-factory export price. The Authority has determined the ex-factory export price of this producer/exporter as US\$ *** per kg. after making adjustments for the expenses as per table given at para 74 below.

J.1.b. M/s Yangxin Chentian Chemical Industry Co. Ltd.

71. Yangxin Chentian Chemical Industry Co. Ltd. has reported export of *** Mt of the subject goods to India during the POI. The exporter has claimed adjustments towards ocean freight, insurance, commission, inland transportation, other auxiliary fees and bank charges to arrive at ex-factory export price. However, during verification of the exporter's data, it was noticed that no adjustment towards VAT paid and refund obtained has been made though the exporter is required to pay VAT @17% of the invoice value and is entitled for a refund of a part of the VAT paid on exports. Such adjustments have therefore been made based on the invoice value. The Authority has therefore determined the ex-factory export price of this producer/exporter as US\$ *** per kg. after making adjustments for the expenses as per table given at para 74 below.

J.1.c. M/s Xintai Pesticides Co. Ltd.

72. M/s Xintai Pesticides Co. Ltd. has reported export of *** Mt of the subject goods to India during the POI. The exporter has claimed adjustments towards overseas transportation, inland freight, port surcharge, bank charges, credit cost and overseas insurance to arrive at ex-factory export price. However, during the verification of the exporter's data it was noticed that no adjustment towards VAT paid and refund obtained has been made though the exporter is required to pay VAT @17% of the invoice value and is entitled for a refund of a part of the VAT paid on exports. Such adjustments have therefore been made based on the invoice value. The Authority has therefore determined the ex-factory export price of this producer/exporter as US\$ *** per kg. after making adjustments for the expenses as per table given at para 74 below.

J.1.d. M/s Lianyungang Liben Agro Chemical Co. Ltd.

73. M/s Lianyungang Liben Agro Chemical Co Ltd has reported export of *** Mt of the subject goods to India during the POI. The exporter has claimed adjustments towards overseas transportation, overseas insurance, credit cost, VAT, inland freight and port charges to arrive at ex-factory export price. The Authority has determined the ex-factory export price of this producer/exporter as US\$ *** per kg. after making adjustments for the expenses as per table given at para 74 below.

74. The ex-factory export prices for the above cooperative producers/exporters are determined as follows: -

	Unit	Yangxin Chentian	Lianyungang Liben	Xingtai Pesticides	Zhejiang Xinnong
Export volume	Mt	***	***	***	***
Export price per unit	US\$/Kg	***	***	***	***
Price adjustments					
<input type="checkbox"/> Ocean freight	US\$/Kg	***	***	***	***
<input type="checkbox"/> Insurance	US\$/Kg	***	***	***	***
<input type="checkbox"/> Commission	US\$/Kg	***	***	***	***
<input type="checkbox"/> Inland freight	US\$/Kg	***	***	***	***
<input type="checkbox"/> Other Auxiliary Fees	US\$/Kg	***	***	***	***
<input type="checkbox"/> Credit Cost	US\$/Kg	***	***	***	***
<input type="checkbox"/> Bank charges	US\$/Kg	***	***	***	***
<input type="checkbox"/> VAT differential.	US\$/Kg	***	***	***	***
<input type="checkbox"/> Total adjustment	US\$/Kg	***	***	***	***
Ex-factory export price	US\$/Kg	***	***	***	***

J.1.e. Non -Cooperative Exporters

75. Since no other response has been received from any other producer/ exporter of the subject goods from the subject country, the Authority has decided to

determine the export price in respect of non-cooperating exporters, as per facts available in terms of Rule 6(8) of the Anti-dumping Rules. Adjustments at par with the ones allowed in case of co-operating producers/exporters has been allowed for arriving at their export price at ex-factory level. By adopting this method the export price at ex-factory level in respect of non-cooperating exporters for the subject goods worked out by the Authority is US\$ *** per kg. on the basis of facts available.

76. As regards the submission of M/s APJ-SLG for providing the details of computation of dumping margin, the Authority notes that the details of export price have already been provided to the respective responding producer/exporter in the disclosure statement. The methodology of determination of constructed normal value was suitably disclosed in the disclosure statement along with the percentage of dumping margin arrived at.
77. As regards the submission of M/s Dua Associates, the Authority notes that the export price arrived at with adjustments was disclosed to respective responding producer/exporter along with methodology adopted for determination of the same. The methodology of determination of constructed normal value was also suitably disclosed in the disclosure statement along with the percentage of dumping margin arrived at.
78. As regards the submission of M/s Dua Associates regarding the impact of prices of yellow phosphorus, the Authority notes that the Phosphorus Pentasulphide (P₂S₅) is an intermediate and is produced from Yellow Phosphorus. Prices of Phosphorus Pentasulphide are governed more by prices of yellow phosphorus than by the product itself. If price of yellow phosphorus goes up, price of Phosphorus Pentasulphide also goes up.
79. As regards the submission of M/s Dua Associates, in respect of advantages enjoyed by Chinese producers/ exporters with regard to their economies of scale, procurement logistics, process infrastructure, geographical reasons and availability of raw materials, the Authority notes that since the Chinese producers/exporters have not been granted market economy treatment, the Authority has determined normal value based on the methodology explained in para 69.
80. The following views have been expressed by the Domestic Industry in the post disclosure stage:
 - i) The export price of Xintai Pesticides must be rejected in view of diversion of exports through them due to lower duty imposed on them.
 - ii) All the exporters should be declared non-cooperating due to non-declaration of essential facts in their responses.

81. Regarding the view of the domestic industry that the export price of M/s Xintai Pesticides must be rejected in view of diversion of exports through them due to lower duty imposed on them is concerned, the Authority observes that the allegation is unsubstantiated and developments post POI cannot constitute part of the subject investigation. Further, the Authority observes that the subject producers/exporters had submitted responses and cooperated for verification of their data and therefore it will not be proper to declare them as non-cooperative as claimed by the Domestic Industry.

K. Dumping Margin

82. Considering the normal value and export price determined, as explained above, the Authority has determined dumping margin as follows;

	Unit	Yangxin Chentian	Lianyungang Liben	Xingtai Pesticides	Zhejiang Xinnong	Non- cooperative
Normal value	US\$/Kg	***	***	***	***	***
Export price	US\$/Kg	***	***	***	***	***
Dumping margin	US\$/Kg	***	***	***	***	***
Dumping margin	Range %	70-80	40-50	30-40	45-55	85-95

L. Injury and Causal Link

83. Article 3.1 of the WTO Agreement and Annexure-II of the Anti-dumping Rules provide for an objective examination of both, (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices, in the domestic market, for the like products; and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to the volume effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been a significant increase in the dumped imports, either in absolute term or relative to production or consumption in India. With regard to the price effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices to a significant degree, or prevent price increases, which would have otherwise occurred to a significant degree.
84. The Authority has determined the injury to the domestic industry and causal link between the dumped imports and injury, taking into account all relevant facts in accordance with Rule 11 of Anti-dumping Rules and Annexure-II of the Anti-dumping Rules.
85. The Authority notes that the injury analysis has been appropriately carried out in terms of numbers with regard to the injury parameters such as capacity, production, sales, stock, market share etc. As regards the impact of the dumped imports on the domestic industry para (iv) of Annexure-II of the Anti-dumping Rules states as follows:-

"The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned, shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the Industry, including natural and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of margin of dumping actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments."

L.1 Views of the domestic industry

86. Post preliminary findings, the domestic industry has made the following submissions:

- (a) Imports from China PR increased in absolute terms as also in relation to production and consumption in India.
- (b) Imports of the product were undercutting the prices of the domestic industry in the market.
- (c) Whereas cost of production kept increasing over the injury period, even though the selling prices also increased, the increase in selling prices were significantly lower than increase in the cost of production. The imports were suppressing the prices of the domestic industry and preventing the price increases that would have otherwise occurred in the absence of dumped imports.
- (d) Demand for the product declined in 2006-07 and consequently production and sales of the domestic industry also declined. However, the decline in production and sales of the domestic industry was more than the decline in the demand. Resultantly, the domestic industry lost market share significantly upto 2006-07. Even though the domestic industry regained some market share in the POI, the same was much lower than the levels registered earlier. The domestic industry was faced with significant unutilized capacities in a situation where the demand for the product is quite significant in the market.
- (e) Profitability of the domestic industry declined continuously and so steeply that the domestic industry started suffering financial losses from 2006-07, which increased further during the POI.
- (f) Return on capital employed and cash profits followed the same trend as that of profits. Both return on capital employed and cash profits became negative during the POI. Growth of the domestic industry was negative in a number of parameters till 2006-07, which became positive thereafter in respect of volume parameters (even though the domestic industry could have gained higher

volumes in the absence of dumping). However, growth in price parameters continued to remain negative all along.

- (g) Imports were resulting in price undercutting in the market. Consequently, the volume of imports kept increasing even in a situation where the domestic industry was having unutilized capacities.
- (h) The price undercutting being caused to the domestic industry resulted in a situation where the domestic industry was unable to increase its selling prices in proportion to increase in the cost of production.
- (i) Price suppression caused by the dumped imports resulted in deterioration in profitability to such an extent that whereas the domestic industry was earning profits till 2005-06, it started suffering financial losses in 2006-07, which increased further during the POI.
- (j) Deterioration in profitability caused by the dumped imports led to deterioration in performance of the domestic industry in terms of return on capital employed, cash profits and consequently cash flow.

L.2 Views of the Producers/ Exporters

- 87. M/s Seth Associates representing M/s Liben Agro and Xintai have not offered any views on injury in the post preliminary finding stage.
- 88. M/s Dua Associates representing M/s Yangxin Chentian Chemical Industry Co. Ltd., Zhejiang Xinnong Chemical Co., Ltd And China Crop Protection Industry Association, made following submissions in the post preliminary finding stage:-
 - (a) Many of the indices in respect of the domestic industry show a positive trend and the Preliminary Findings themselves record that many of the aforesaid factors indicate improvement which itself leads to the conclusion that it is not alleged dumping which is the cause of any alleged injury to the Petitioner and/or its purported supporter Excel. Unfortunately these appear to have been ignored by the Hon'ble Authority.
 - (b) Authority has ignored improvements recorded in one parameter whilst assessing other parameters and has thus failed to make a cumulative assessment of various parameters relating to the domestic industry which alone can give a realistic picture as to any alleged injury. Further the Authority has chosen to disregard indices pointing against any alleged injury on account of imports from China PR and hence the injury assessment is incomplete and erroneous.
 - (c) Though the Authority has seen it fit to comment that the increase in Chinese imports was very significant during the POI, it has failed to consider that even more significant was the increase in the sales of the domestic industry.

- (d) The increase of imports from Xinnong and other Chinese Exporters is less than the growth of market demand.
- (e) The Authority here also erred in discounting the positive growth in the market share of the domestic industry during the POI and the decrease in the market share of imports from China PR and that the Chinese imports had only grown from 58.66% to 60.94% i.e. just over 2% from 2004-05 to 2007-08 (POI).
- (f) Authority has not explained the basis for its implicit conclusion that any increase in demand must correlate to an equivalent increase in domestic production or the domestic production is suffering some alleged injury. The said assumption presupposes that the domestic production is nearly the same as domestic demand.
- (g) The domestic industry cannot meet the domestic demand and imports are a necessity. The domestic industry has at no point of time been able to meet the demand in India.
- (h) A comparison of the Authority's own data concerning demand in the market and production of the domestic industry set out in the Preliminary Findings and noted above clearly indicates that the domestic industry has all along been incapable of meeting the domestic demand which has in all good monsoon years been far higher than the production of the industry. Further this also makes it amply clear that the same is not on account of exports from Chinese Exporters.
- (i) This makes it amply clear that imports are unavoidable for consumers in India and if duty is imposed on imports from China the clear beneficiary will be the only other production and export source i.e. the Petitioner's Denmark parent.
- (j) So the mere conclusion that because demand increased by 14% and production only by about 6% therefore the dumped imports prevented domestic industry from increasing its production is patently wrong.
- (k) Authority has also chosen to ignore that its own data showing tremendous increase in production of DTPC by the domestic industry during POI i.e. 53.70%.
- (l) Authority whilst commenting on the increase in the Chinese imports during POI, has failed to note that the imports from Denmark have increased by 84% during the POI. Further, the Authority has also ignored that given these facts, if anti dumping duty is imposed on imports from China, imports from Denmark will greatly benefit as then they will be the only source of imports which are necessary since domestic industry cannot meet domestic demand and thus by way of the present investigation a monopoly is sought to be created which will ultimately be detrimental to the consumers in India.
- (m) Domestic industry's decline in prices over the injury investigation period has

been just 0.2% and during the POI just 2.08% although in the same period Chinese import prices have gone up in fact 1.98% over injury investigation period and over 16% during the POI. Hence there is no price effect establishing any alleged injury either.

- (n) There is no material injury or any threat of material injury to the Domestic Industry by the imports of DTPC from China. The alleged injury is just a mere allegation, conjecture and remote possibility and the same are not substantiated by evidence.
- (o) It is reiterated that imports of DTPC are on account of the gap in the demand in India and the Indian domestic production. That imports are to bridge this gap. The increase of volume of imports is mainly on account of increase in demand of the subject goods which cannot be supplied by domestic production.
- (p) There is no Causal Link attributable to "Other Factors". Injury, if any, suffered by the Indian industry are on account of disadvantages suffered by it which are not suffered by Chinese exporters.
- (q) It has been admitted by the Domestic Industry that it has always been earning low levels of profit in the preceding years and that the losses in recent years have been due to "other factors" and not due to dumping of DTPC by the Chinese exporters.
- (r) Injury, if at all, suffered by the Petitioner is on account of loss of market share to its internal competitor.
- (s) The 6% decrease in production of the Petitioner has resulted in 6% increase in the production of the Supporter, Excel. Therefore, the decrease in production of the Petitioner is due to internal competition with the only producer in the Indian market and not due to imports or dumping from China PR as alleged.
- (t) There is a wide gap between domestic demand and domestic production and sales, thus necessitating imports of the subject goods from the subject countries, especially in view of the fact that the subject good is exported to India only from China and now Denmark.

L.3 Views of the Importers/Users

89. The importers/ users have not offered any views on injury in the post preliminary finding stage.

L.4 Post disclosure the following issues relating to injury analysis have been raised by the interested parties:-

90. - No examination of the sales negotiation process in the Indian market has been undertaken by the Designated Authority.

91. No analysis has been done by the Designated Authority to examine competition between Excel and Cheminova .
92. No examination has been done by the Designated Authority to seek at what price the captive sales were made by the domestic industry and whether any injury could be attributed to such captive sales or sales to related entities.

L.5 Examination by the Authority

93. The Authority has determined the injury to the domestic industry and causal link between the dumped imports and injury, taking into account all relevant facts in accordance with Rule 11 of Anti-Dumping Rules.
94. The Authority notes that the injury analysis has been appropriately carried out in number terms with regard to the injury parameters such as capacity, production, sales, stock, market share etc.
95. Having examined the degree and extent of dumping from China PR the Authority has examined the injury caused to the domestic industry, if any, and the causal link between the dumped imports and injury so suffered by the domestic industry. The Authority holds that the domestic industry constitutes a major proportion of Indian production of the subject goods during the period of investigation under Rule 2(b) of Anti-dumping Rules. Therefore, for the purpose of injury determination the applicant company and the supporter company have been held to constitute the domestic industry within the meaning of the Rules.
96. Rule 11 of Antidumping Rules read with Annexure-II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, “.... taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles....” In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree.
97. The Authority has taken note of arguments of interested parties on injury and causal link and addressed the relevant issues raised at appropriate places. The Authority has examined the injury parameters objectively taking into account the facts and the arguments of the interested parties.
98. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, stock, profitability, net sales

realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Rules supra.

99. Post disclosure the interested parties have stated that the Authority has not examined sales negotiation process in the domestic market and that M/s Cheminova has long term sales contracts with the consumer industries which involves an inbuilt pricing formula. The Authority observes that no such argument on this account was raised by the interested parties during the course of the proceedings. The Authority holds that no interested party should raise such highly factual arguments (consideration of which even requires spot verification) at the belated stage of disclosure statement. Nevertheless, the Authority examined this issue and directed the domestic industry to clarify the factual position along with the copies of the long term contracts and a statement of sales bifurcating the contractual sales and normal sales. From the information/document furnished by the domestic industry, the Authority observes that during POI M/s Cheminova has ***% of the total domestic sales through contracts at the weighted average rate of Rs.*** per Kg. and ***% domestic sales otherwise at the weighted average rate of Rs.*** per Kg. From the above analysis the Authority observes that there is no significant difference in the pricing structure between the two routes of domestic sales of M/s Cheminova during the POI. The Authority further observes that the weighted average price of M/s Excel, the other constituent of Domestic Industry, is less than the weighted average contractual price and the weighted average non-contractual price of M/s Cheminova during the POI. Moreover, the price undercutting, price underselling, price suppression and price depression examined by the Authority basing exclusively on M/s Excel's data is found to behaving in the same trend as the injury parameters when examined by taking the data of the domestic industry.

Price Undercutting

Particulars	Units	2004-05	2005-06	2006-07	POI
Price undercutting based on Excel	Rs./kg	***	***	***	***
Price undercutting based on DI	Rs./kg	***	***	***	***
Price undercutting based on Excel	%	10-20	15-25	15-25	5-12
Price undercutting based on DI	%	10-20	15-25	15-25	7-15

Price Underselling

Particulars	Units	Excel	DI
Landed Price	Rs./kg	85.40	85.40
Non-injurious price	Rs./kg	***	***
Price underselling	Rs./kg	***	***
Price underselling	%	30-40	35-45

Price suppression and depression

Particulars	Unit	2004-05	2005-06	2006-07	POI
Cost of Sales - Excel	Rs/ Kg	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	106.07	109.94	107.90
Cost of Sales - DI	Rs/ Kg	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	106.60	114.71	110.55
Selling Price - Excel	Rs/ Kg	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	99.06	89.57	85.06
Selling Price - DI	Rs/ Kg	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	101.22	94.67	88.85

100. In view of the arguments of the interested parties, the performance of the domestic industry was examined individually. It is seen that the price undercutting is positive and both the companies individually show price depression. Further, the profitability of both the units also show the same pattern. It is observed from the data available on record that profitability of both the domestic industry has deteriorated. Both the units were in profits in the base year and the profits steeply deteriorated and both suffered financial losses during 2006-07 and 2007-08. Return on investment of both the companies were also positive in the base year and steeply deteriorated to negative levels during the POI. Thus, the information on record does not show that the conclusions with regard to injury to the domestic industry would have been different for the reasons stated by the interested parties. On the contrary, if the selling price of M/s Cheminova is higher due to alleged sales on contract basis, it implies that the financial losses and return on investment of the company would have been more adverse than the levels found during the investigation period.
101. The interested parties have also disputed injury determination arguing that the performance of the domestic industry improved on account of sales, market share, decline in imports, production and capacity utilization. It is, however, found that they have primarily compared period of investigation with preceding year and have assumed that dumping commenced only in the period of investigation. Even when the Authority fixes a period of investigation for the purpose of determination of dumping margin, the same does not imply that the dumping occurs only during the period of investigation. The pattern of price and volumes in fact shows that dumping occurred over a longer period. In order to contain its volume injury, the domestic industry took a hit on profitability during the period of investigation which directly resulted in some increase in the volumes during the period of investigation, even when profitability and return on investment declined. However, the parameters during the period of investigation are still remained far adverse as compared to the first two years. The Authority is required to see overall situation prevailing during the injury period and then come to a conclusion.

102. They have also alleged that the price war in the Indian market could have been triggered by imports made by the related party of Excel. Such arguments are merely conjectures and unsubstantiated. The insignificant quantum of *** Mt of imports made by M/s Excel Crop Care Ltd., as is evident from the DGCI&S data, as against the total imports of 12361 Mt in to India during the POI can not cause any price war in the domestic market. When an interested party claims that some other factor could have contributed injury to the domestic industry, the onus to establish existence of such other factors and to quantify injury on account of the same rests on such interested parties themselves. While the Designated Authority is required to examine other known factors of injury and while the Authority can still consider such other known factors as are brought to the notice of the Authority, the same does not imply that the obligation to examine existence of other unlisted factors and quantify injury due to the same is onto the Authority without any supporting evidence and necessary information from the interested parties. In fact, the interested parties are required to demonstrate existence of such other factors and quantify injury caused to the domestic industry due to any such other factors.
103. Regarding the price of the captive sales of the domestic industry and its injury potential that can be attributed to such captive sales or sales to related entities, the Authority observes that M/s Excel has no captive sales. As far as M/s Cheminova is concerned, their captive sales is too insignificant (***Mt) compared to the total domestic sales (***Mt) and therefore cannot have any substantial impact on the injury.
104. The interested parties have also disputed injury determination arguing that the performance of the domestic industry improved on account of sales, market share, decline in imports, production and capacity utilization etc. It is, however, found that they have primarily compared period of investigation with preceding year and have assumed that dumping commenced only in the period of investigation which is far from the truth. The Authority is required to see overall situation prevailing during the injury period and then come to a conclusion.
105. The view that the price war in the Indian market could have been triggered by imports made by related party of M/s Excel sounds to be merely a conjecture and unsubstantiated. The volume of imports by such related party were so low as compared to the rest of the imports that the same could not have triggered any price war.

M. Volume Effects of Dumped Imports

a) Demand and market share

106. For the purpose of the present investigation, the Authority has defined demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of the

Indian Producers and imports from all sources. The demand so assessed is given in the table below.

Demand	Unit	2004-05	2005-06	2006-07	POI
Total Imports	MT	10,470	8,055	8,758	12,616
Sales – domestic industry	MT	7,378	6,154	4,622	7,669
Demand	MT	17,848	14,209	13,380	20,285
Trend	Indexed	100	79.61	74.97	113.66

107. It is seen from the table above that the demand for the product declined significantly between 2005-06 and 2006-07 and thereafter shown a significant increase during the POI.

b) Import volume and market share

108. The Authority has examined the volume of imports of the subject goods as provided by (a) the applicant domestic industry (which is based on secondary source of import data), (b) information procured by the Authority from the DGCI&S and (c) the responding producers/exporters. It is noted that the volume of imports reported in the DGCI&S data is not exhaustive, which appears to be due to the fact that the imports have been cleared in a number of customs classifications. This was further established by examination of the import data provided by the responding importers. Therefore, the Authority has relied upon the information received from the secondary sources (IBIS) as provided by the applicant. On the basis of various import data on record, the import volume from China PR are found to be above the de-minimis levels.

109. Imports volume from subject country and other countries has been as under:-

Imports in MT	Unit	2004-05	2005-06	2006-07	POI
China PR	MT	10,470	8,055	8,620	12,361
Other Countries	MT	-	-	138	255
Total Imports	MT	10,470	8,055	8,758	12,616

110. It is observed from the table above that Chinese imports declined in 2005-06, but increased thereafter. Increase was very significant during the period of investigation. It is also noted that imports from China PR account for very significant proportion of the total imports of the product under consideration in India.

c) Market share in demand

111. Considering imports from various sources and sales of the Indian Producers, market share of imports of the subject goods in demand in India was examined. Factual position is as follows:-

	Unit	2004-05	2005-06	2006-07	POI
Domestic industry	%	41.34	43.31	34.55	37.81
China PR	%	58.66	56.69	64.42	60.94
Other Countries	%	0.00	0.00	1.03	1.25

112. It is observed from the table above that the market share of dumped imports from China PR, in domestic demand, increased from 58.66% during base year to 60.94% during the POI, whereas the market share of domestic industry declined from 41.34% to 37.81% during the corresponding period. Even though the market share of the domestic industry increased and that of imports declined during the POI as compared with the preceding year, the market share of the domestic industry during the POI was lower than the levels achieved earlier.

d) Share of dumped imports in relation to domestic production

113. Authority observes that the dumped imports from subject country have increased in relation to the production of the domestic industry, as is evident from the following table:-

	Unit	2004-05	2005-06	2006-07	POI
Imports from China	MT	10,470	8,055	8,620	12,361
Production of the domestic industry	MT	9003	7938	6200	9335
Dumped Imports in relation to production of domestic industry.	%	116.29	101.47	139.03	132.42

e) Capacity & capacity utilization

114. Capacity and capacity utilization of the domestic industry over the injury period is given in the following table:-

	Unit	2004-05	2005-06	2006-07	POI
Capacity MT	MT	11,500	11,500	11,500	12,000
Capacity utilization %	%	78	69	54	78

115. It is observed from the table above that capacity utilization of the domestic industry declined upto 2006-07, but increased thereafter during the POI. Though, production of the domestic industry increased again during the POI, the same is still low considering that there is significant demand for the product in the Country.

f) Production

116. Production of the domestic industry is given in the following table:-

	Unit	2004-05	2005-06	2006-07	POI
Production MT	MT	9003	7938	6200	9335
Trend	Indexed	100	88.17	68.87	103.68
Demand	MT	17,848	14,209	13,380	20,285
Trend	Indexed	100	79.61	74.97	113.66
Production in relation to Demand	%	50.45	55.87	46.34	46.02

117. It is observed that production of the domestic industry declined upto 2006-07. However, decline in production was more than decline in the demand, which shows that dumped imports led to higher loss of market for the domestic industry in the past. During the POI, even when demand increased sharply, the dumped imports prevented the domestic industry to increase its production. Whereas demand increased by about 14%, production increased only by about 4%.

g) Sales volume

118. Sales volume of the domestic industry is given in the following table:

	Unit	2004-05	2005-06	2006-07	POI
Domestic sales	MT	7378	6154	4622	7670
Trend	Indexed	100	83.41	62.65	103.96
Demand	MT	17,848	14,209	13,380	20,285
Trend	Indexed	100	79.61	74.97	113.66
Market Share of domestic industry in Demand	%	41.34	43.31	34.55	37.81

119. It is observed from the table above that sales of the domestic industry declined sharply till 2006-07 and thereafter increased substantially. While the demand for the product also declined, the decline in sales was far more than decline in the demand. Resultantly, the domestic industry lost significant market share. Demand for the product increased significantly during the POI. However, inspite of the same, the domestic industry has not been able to increase its sales volumes to the extent of increase in demand. In fact, even market share of the domestic industry has not gone back to the levels of the base year. Therefore, dumped imports are impacting the sales of the domestic industry.

N. Price Effect of the Dumped imports on the Domestic Industry

a. **Price Undercutting**

120. With regard to the effect of the dumped imports on the prices, the Designated Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like products in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the purpose of this analysis, the weighted average cost of production (COP), weighted average Net Sales Realization (NSR) and the Non-Injurious Price (NIP) of the domestic industry have been compared with the landed cost of imports from the subject country.
121. The net sales realization was arrived at after deducting all rebates and taxes. Landed value of imports has been calculated by adding 1% handling charge and applicable basic customs duty to the CIF value of subject imports. The landed value of imports was compared with net sales realization of the domestic industry and it was found that the dumped imports are undercutting the prices of the domestic industry.

Price Undercutting based on Net sales realization of Domestic Industry:

Particulars	Units	2004-05	2005-06	2006-07	POI
CIF Import Price	Rs./kg	76.98	72.18	67.22	78.49
Landed price of imports	Rs./kg	93.61	84.06	76.64	85.40
Net Sales Realization	Rs./kg	***	***	***	***
Price undercutting	Rs./kg	***	***	***	***
Price undercutting %	%	10-20	15-25	15-25	7-15
Cost of sales	Rs./kg	***	***	***	***

122. Further, it is observed from the table below that the price undercutting is positive both when the calculation is done basing on the data of M/s Excel Industries Ltd exclusively and also when calculated on the basis of the data of a few individual cooperating importers. Therefore the post disclosure allegation of the interested parties that M/s Cheminova has long term sales contracts having inbuilt pricing formula and therefore the price undercutting calculated on the basis of cumulative price of both the constituents of the domestic industry is faulty, is not correct.

Price Undercutting based on data of M/s Excel Industries Ltd

Particulars	Units	2004-05	2005-06	2006-07	POI
CIF Import Price	Rs./kg	76.98	72.18	67.22	78.49
Landed price of imports	Rs./kg	93.61	84.06	76.64	85.40

Net Sales Realization	Rs./kg	***	***	***	***
Price undercutting	Rs./kg	***	***	***	***
Price undercutting %	%	10-20	15-25	15-25	5-12

Price Undercutting based on individual importers data for the POI

Particulars	Units	MEGHMANI	GHARDA	BHAGIRADHA
CIF Import Price	US\$/Kg	***	***	***
Landed price of imports	US\$/Kg	***	***	***
Purchase Price From DI	Rs/Kg	***	***	***
Purchase Price From DI	US\$/Kg	***	***	***
Price undercutting	US\$/Kg	***	***	***
Price undercutting	Rs/Kg	***	***	***
Price undercutting %	%	5-15	1-10	10-20

123. It is observed from the table above that imports are undercutting prices of the domestic industry. It is also noted that having lost significant market share during 2006-07, the domestic industry seem to have reduced the price difference between the imported product and domestic product in order to regain its market share. Resultantly, the market share of the domestic industry improved during the POI.

b) **Price Underselling**

124. Authority notes that the price underselling is an important indicator of assessment of injury. Non injurious price has been worked out and compared with the landed value of the subject goods to arrive at the extent of price underselling. The non-injurious price has been evaluated for the domestic producers by appropriately considering the cost of production for the product under consideration during the POI in accordance with the practice of the Authority as also taking in to account the decision of Hon'ble Supreme Court in the Reliance case. The analysis shows that the landed value of subject imports was significantly below the non-injurious price determined as follows:-

Particulars	Rs/Kg
CIF price	78.49
Landed Price	85.40
Non-injurious price	***
Price underselling	***
Price underselling Range (%)	35-45

c) Price suppression/depression

125. Price depression exists when the industry's prices are lower than the level of the previous period. Price suppression occurs when dumping prevents price increase that would otherwise take place due to increase in costs.

Particulars	Unit	2004-05	2005-06	2006-07	POI
Cost of Sales	Rs/ Kg	***	***	***	***
Trend	Index	100	106.60	114.71	110.55
Selling Price	Rs/ Kg	***	***	***	***
Trend	Index	100	101.22	94.67	88.85

126. From the above table, it is evident that price depression is there since the industry's price during the POI is lower than the price during the immediate preceding year. Further, price suppression is also there as the proportion of reduction in the cost of sales during the POI as compared to the immediate preceding year is 4% whereas during the same period the selling price has been reduced by 6%.
127. The above analysis shows that the dumped imports have adverse volume and price effect on the domestic industry in terms of increase in volume of dumped imports both in absolute and relative terms, and by suppressing and depressing the prices of the domestic market while eroding its market share.

d) Profit/Loss

128. The profitability of the domestic industry is given in the following table:-

	Unit	2004-05	2005-06	2006-07	POI
Profit before tax(PBT)	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100.00	46.57	-53.30	-105.53
Profit before interest & tax(PBIT)	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100.00	62.83	-28.33	-63.71
Profit Before interest(PBIT)	Rs./KG	***	***	***	***
Trend	Indexed	100.00	75.33	-45.21	-61.28
Profit before tax (PBT)	Rs./MT	***	***	***	***
Trend	Indexed	100.00	54.33	-79.92	-100.16

129. From the table above it is observed that profitability of the domestic industry declined significantly. Whereas the domestic industry was earlier earning profits (albeit low level of profits), it started suffering financial losses from 2006-07. While domestic industry conceded that its losses in 2006-07 were due to an additional factor of low level of production (due to decline in demand), if this factor is adjusted, it would be seen that the profitability declined more steeply during the POI.

O. Examination of other Injury Parameters

130. After having examined the effect of dumped imports on the volumes and prices of the domestic industry and major injury indicators like volume and value of imports, capacity, output, capacity utilization and sales of the domestic industry as well as demand pattern with market shares of various segments, other economic parameters which could indicate existence of injury to the domestic industry have been analyzed by the Authority as follows:-

a) Return on capital employed

131. Information regarding return on capital employed is given in the table below:-

	Unit	2004-05	2005-06	2006-07	POI
Return on Capital Employed - NFA basis	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	64.38	-40.04	-81.14

132. The Authority notes from the table above that return on capital employed of the domestic industry has deteriorated significantly over the injury period and the same became negative during 2006-07 and during the POI.

b) Cash Flow

133. Authority has examined the trends in cash profits in order to examine the impact of dumping on cash flow situation of the domestic industry. Information regarding cash profit of the domestic industry is given in the following table.

	Unit	2004-05	2005-06	2006-07	POI
Cash profits	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	65.57	1.43	-23.50

134. It is seen from the table above that the cash profits of the domestic industry steeply declined over the injury period. The decline was consistently occurring every year to such an extent that the domestic industry suffered cash losses during the POI.

c) Factors affecting domestic prices

135. Change in cost structure, competition in the domestic industry and prices of competing substitutes have been examined for analyzing the factors other than dumped imports that might be affecting the prices in the domestic market. The landed price of subject imports is below the selling price of the domestic industry. It could not be concluded that inter-se competition is to such an extent that the same led to decline in the prices by the domestic industry.

d) Inventories

136. Inventory holding of the domestic industry has declined as compared to the base year. However, the same has gone up during the POI as compared to the immediate preceding year as observed from the table below.

Particulars	Unit	2004-05	2005-06	2006-07	POI
Opening stock	Mt	458	502	403	369
Closing stock	Mt	502	403	369	421
Average stock	Mt	480	452	386	395

e) Productivity

137. Authority notes that the productivity of the domestic industry shows same trend as that of production. Productivity was declining till 2006-07, but increased during the POI.

	Unit	2004-05	2005-06	2006-07	POI
Productivity per employee	Mt	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	85.25	72.17	110.63
Productivity per day	Mt	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	88.17	68.87	103.68

f) Employment and Wages

138. Authority notes that employment with the domestic industry declined during the injury period except 2005-06, while wage paid shows increasing trend during the POI as compared to the immediate preceding year as well as the base year.

	Unit	2004-05	2005-06	2006-07	POI
Employment	No	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	103.43	95.43	93.71
Wages	Rs.Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	97.34	79.76	142.67

g) Growth

139. The Authority notes that growth of the domestic industry was negative in a number of parameters till 2006-07, which was partly due to decline in demand. Even though growth in volume parameters was positive during the POI, the same was still below the growth in demand. In any case, growth in price parameters continued to be negative all along.

h) Ability to raise capital investment

140. In the preliminary finding it was mentioned that no significant investment was made by the domestic industry. But, after verification of the domestic industry's data it was observed that the domestic industry has made investments to the tune of Rs.*** lakhs during the POI. However, continued dumping of the product would certainly have adverse impact on the ability of the domestic industry to raise capital investment.

P. Examination of other issues raised by the various interested parties

141. With regard to information concerning a number of parameters in the application, the Authority notes that the application filed contains separate information with regard to various injury parameters. In any case captive consumption by the applicant domestic industry is not very significant. Further, the application includes information on indexed basis with regard to inventories, profits, employment and capital investment for expansion.
142. The Authority notes that demand for the product has substantially increased during the investigation period as compared to previous year. In fact, in its application, the applicant alleged that there was a significant decline in demand during 2006-07 leading to decline in sales volumes.
143. It is, however, noted that imports have increased in absolute terms and in relation to production and consumption over the injury period. Even though market share of imports declined during the period of investigation as compared to preceding year, the same is still higher as compared to earlier years.
144. With regard to increase in prices during the period of investigation, the Authority notes that there has been significant change in the prices over the injury period. Even within the period of investigation, the prices moved significantly from a low of Rs *** per Kg. to as high as Rs.*** per Kg. The increase of ***% in overall import price does not imply that imports are not having any adverse price effect on the domestic industry.
145. With regard to production, sales and capacity utilization, the Authority notes that the unutilized capacity with the domestic industry is still substantial despite increasing demand in the country. Further, the volume achieved by the domestic

1722 GI/10-20

- industry has to be seen along with the price at which the goods have been sold. It is noted that the profitability of the domestic industry steeply deteriorated over the injury period.
146. While it is appreciated that demand for the product has increased, it is noted that the domestic industry could have produced and sold significantly higher volumes, by using unutilized capacities (22% during POI), in the absence of dumped imports. It is noted that the increase in imports between 2004-05 and POI was 2146 MT, whereas the unutilized capacity with the domestic industry in the POI was 2665 MT. In other words, had the dumped imports not increased over the period, the domestic industry could have utilized its full capacity. It could not therefore be accepted that the entire increase in imports was due to shortfall in the demand in the Country. In any case, the performance of the domestic industry deteriorated in terms of parameters such as profit/loss, return on investment and cash profits.
147. With regard to alleged unfair advantage to the domestic industry in production of Pesticides as a result of imposition of proposed anti dumping duties, the Authority is of the view that the purpose of anti dumping duties is to eliminate unfair pricing and to create a level playing field for the domestic industry vis-à-vis the dumped imports. Contrary to what has been argued by the interested parties, it can be said that access to unfairly priced import to other Pesticides manufacturers is giving undue advantage as compared to those manufacturers who are having their own captive production of DETPC.
148. Reduction in price undercutting in 2007-08 as compared to 2006-07 is because of significant increase in imports during 2006-07 when the demand increased and the domestic industry lost their market share. Domestic industry argued that as a result of this loss of market share during 2006-07, the domestic industry took corrective action in reducing the price gap between the domestic and imported product, results of which could be seen in the market share in the investigation period increasing in favour of domestic industry. However, it is evident that while the demand increased by 2438 MT over the injury period, sales of the domestic industry increased only by 292 MT, whereas the imports increased by 2146 MT. At the same time, the domestic industry had unutilized capacity of 2665 MT in investigation period. It is thus evident that practically entire increase in demand was taken away by the dumped imports in a situation where the domestic industry had unutilized capacities to the extent of increase in demand.
149. While arguing that the petitioner could have suffered losses or low profits due to "other factors", no such "other factors", other than those dealt with in this findings, have been brought to the notice of the Authority. The investigation so far has also not shown any other factor, which could have adversely impacted profitability of the domestic industry.

Q. Conclusion on Injury

150. On examination of various injury parameters, the Authority finds that imports from China PR increased in absolute terms as also in relation to production and consumption in India. Imports of the product were undercutting the prices of the domestic industry in the market. Further, whereas cost of production kept increasing over the injury period, even though the selling prices also increased, the increase in selling price was significantly lower than the increase in the cost of production. The imports were thus suppressing the prices of the domestic industry and preventing the price increase that would have otherwise occurred in the absence of dumped imports. With regard to consequent impact of the dumped imports on the domestic industry, it is found that demand for the product declined very significantly upto 2006-07 and consequently production and sales of the domestic industry declined upto 2006-07. However, the decline in production and sales of the domestic industry was more than the decline in demand. Resultantly, the domestic industry lost market share significantly upto 2006-07. Even though the domestic industry regained some market share during the POI, the same was much lower than the levels registered earlier.
151. The domestic industry was faced with significant unutilized capacities in a situation where the demand for the product is quite significant in the market. Profitability of the domestic industry declined continuously and so sharply that the domestic industry started suffering financial losses from 2006-07, which increased further during the POI. Return on capital employed and cash profits followed the same trend as that of profits. Both return on capital employed and cash profits became negative during the POI. Growth of the domestic industry was negative in a number of parameters till 2006-07, which became positive thereafter in respect of volume parameters (even though the domestic industry could have gained higher volumes in the absence of dumping). However, growth in price parameters continued to remain negative all along. It is thus concluded that the domestic industry has suffered material injury.

R. Causal Link and Other Factors

152. Having examined the existence of material injury and volume and price effects of dumped imports on the prices of the domestic industry, in terms of its price undercutting, price underselling and price suppression, and depression effects, other indicative parameters listed under the Indian Rules and Agreement on Anti-dumping have been examined to see whether these any other factor, other than the dumped imports could have contributed to injury to the domestic industry. Accordingly, the following parameters have been examined:-

(a) Volume and Prices of imports from third country

153. The Authority notes that there are negligible imports of the product under consideration from other countries. Imports from third countries could not have caused injury to the domestic industry.

(b) Trade restrictive practice and competition between the foreign and domestic producers

154. The Authority has not found any trade restrictive practice followed by the domestic industry and other Indian producers. The Authority notes that the subject goods are freely importable and there are no trade restrictive practices in the domestic market.

(c) Contraction of demand or Changes in the pattern of consumption

155. The Authority notes that demand for the product showed significant decline during 2005-06 and 2006-07. Consequently, sales volumes of the domestic industry and resultant production & capacity utilization of the domestic industry suffered upto this period. However, it is also noted that the decline in sales volumes of the domestic industry was more than the decline in demand for the product. During the POI, the demand registered significant increase once again. Even though the domestic industry was able to regain part of its market share, the same still remained significantly lower than the earlier years. Further, the profitability of the domestic industry continuously declined over the injury period. The Authority thus concludes that injury to the domestic industry was not due to contraction in demand.

(d) Development in Technology

156. There is no development in technology for production of the product. Possible development in technology therefore, is not a reason for any injury to the domestic industry.

(e) Export performance of Domestic Industry

Period	2004-05	2005-06	2006-07	POI
Volume in Mt	***	***	***	***
Indexed	100	96	96	122

157. Domestic industry does not have significant exports activities for the product concerned. However, export performance has declined during 2005-06 and 2006-07 and improved during POI as compared to base year. Therefore, any possible decline in export performance is not a cause of any injury. In any case, the Authority has considered only domestic operations in order to ascertain impact on price parameters.

(f) Productivity of the Domestic Industry

158. Productivity of the domestic industry declined upto 2006-07, but increase thereafter during the POI. However, regardless of changes in productivity levels, the profitability of the domestic industry showed continued decline.
159. The above non-attribution analysis shows that no other known factors, other than the dumped imports, appear to have affected the domestic industry.

S. Factors establishing causal link

160. Analysis of the performance of the domestic industry over the injury period shows that the performance of the domestic industry has materially deteriorated over the injury period. The causal link between dumped imports and the injury to the domestic industry is established on the following grounds:-
- a) Imports were resulting in price undercutting in the market. Consequently, the volume of imports kept increasing even in a situation where the domestic industry was having unutilized capacities.
 - b) The price undercutting being caused by the domestic industry resulted in a situation where the domestic industry was forced to reduce its selling prices more than the proportion in which the cost of production declined during the POI.
 - c) Price suppression caused by the dumped imports resulted in deterioration in profitability to such an extent that whereas the domestic industry was earning profits till 2005-06, it started suffering financial losses in 2006-07, which increased further during the POI.
 - d) Deterioration in profitability caused by the dumped imports led to deterioration in performance of the domestic industry in terms of return on capital employed, cash profits and consequently cash flow.
161. Therefore, the Authority concludes that the domestic industry has suffered material injury and the injury to the domestic industry has been caused by the volume and price effects of dumped imports from the subject country.

T. Magnitude of injury and injury margin

162. The Authority has determined non-injurious price for the domestic industry taking into cost of production of the domestic industry. This non-injurious price of the domestic industry has been compared with the weighted average landed value of the subject imports to determine injury margin. The injury margins have been worked out as follows:

	Unit	Yangxin Chentian	Lianyungang Liben	Xingtai Pesticides	Zhejiang Xinnong	Non- cooperative
Non-injurious	US\$/Kg	***	***	***	***	***

price						
Landed price of imports	US\$/Kg	***	***	***	***	***
Injury margin	US\$/Kg	***	***	***	***	***
Injury margin	Range %	50-60	30-40	15-25	30-40	85-95

U. Conclusion:

163. After examining the issues raised and submissions made by the interested parties and facts made available before the Authority as recorded in this finding, the Authority concludes that:

(a) The product under consideration has been exported to India from China PR below its normal value, thus resulting in dumping of the product.

(b) The domestic industry has suffered material injury due to dumping of the product under consideration.

(c) The material injury has been caused by the dumped imports from China PR.

V. Indian industry's interest & other issues

V.1 Issues raised by the interested parties

164. The following issues were raised by the interested parties:-

a) There is a wide gap between domestic demand and domestic production and sales thus necessitating imports of the subject goods from the subject country, especially in view of the fact that the subject good is exported to India only from China PR and now Denmark.

b) The cost of commonly used and popular pesticide products such as Chlorpyrifos, Quinalphos, Propenofos, Triazophos and Anilophos, for most common crops will go up by at least 15 to 20% on account of the imposition of the high anti-dumping duty recommended by the Authority in the Preliminary Findings thus impacting the interest of the farmers.

c) In the event the anti-dumping duty are imposed by the Authority on the imports of DTPC from China PR, Indian Exporters will have to increase their prices by at least 5% to 7% and will therefore lose a competitive edge over the other exporters around the world. This will further worsen the declining export

performance of India as a country.

d) Several Indian companies manufacture the products namely, Chlorpyrifos, Quinalphos, Propenofos, Triazophos and Anilophos in which DTPC is used as the main raw material. In order to protect the interest of the Petitioner, it is not prudent to penalize 20 or more manufacturers who use the product.

e) Both Indian producers put together are unable to meet the domestic demand. Imposition of anti dumping duty in such situation is counterproductive and will cause scarcity of DTPC in the domestic market.

V.2 Examination by the Authority

165. The Authority notes that the purpose of anti-dumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the Country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject country in any way, and, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers. The imposition of anti-dumping duties does not intend to create market scarcity in the domestic market by preventing imports. In fact the subject goods are freely importable and even in the event of imposition of anti-dumping duties against imports of the subject goods originating in or exported from the subject country, the subject goods would continue to be imported freely. The fundamental principle of anti-dumping duty is to prevent dumping and to ensure fair trading practice and to create a level playing field for the domestic producers vis-a-vis foreign producers/exporters resorting to dumping.
166. It is recognized that the imposition of anti-dumping duties might affect the price levels of the products manufactured using the subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of these products. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the antidumping measures, particularly if the levy of the anti-dumping duty is restricted to an amount necessary to redress the injury to the domestic industry. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices, would prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject country in any way, and therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.

W. Recommendation

167. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all the known interested parties and adequate opportunity was given to the exporters,

importers and other interested parties to provide information on the aspects of dumping, injury and causal link. Having initiated and completed the investigation into dumping, injury and causal link in terms of the Anti-dumping Rules laid down and having established positive dumping margin as well as material injury to the domestic industry caused by such dumped imports from the subject country, the Authority is of the view that imposition of anti-dumping measures is required to offset dumping and injury. Therefore, the Authority considers it necessary and recommends imposition of definitive anti-dumping duties on imports of the subject goods from the subject country in the form and manner described hereunder.

168. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, antidumping duty equal to the amount mentioned in Col 8 of the table below is recommended to be imposed from the date of imposition of the provisional duty notified by the Central Government, in the event of acceptance of these recommendations by the Central Government, on all imports of subject goods originating in or exported from the China PR:-

SN	Heading/ subheading	Description of goods.	Country of origin	Country of export	Producer	Exporter	Duty amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	29.30	Diethyl Thio Phosphoryl Chloride (DETPC)	China PR	China PR	Yangxin Chentian Chemical Industry Co., Ltd.	Yangxin Chentian Chemical Industry Co., Ltd.	1.024	Per Kg	US\$
2	29.30	Diethyl Thio Phosphoryl Chloride (DETPC)	China PR	China PR	Lianyungang Liben Agro- chemical Co., Ltd.	Lianyungang Liben Agro- chemical Co., Ltd.	0.754	Per Kg	US\$
3	29.30	Diethyl Thio Phosphoryl Chloride (DETPC)	China PR	China PR	Xingtai Pesticides Co., Ltd.	Xingtai Pesticides Co., Ltd.	0.516	Per Kg	US\$
4	29.30	Diethyl Thio Phosphoryl Chloride (DETPC)	China PR	China PR	Zhejiang Xinnong Chemical Co., Ltd.	Zhejiang Xinnong Chemical Co., Ltd.	0.798	Per Kg	US\$
5	29.30	Diethyl Thio Phosphoryl Chloride (DETPC)	China PR	China PR	Any combination of producer and exporter other than the above		1.157	Per Kg	US\$
6	29.30	Diethyl Thio Phosphoryl Chloride (DETPC)	China PR	Any country other than China PR	Any	Any	1.157	Per Kg	US\$
7	29.30	Diethyl Thio Phosphoryl Chloride (DETPC)	Any country other than China PR	China PR	Any	Any	1.157	Per Kg	US\$

169. Subject to the above, the Authority confirms the preliminary findings dated 25th May, 2009.
170. An appeal against the findings after its acceptance by the Central Government shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and Customs Tariff Rules, 1995.

P. K. CHAUDHERY, Designated Authority